

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

कमजोर आत्मविश्वास और बढ़ते संरक्षणवाद के बीच 2024 की चौथी तिमाही के दौरान वैश्विक आर्थिक गतिविधि आघात-सहनीय रही। भारत में, 2024-25 की दूसरी तिमाही में देखी गई गति में कमी अब नहीं रही क्योंकि निजी खपत तीसरी तिमाही में वास्तविक गतिविधि को रोशन करने वाले त्योहारी व्यय के साथ घरेलू मांग का वाहक बनने के लिए तैयार है। घरेलू वित्तीय बाजारों में अमेरिकी डॉलर के लगातार बढ़ने और लगातार पोर्टफोलियो बहिर्वाह से इक्विटी के दबाव में आने से सुधार देखा जा रहा है। मध्यम-अवधि का परिदृश्य तेज बना हुआ है क्योंकि समष्टि-विवेकपूर्ण की ताकत खुद को फिर से स्थापित करती है। हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अक्टूबर 2024 में ऊपरी सहनशीलता बैंड से ऊपर पहुंच गई, जिसमें कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ-साथ खाद्य कीमतों की गति में तेज उछाल आया।

भूमिका

जैसा कि दुनिया के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर अक्टूबर 2024 के अंत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक के लिए वाशिंगटन डीसी में एकत्रित हुए, धीमी मुद्रास्फीति करना और चक्रीय असंतुलन में सहजता वैश्विक अर्थव्यवस्था की सॉफ्ट लैंडिंग का रास्ता साफ कर रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फिलिप्स वक्र के तीव्र होने से उत्पादन के आश्चर्यजनक रूप से मजबूत प्रदर्शन को सक्षम करते हुए मुद्रास्फीति में उम्मीद से अधिक तेजी से गिरावट आई है।

हाल के उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि 2024 की चौथी तिमाही के दौरान अब तक मोटे तौर पर अपरिवर्तित परिदृश्य के साथ थोड़ी कम हुई है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में विनिर्माण गतिविधि के क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में गिरावट आई, जबकि सेवाओं में मजबूती

* यह आलेख माइकल देवव्रत पात्र, जी. वी. नथनएल, शाहबाज खान, बिस्वजीत मोहंती, बजरंगी लाल गुप्ता, रमेश कुमार गुप्ता, हरेंद्र बेहरा, के एम नीलिमा, रिज़न यांगडोल, ऋषभ कुमार, राशिका अरोड़ा, मधुरेश कुमार, एडम अभिग्नू यादव, हर्षिता यादव, शैलजा भाटिया, शिवम, अंजली मारिया जोस, सुक्ति खांडेकर, सुभ्रदीप पॉल, श्रेया गुप्ता, अभिनंदन बोरड, सुनील कुमार, धीरेंद्र गजभिये, खुशी सिन्हा, युवराज कश्यप, सोनल यादव, कार्तिकेय भार्गव, अक्षरा अवरुथी, आशीष थॉमस जॉर्ज, समीर रंजन बेहरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव और रेखा मिश्र द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

बनी रही। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, पीएमआई मिश्रित संकेत दे रहे हैं। एशिया के लिए, निर्यात में तकनीक-संचालित वृद्धि के साथ, वृद्धि को अपेक्षाओं के सापेक्ष मजबूती मिली है। इस मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, आईएमएफ का आकलन है कि एशियाई दृष्टिकोण के लिए जोखिम बढ़ गया है, मुख्य रूप से कमजोर बाहरी वातावरण और प्रतिकूल जनसांख्यिकी के कारण। मुद्रास्फीति में गिरावट जारी है और कई क्षेत्रों में 2025 तक लक्ष्य तक पहुंचने का अनुमान है। एशिया में ईएमई में हेडलाइन मुद्रास्फीति मोटे तौर पर स्थिर रही है या पीछे हट रही है, लेकिन लैटिन अमेरिका में यह लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है क्योंकि सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी उनके महामारी-पूर्व औसत से लगातार मजबूत रही है।

फिर भी, बढ़ते ऋण स्तर - सार्वजनिक ऋण इस वर्ष 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा संचालित है - परिदृश्य को धूमिल कर रहे हैं। आईएमएफ को उम्मीद है कि भविष्य में ऋण का स्तर वर्तमान अनुमान से अधिक हो सकता है। इसके विचार में, हाल के दशकों में राजकोषीय मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा तेजी से उच्च सरकारी व्यय की ओर झुक गई है। राजकोषीय नीति में अनिश्चितता बढ़ गई है, और कराधान पर राजनीतिक सीमाएँ अधिक मजबूत हो गई हैं। हरित परिवर्तन, जनसंख्या की उम्र बढ़ने, सुरक्षा चिंताओं और लंबे समय से चली आ रही विकास चुनौतियों से निपटने के लिए व्यय का दबाव बढ़ रहा है। ऋणग्रस्तता के टिक-टिक टाइम बम के साथ-साथ, संभावित प्रभाव-विस्तार और बढ़ते युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था की दोष रेखाओं को बदल रहे हैं।

परिणामस्वरूप, परिदृश्य को लेकर अनिश्चितता का स्तर बढ़ गया है। व्यापार और राजकोषीय नीतियों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव की संभावना को लेकर चिंताएँ बहुत अधिक हैं। वित्तीय बाजार में अस्थिरता की वापसी ने छिपी हुई कमजोरियों और कुछ उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए राष्ट्रिक उधार के प्रसार के बारे में पुरानी आशंकाओं को जन्म दिया है। जैसा कि खंड II में चर्चा की गई है, वैश्विक वृद्धि की स्थिर होने की उम्मीद है, लेकिन इसकी आघात-सहनीयता के बावजूद यह बराबर से नीचे है, अभी भी उच्च उधार लागत के कारण निजी ऋण और निवेश में बाधा आ रही है। यदि राजकोषीय समेकन शुरू किया जाता है, तो शुरुआती वर्षों में वृद्धि धीमी होने की संभावना है, लेकिन दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

हालाँकि विश्व व्यापार अब तक स्थिर बना हुआ है और माल बाजारों में स्थिरता लॉजिस्टिक्स डील को पुनर्जीवित कर रही है, एक अधिक खंडित वैश्विक व्यापार परिदृश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की आघात-सहनीयता को कम कर सकता है जो अब तक भूराजनीतिक तनावों के कारण कायम है। इसके अलावा, जैसे-जैसे संरक्षणवाद बढ़ता है, पूंजी का प्रवाह बाधित होता है। तदनुसार, कमजोर वैश्विक वृद्धि परिदृश्य मध्यम अवधि तक फैला हुआ है, जिससे पता चलता है कि संभावित उत्पादन स्थायी रूप से प्रभावित हुआ है। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अधिक स्थायी निशान दिखा रही हैं। “वैश्विक अर्थव्यवस्था को कम वृद्धि, उच्च ऋण पथ पर फंसने का खतरा है। इसका मतलब है कम आय और कम नौकरियाँ।”¹

निकट अवधि की वित्तीय स्थिरता के जोखिम नियंत्रित हैं और वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल हैं। मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के कारण दीर्घकालिक सरकारी प्रतिफल में वृद्धि हुई और अमेरिकी डॉलर सितंबर में अपने हालिया निचले स्तर से मजबूत हुआ। अमेरिकी चुनाव से पहले की अस्थिरता को छोड़कर इक्विटी बाजारों में उछाल के साथ-साथ, क्रेडिट बाजार की स्थितियाँ सौम्य बनी हुई हैं, और स्प्रेड पूर्व-महामारी के औसत के मुकाबले बहुत कम हो गया है। हालाँकि, आय के प्रदर्शन की तुलना में मूल्य-निर्धारण बढ़ा हुआ है और विशेष रूप से गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों के बीच लीवरेज का उपयोग अनिश्चितता के साथ अस्थिरता की बढ़ती संभावना के साथ बढ़ गया है।

जैसे ही अमेरिकी चुनाव का परिणाम स्पष्ट हो गया, दुनिया भर के प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी आई, अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में उछाल आया, और अमेरिकी डॉलर ने 2020 के बाद से अपनी सबसे बड़ी एक दिवसीय छलांग लगाई, जो व्यापार के बाद के दिनों में और भी अधिक हो गई। टैरिफ प्रस्तावों और संभावित प्रतिशोध के परिदृश्य में भयंकर व्यापार युद्धों की आशंका है - आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक में चेतावनी दी है कि उच्च टैरिफ 2025 में 0.8 प्रतिशत और 2026 में 1.3 प्रतिशत आउटपुट को मिटा सकता है। अमेरिकी डॉलर में उछाल के सामने, एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक उभरते बाजारों की मुद्राएं कमजोर होकर नए निचले स्तर पर पहुंच गईं और उन्होंने अमेरिकी चुनाव परिणामों के बाद चीन से प्रोत्साहन के एक नए दौर की तैयारी की, लेकिन घोषणाएं निराशाजनक रहीं

और इसलिए अधिक की उम्मीद की जा रही है। हाल ही में रिकॉर्ड स्तर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, जिसमें अमेरिकी खजाने में चुनाव पूर्व बिकवाली भी शामिल है, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी के दबाव में स्वर्ण की कीमतें गिर गईं, जबकि तांबे की कीमतों से चीनी युआन में भारी गिरावट आई। बिटकॉइन में रिकॉर्ड-तोड़ रैली ने भविष्य में व्युत्पन्नी में आसन्न जोखिम के नियमित आवर्तन का संकेत दिया। क्या ट्रंप के व्यापार का उत्साह बरकरार रहेगा जिसने व्यापारियों को ब्याज दरों के रास्ते पर अपनी अपेक्षाओं को फिर से खींचने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है? वर्ष की फेड की दूसरी ब्याज दर में कटौती का मुख्य कारण इक्विटी और अमेरिकी डॉलर में थोड़ी कमी और बॉण्ड में वृद्धि थी। स्वैप बाजारों से संकेत मिलता है कि वर्ष के शेष भाग में फेड द्वारा दरों को अपरिवर्तित रखने की एक महत्वपूर्ण संभावना है, विशेष रूप से अक्टूबर से अमेरिकी मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इन सभी घटनाओं से पहले, ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन में नियोजित वृद्धि को एक महीने के लिए पीछे धकेलने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, जो कमजोर वैश्विक मांग पर व्यापक चिंताओं के बीच सावधानी का संकेत देता है, भले ही भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम हाल में कम हो गया हो। कुल मिलाकर, एक कमजोर आत्मविश्वास और संरक्षणवाद की ओर संभावित झुकाव पूर्ण वैश्विक सुधार में बाधा डालता है।

भारत में, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में देखी गई गति में कमी पीछे रह गई है। निजी निवेश कमजोर है, जैसा कि कॉरपोरेट आय में कमी के कारण जुलाई-सितंबर 2024 के दौरान अचल और गैर-चालू आस्तियों में क्रमिक रूप से कम निवेश में परिलक्षित होता है। फिर भी कर्मचारियों की लागत में वृद्धि में कमी और गैर-परिचालन आय में वृद्धि ने समाप्त होने के कगार पर तेल और गैस क्षेत्र और उच्च प्रदर्शन वाले वित्तीय सेवा क्षेत्र को छोड़कर भी निवल लाभ को बढ़ावा दिया। निजी उपभोग हालांकि मिश्रित स्थिति के साथ फिर से घरेलू मांग का वाहक बन गया है। त्योहारी खर्च ने तीसरी तिमाही में वास्तविक गतिविधि को बढ़ा दिया है, जैसा कि खंड III में बताया गया है जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तात्कालिक पूर्वानुमान के लिए उच्च आवृत्ति संकेतकों को ट्रैक करता है। मॉल में लोगों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन नई पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ई-कॉमर्स कई तरह की मार्केटिंग रणनीतियों और ब्रांड रिकॉल पहलों के साथ बढ़ रहा

¹ वैश्विक नीति एजेंडा अक्टूबर 2024 प्रेस ब्रीफिंग आईएमएफ, 24 अक्टूबर 2024।

है। एफएमसीजी और ऑटो कंपनियां मांग को पुनर्जीवित करने के लिए विज्ञापन खर्च बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही, इस त्योहारी सीजन में ग्रामीण भारत ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सोने की खान बनकर उभर रहा है; उम्मीद है कि खरीफ़ उत्पादन में तेज़ वृद्धि और रबी उत्पादन को लेकर आशावाद के कारण वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड खाद्यान्न लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (डी2सी) ब्रांड अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और क्विक-कॉमर्स (क्यू-कॉम) प्लेटफॉर्मों-एक इको-सिस्टम जिसका मूल्य 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और वर्ष 2029-30 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, इसके माध्यम से बिक्री बढ़ाने के लिए धन की तलाश कर रहे हैं।² खुदरा विक्रेता दूसरी तिमाही के सापेक्ष बिक्री वृद्धि में तेजी रिपोर्ट कर रहे हैं। इस दिवाली ई-दोपहिया वाहनों की धूम रही, हालांकि इसमें एक अलग प्रीमियमीकरण देखने को मिला है, जो कि लक्जरी कार सेगमेंट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देश भर में नए शहर बढ़ रहे हैं और शहरी आबादी चार गुना बढ़ जाएगी - 2025 तक, भारत की आधी आबादी की शहरों में रहने की उम्मीद है, जिससे शहरी मांग बढ़ेगी। बस जरूरत इस बात की है कि मुद्रास्फीति को कम किया जाए ताकि भारत अपनी क्षमता के साथ फिर से जुड़ सके।³

सितंबर में बढ़ोतरी की चेतावनी के बाद अक्टूबर सीपीआई मुद्रास्फीति की रीडिंग एक बड़ा आघात साबित हुई, जिससे जुलाई और अगस्त के लिए उप-लक्ष्य परिणामों पर आरबीआई की चेतावनियों को बल मिला। चिंता की बात यह है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज उछाल के अलावा, कोर मुद्रास्फीति भी बढ़ी है। दूसरे क्रम के प्रभाव या उच्च प्राथमिक खाद्य कीमतों के प्रभाव-विस्तार के शुरुआती संकेत हैं - खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि के बाद, प्रसंस्कृत खाद्य कीमतों के संबंध में मुद्रास्फीति में तेजी देखी जाने लगी है। घरेलू नौकरों/रसोइयों जैसी घरेलू सेवाओं की कीमतों में वृद्धि भी भोजन की ऊंची कीमतों के कारण जीवनयापन के उच्च दबाव को दर्शाती है, जो इन विशिष्ट मजदूरी तक पहुंचने लगी है।⁴ इस माहौल में, वस्तुओं और सेवाओं में इनपुट लागत के बढ़ने और बिक्री कीमतों में उनके प्रवाह को ध्यान से देखने की

जरूरत है, जैसा कि खंड III में विश्लेषण किया गया है। मुद्रास्फीति पहले से ही शहरी उपभोग मांग और कॉरपोरेट्स की कमाई और पूंजीगत व्यय को प्रभावित कर रही है। यदि इसे अनियंत्रित रूप से चलने दिया गया, तो यह वास्तविक अर्थव्यवस्था, विशेषकर उद्योग और निर्यात की संभावनाओं को कमजोर कर सकता है।

जैसा कि खंड III में विस्तार से बताया गया है, भारत के निर्यात का दृष्टिकोण उज्ज्वल है। पिछले कुछ महीनों की धीमी वृद्धि प्रोफ़ाइल के तहत, भारत प्रमुख विनिर्माण वस्तुओं के वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी हासिल कर रहा है। वास्तव में, भारत वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 13 प्रतिशत या छठा हिस्सा रखता है, जो बढ़ती रिफ़ाइनिंग क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने की क्षमता का प्रमाण है। यह बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों का सबसे बड़ा निर्यातक, कीटनाशकों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक, रबर वायवीय टायरों में आठवां सबसे बड़ा और अर्धचालकों में नौवां सबसे बड़ा निर्यातक है।

2024-25 की पहली छमाही में, एप्पल ने लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत निर्मित आईफोन का निर्यात किया, जबकि ऑटोमोबाइल निर्यात में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों के कारण रहा। कई वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। समग्र निर्यात को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में प्रीमियम मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों की संख्या का विस्तार करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पहले से ही, 1100 से अधिक जीआई उत्पाद एक-जिला-एक-उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत पंजीकृत हैं, जिनमें से वैश्विक कुल लगभग 70,000 जीआई उत्पादों में से 640 का निर्यात किया जाता है।⁵

उत्पत्ति के नियमों और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत करने के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। अनेक द्विपक्षीय समझौते भारत को वैश्विक विनिर्माण में 'चाइना प्लस वन' प्रवृत्ति का लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे। बाजार पहुंच में सुधार करना महत्वपूर्ण है - पिछले पांच वर्षों में, यह अनुमान लगाया गया है कि एफटीए भागीदारों (आसियान, संयुक्त अरब अमीरात, साफ्टा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मॉरीशस)

² बिजनेस स्टैंडर्ड, "डी2सी ब्रांड क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के लिए धन जुटाते हैं", 23 अक्टूबर 2024।

³ आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2024।

⁴ सीपीआई (2012=100) ऑल इंडिया आइटम इंडेक्स, <https://cpi.mospi.gov.in>

⁵ "चीन पर नज़र रखते हुए, भारत जीआई लिस्टिंग का विस्तार करेगा", मिंट, 20 अक्टूबर 2024।

से भारत का कुल आयात 37.9 प्रतिशत बढ़ा है जबकि निर्यात केवल 14.5 प्रतिशत बढ़ा है।⁶

भारत समुद्री व्यापार के लिए अपने लॉजिस्टिक्स में एक शांत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो मात्रा के हिसाब से भारत के व्यापार का 95 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 65 प्रतिशत है। पिछले दस वर्षों में बंदरगाह क्षमता 745 मिलियन टन से दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 1,600 मिलियन टन से अधिक हो गई है। प्रमुख बंदरगाहों पर यातायात लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गया है। टर्नअराउंड समय 2010 में 127 घंटे से गिरकर हाल ही में 53 घंटे हो गया है, न्हावा शेवा में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) में केवल 21 घंटे है। इस अवधि में, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 54वें से बढ़कर 38वां हो गया है। भारत निकोबार द्वीप समूह में गेलाथिया खाड़ी में एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब की योजना बना रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक पर स्थित है। वधावन में एक नए बड़े बंदरगाह की भी योजना बनाई गई है।⁷ चौगुनी बंदरगाह क्षमता के साथ-साथ, भारत को एक अग्रणी जहाज निर्माता बनने, भीतरी इलाकों के साथ विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी विकसित करने और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने का लक्ष्य रखना होगा ताकि आयात और निर्यात का काम वहाँ कम हो। लाल सागर संकट के बीच उछाल का लाभ उठाने के लिए एयर कार्गो में भी वृद्धि जरूरी है।

घरेलू वित्तीय बाजारों में सुधार देखा जा रहा है। अमेरिकी डॉलर की लगातार सख्ती ने अन्य सभी मुद्राओं पर नीचे की ओर दबाव डाला है, साथ ही भारतीय रुपये में भी राजनीतिक और भू-राजनीतिक दोनों कारणों से गिरावट देखी जा रही है, लेकिन वैश्विक अशांति कम होने और व्यापक-बुनियादी सिद्धांतों की अंदरूनी ताकत फिर से मजबूत होने के कारण मध्यम अवधि का दृष्टिकोण तेज बना हुआ है। हाल की अवधि में, भारतीय रुपये की विनिमय दर पर कुछ चर्चा हुई है, विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से और समकक्षों के संबंध में इसकी सापेक्ष स्थिरता पर कुछ असंतोष है। जैसा कि बॉक्स 2 में बताया गया है, भारतीय रुपये का स्तर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो अंतिम विश्लेषण में, भारतीय अर्थव्यवस्था के

अंतर्निहित व्यापक-बुनियादी सिद्धांतों की स्थिति को दर्शाता है। विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप से अनुचित अस्थिरता को सुचारु किया जाता है ताकि बाजार व्यवस्थित तरीके से साफ हो सके। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब भू-राजनीतिक तनाव, अलग-अलग मौद्रिक नीति मार्ग, भू-आर्थिक विखंडन और राजनीतिक फैलाव और अन्य अतिव्यापी संकटों के बीच वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता अभूतपूर्व रूप से अधिक है। दुनिया भर में मुद्रा बाजार घरेलू आर्थिक गतिविधियों में इन वैश्विक आघातों के प्रसार के माध्यम बन गए हैं। भारतीय रुपये में स्थिरता प्रदान करके, अर्थव्यवस्था कई वैश्विक प्रभाव-विस्तार और सहायक वित्तीय स्थिरता जोखिमों से अपेक्षाकृत अछूती रहती है। बॉक्स 2 में यह भी बताया गया है कि कैसे अर्थव्यवस्था को बफर करने के इस दृष्टिकोण ने भारत के बुनियादी सिद्धांतों की जन्मजात ताकत को एक शत्रुतापूर्ण और अत्यधिक अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय वातावरण में निर्मित करने में सक्षम बनाया है।

क्रेडिट बाजार में, व्यक्ति-वित्तीय संस्थानों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने ऋण पर अत्यधिक ब्याज दरों के कारण विनियामकों का ध्यान आकर्षित किया। बताया गया है कि कई निजी बैंक छोटे टिकट अग्रिमों, क्रेडिट कार्ड और व्यक्ति ऋणों में दबाव का सामना कर रहे हैं, साथ ही अति-लाभ वाले ग्राहकों के साथ-साथ प्रावधान में भी वृद्धि हुई है। आम तौर पर, बैंकों ने खुदरा और सेवाओं को ऋण देने में सावधानी बरती है। दूसरी ओर, उन्होंने उद्योग - छोटे, मध्यम और बड़े - को ऋण में मजबूती से वृद्धि की है, जो भारतीय उद्योग की अंतर्निहित विकास गति में उछाल को दर्शाता है। कुल मिलाकर, जमा और ऋण वृद्धि के बीच एक बेहतर संतुलन उभर रहा है, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात पहले समतापमंडलीय ऊंचाइयों से सामान्य स्तर पर गिर रहा है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निरंतर बिकवाली के बावजूद, इक्विटी बाजार घरेलू समर्थन पर एक नई बढ़त के लिए तैयार हो रहे हैं, खासकर प्रमुख म्यूचुअल फंड इक्विटी योजनाओं के लिए। मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के कारण कुछ सुधारों के बावजूद, 2024 में भारतीय मिड-कैप और स्मॉल-कैप सूचकांकों में अब तक बढ़त सबसे अच्छी है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से बेपरवाह, कुछ बड़े टिकट सौदों में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी द्वारा फंडिंग बढ़ रही है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, यह अक्टूबर और नवंबर की पहली छमाही भारत में सबसे गर्म रिकॉर्ड के रूप में दर्ज

⁶ भारत की पण्य वस्तु व्यापार रिपोर्ट की पंचवर्षीय समीक्षा, वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल, मई 2024।

⁷ "भारत ने चुपचाप अपने बंदरगाहों को बदल दिया", द इकोनॉमिस्ट, 09 मई 2024।

की गई। ला नीना की संभावना और समुद्र की सतह के तापमान में समय-समय पर होने वाली ठंडक को अब दिसंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया है, जो ठंडी सर्दी का संकेत देता है। फिर भी, जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में प्रयास दिखाई दे रहे हैं। पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना द्वारा समर्थित, 2027 तक 30 गीगा वाट जोड़ने के लक्ष्य के साथ, छत पर सौर क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत को विकास के स्वच्छ और अधिक टिकाऊ मार्ग की दिशा में की गई प्रगति की मान्यता में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। चुनौतियों के बावजूद, भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में इस वर्ष 4.5-5.0 गीगा वाट जुड़ने की उम्मीद है, 2026 में संभावित वार्षिक स्थापना 10 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी। स्थापित पवन क्षमता का 70-80 प्रतिशत स्थानीयकृत है। डिस्कॉम द्वारा दीर्घकालिक बिजली खरीद अनुबंधों ने नवीकरणीय ऊर्जा में निजी डेवलपर्स के निवेश को जोखिम से मुक्त कर दिया है। भंडारण में निवेश करना समय की मांग है।

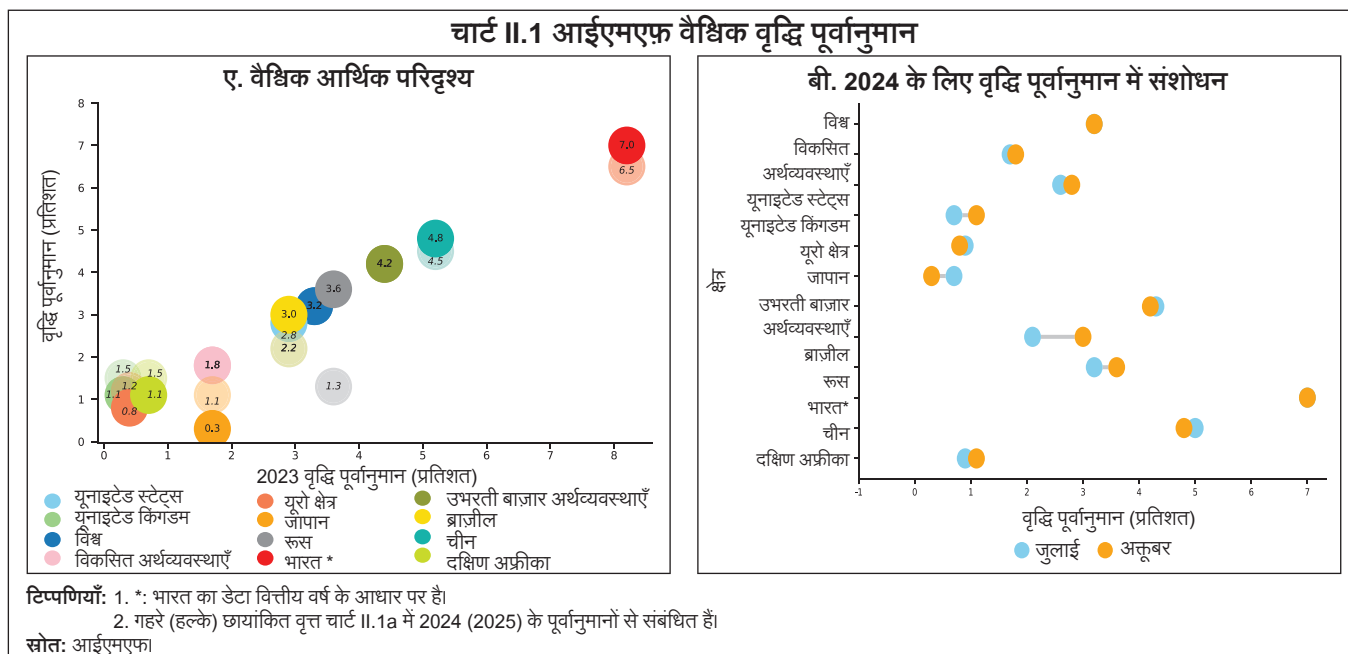
इस पृष्ठभूमि में, आलेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रही गतिविधियों को शामिल करता है। घरेलू समष्टिआर्थिक स्थितियों का आकलन खंड III में दिया गया है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, जबकि अंतिम खंड निष्कर्ष टिप्पणियाँ निर्धारित करता है।

II. वैश्विक व्यवस्था

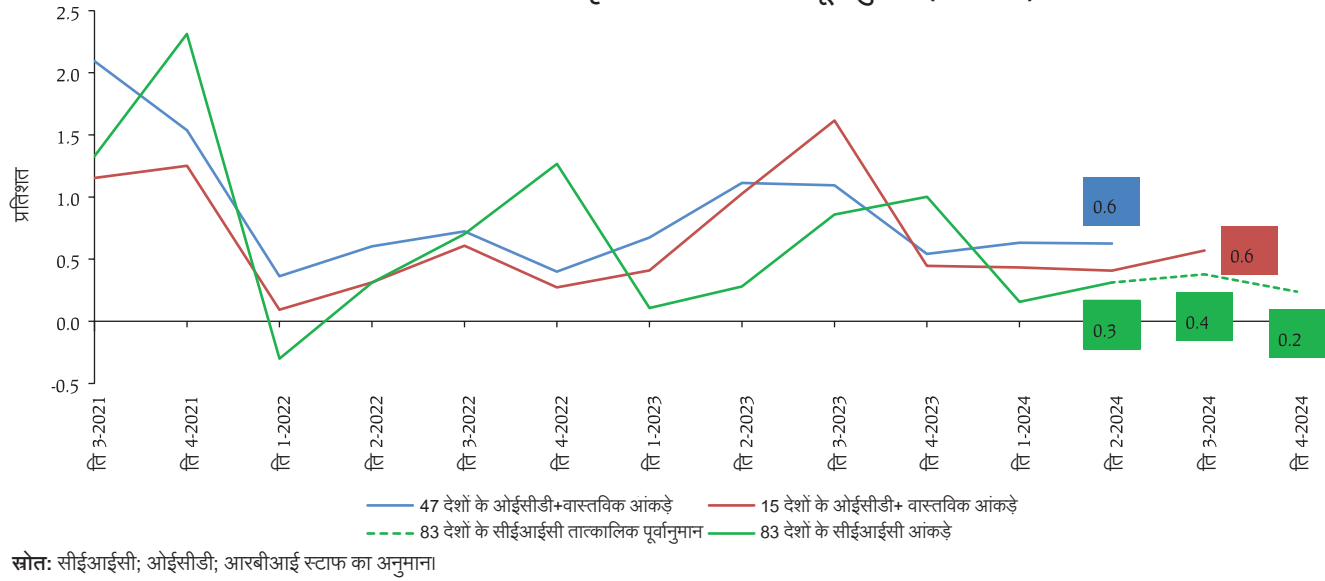
वैश्विक अर्थव्यवस्था चल रही भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद आघातसहनीय बनी हुई है, भले ही विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विकास का परिदृश्य अलग-अलग है। मौद्रिक नीति सामान्यीकरण आई में नीतिगत कार्रवाई को चला रहा है, भले ही कई देशों में अवस्फीति की गति असमान बनी हुई है। अपने अक्टूबर 2024 के वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक अपडेट में, आईएमएफ ने 2024 के लिए वैश्विक वृद्धि के अपने अनुमान को 3.2 प्रतिशत पर बनाए रखा, जो जुलाई के समान ही था (चार्ट II.1)। हालाँकि, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के लिए दृष्टिकोण में गिरावट के कारण 2025 के लिए वृद्धि के अनुमान को 10 आधार अंक (बीपीएस) घटाकर 3.2 प्रतिशत कर दिया गया क्योंकि चरम मौसम की घटनाओं और आपूर्ति व्यवधानों से उनके उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023 में वार्षिक औसत 6.7 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.8 प्रतिशत और 2025 में 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान है, साथ ही आई द्वारा ईएमडीई की तुलना में मुद्रास्फीति को जल्द ही लक्ष्य पर वापस लाने की उम्मीद है।

वैश्विक जीडीपी का हमारा मॉडल-आधारित तात्कालिक पूर्वानुमान, बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण 2024 की तीसरी तिमाही और 2024 की चौथी तिमाही में गति में कुछ कमी का संकेत देता है (चार्ट II.2)।

चार्ट II.1 आईएमएफ वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान



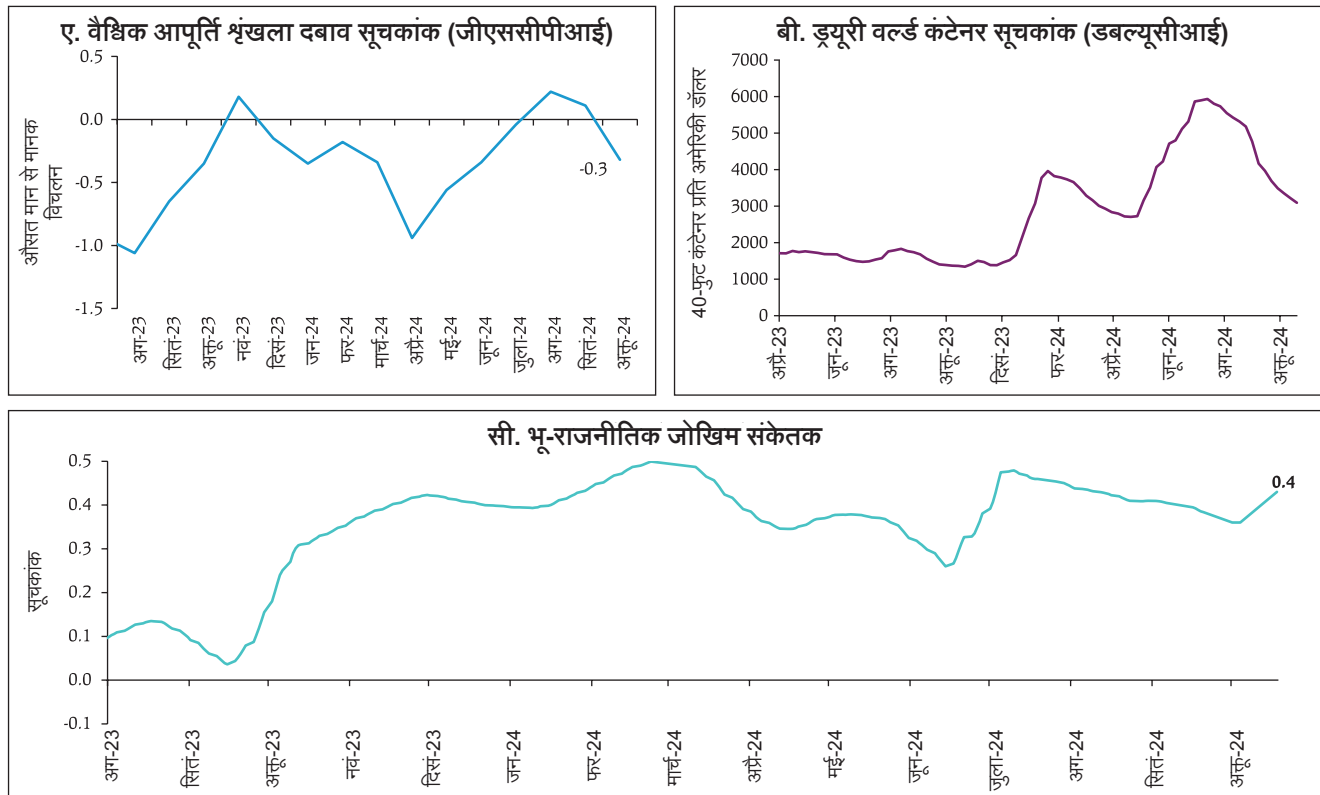
चार्ट II.2: वैश्विक जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक पूर्वानुमान (ति-द-ति)



वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) अक्टूबर 2024 में लगातार दूसरे महीने कम हुआ, और अपने

ऐतिहासिक औसत से नीचे गिर गया (चार्ट II.3ए)। आपूर्ति में व्यवधान के कारण कंटेनर शिपिंग लागत बढ़ी हुई है, हालांकि

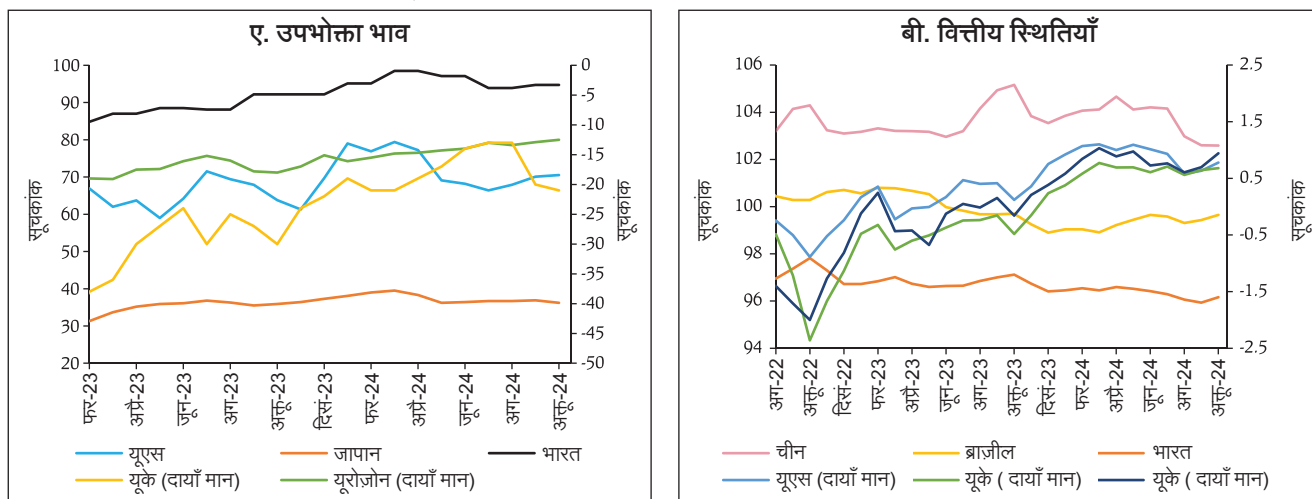
चार्ट II.3: भू-राजनीतिक जोखिम और वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव में रुझान



टिप्पणियाँ: 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों पर डेटा दर्शाता है।
 2. ड्रयूरी द्वारा साप्ताहिक मूल्यांकन किया गया डबल्यूसीआई प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल ढुलाई दरों की रिपोर्ट करता है। समग्र 8 शिपिंग मार्गों की मात्रा के भारत औसत को 40-फुट कंटेनर प्रति अमेरिकी डॉलर के रूप में दर्शाता है।

स्रोत: फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, अक्टूबर 2024; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.4: उपभोक्ता भाव और वित्तीय स्थितियां



टिप्पणियाँ: 1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है और 50 तटस्थता को दर्शाता है।
2. यूरोजोन और यूके: -100 आत्मविश्वास की अत्यधिक कमी का संकेत देता है, 0 तटस्थता को दर्शाता है जबकि 100 अत्यधिक आत्मविश्वास को दर्शाता है।
3. भारत और अमेरिका: सूचकांक का मान जितना अधिक होगा, उपभोक्ता विश्वास उतना ही अधिक होगा।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

सितंबर-अक्टूबर 2024 के दौरान इसमें कुछ कमी दर्ज की गई (चार्ट II.3बी)। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण अक्टूबर में भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ गए, जो जुलाई के मध्य से देखी गई नरमी के विपरीत है (चार्ट II.3सी)।

अक्टूबर 2024 में, अमेरिका, यूरो क्षेत्र और भारत में उपभोक्ता विश्वास में सुधार हुआ लेकिन यूके में यह खराब हो गया (चार्ट II.4ए)। प्रमुख आई और ईएमई में वित्तीय स्थितियां सहज हुईं (चार्ट II.4बी)।

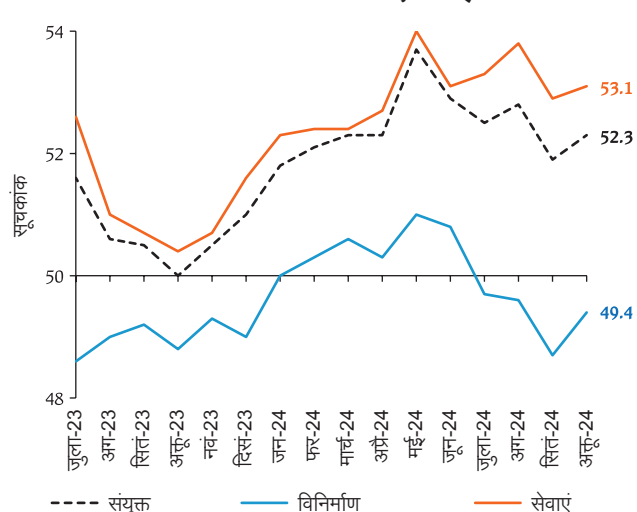
वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) सितंबर में दर्ज आठ महीने के निचले स्तर से अक्टूबर में बढ़ गया और लगातार बारहवें महीने विस्तार क्षेत्र में रहा (चार्ट II.5)। व्यापार, उपभोक्ता और वित्तीय सेवाओं में उत्पादन में विस्तार के साथ सेवा गतिविधियों में एक मजबूत पुनरुद्धार विनिर्माण में सुस्त प्रदर्शन की भरपाई करता है। नए ऑर्डर, रोजगार वृद्धि और खरीद के स्टॉक में कमी के कारण वैश्विक विनिर्माण पीएमआई अक्टूबर में लगातार चौथे महीने तटस्थ स्तर से नीचे रहा।

निर्यात ऑर्डर के लिए समग्र पीएमआई अक्टूबर में बढ़ी, लेकिन जून 2024 से यह संकुचन क्षेत्र में बनी हुई है क्योंकि

विनिर्माण निर्यात में गिरावट सेवा निर्यात में वृद्धि की तुलना में अधिक है। हालाँकि, अनुक्रमिक आधार पर, विनिर्माण निर्यात ऑर्डरों में कम संकुचन देखा गया, जबकि सेवा निर्यात ऑर्डरों में गिरावट आई (चार्ट II.6)।

अक्टूबर में वैश्विक कमोडिटी कीमतों में कमी आई क्योंकि धातु की कीमतों में गिरावट से ऊर्जा कीमतों में बढ़त की भरपाई

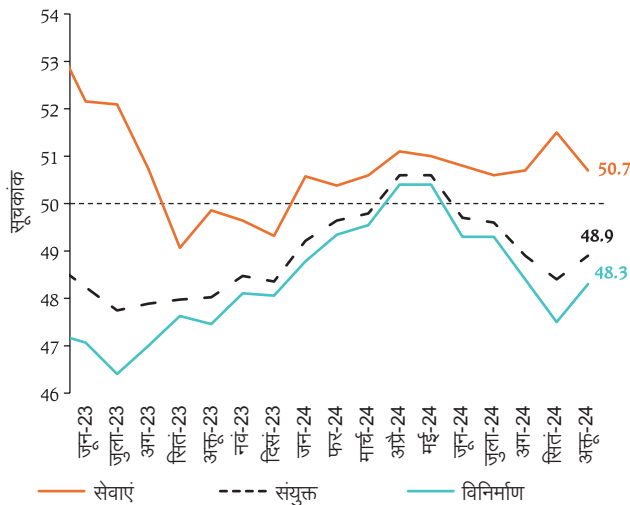
चार्ट II.5 : वैश्विक पीएमआई



टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत दर्शाते हैं।

स्रोत: एस एंड पी वैश्विका

चार्ट 11.6: वैश्विक पीएमआई: निर्यात आदेश



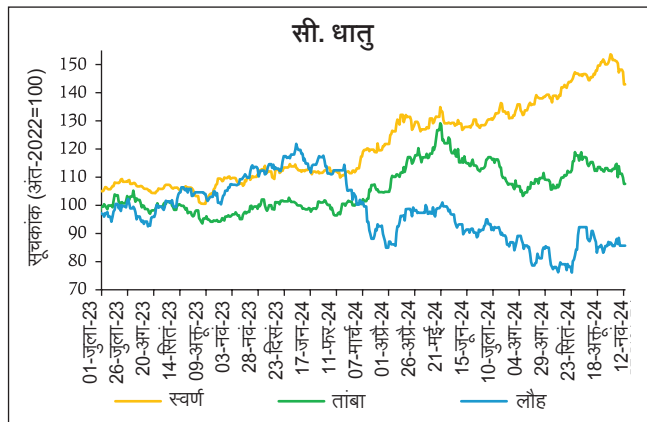
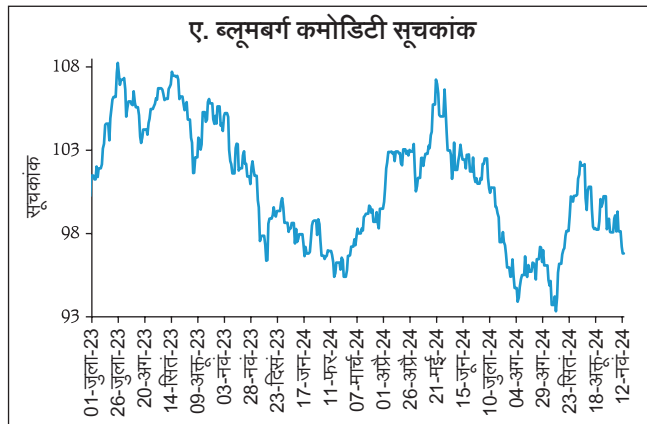
टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत दर्शाते हैं।
स्रोत: एस एंड पी वैश्विका

हो गई। ब्लूमबर्ग कमोडिटी सूचकांक अक्टूबर में 2.2 प्रतिशत (म-द-म) गिर गया (चार्ट 11.7ए)। खाद्य और कृषि संगठन

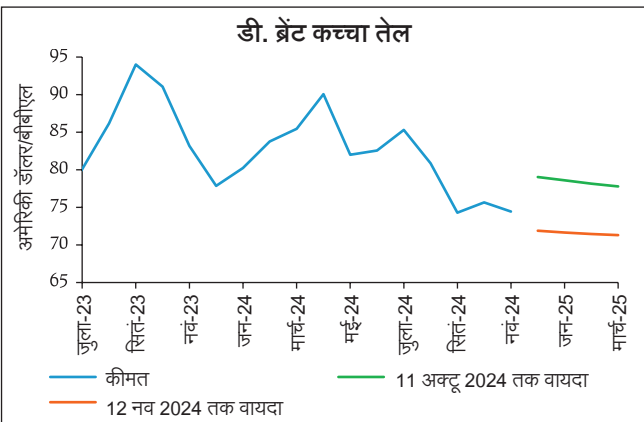
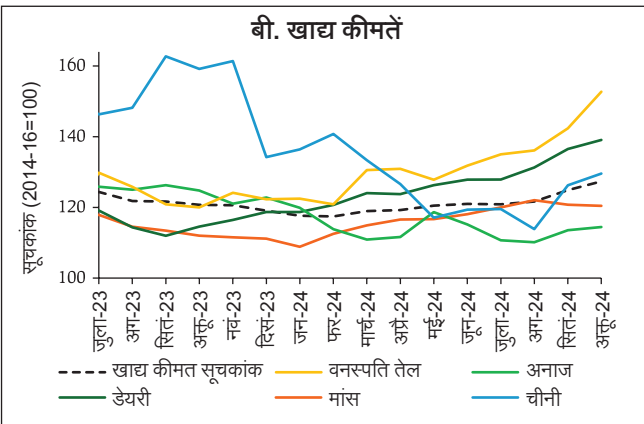
(एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक में अक्टूबर में 2.0 प्रतिशत (म-द-म) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें मांस को छोड़कर सभी श्रेणियों में कीमतें बढ़ गईं; सब्जियों की कीमतों में विशेष रूप से तेज वृद्धि देखी गई (चार्ट 11.7बी)। अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में धातु की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि प्रोत्साहन उपायों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के कारण आधारभूत धातु के दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता चीन की मांग में कमी आई।

अमेरिकी चुनावों को लेकर अनिश्चितताओं और मध्य पूर्व में संघर्षों के बीच सुरक्षा-कवच की मांग के कारण अक्टूबर में स्वर्ण की कीमतों में 4.6 प्रतिशत (म-द-म) की वृद्धि हुई, जो पहली बार 2700 अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गई। हालाँकि, नवंबर के पहले पखवाड़े में स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि बढ़ते प्रतिफल और मजबूत अमेरिकी डॉलर ने स्वर्ण रखने की अवसर लागत को बढ़ा दिया (चार्ट 11.7सी)। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें

चार्ट 11.7: कमोडिटी और खाद्य कीमतें



स्रोत: ब्लूमबर्ग; वर्ल्ड बैंक पिक शीट; और एफएओ



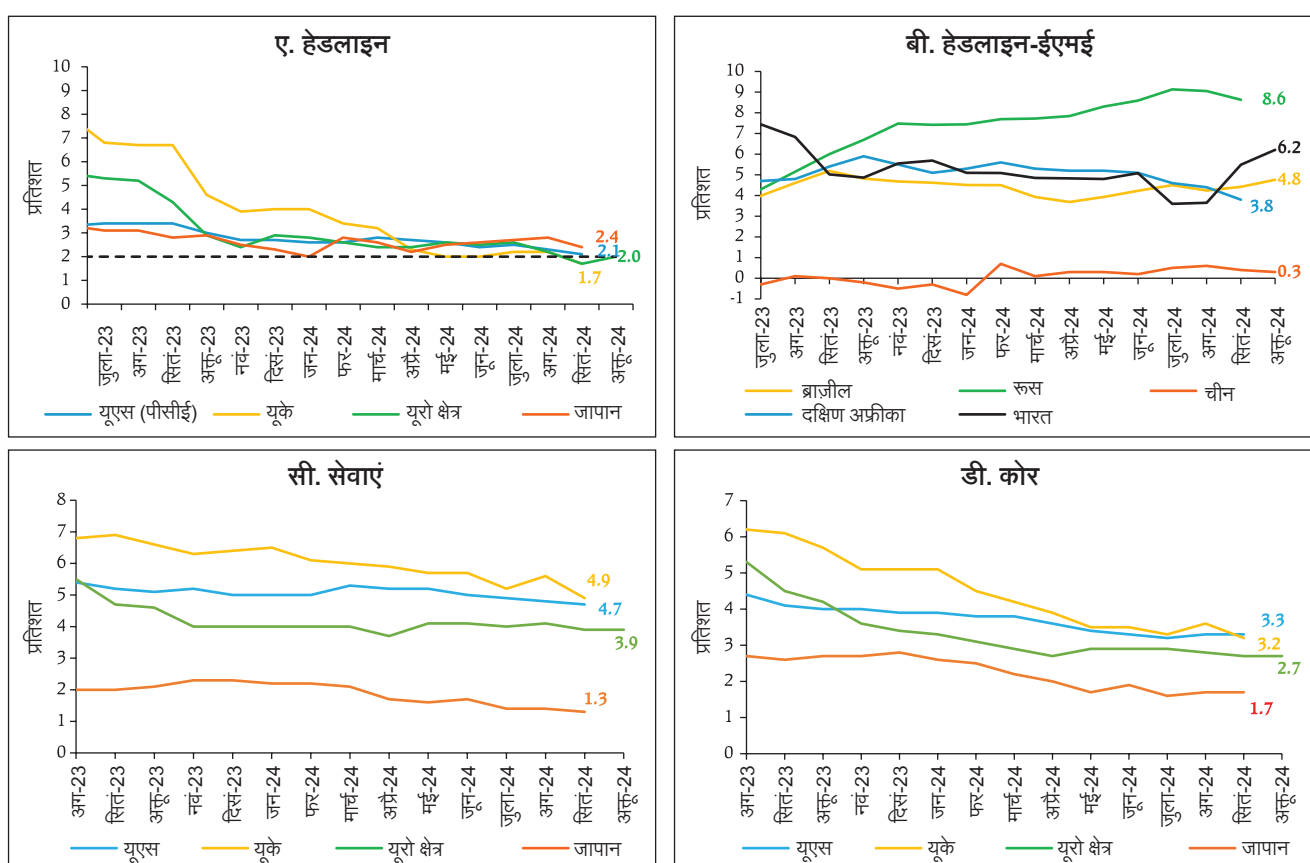
अक्टूबर की शुरुआत में बढ़ी क्योंकि मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद बाजार निशाने पर थे। हालाँकि, 2025 में आपूर्ति की संभावनाओं में वृद्धि और भू-राजनीतिक तनाव में आंशिक कमी को देखते हुए, महीने के उत्तरार्ध में तेल की कीमतों में गिरावट आई। कुल मिलाकर, अक्टूबर में कीमतों में 2.3 प्रतिशत (म-द-म) की वृद्धि हुई। नवंबर की पहली छमाही में, कमजोर मांग परिदृश्य के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई (चार्ट ॥.7डी)।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही, यद्यपि असमान रूप से, हालांकि सेवाओं की मुद्रास्फीति अभी भी ऊंची बनी हुई है, खासकर एई में। अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति सितंबर में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2024 में वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) 2.6 प्रतिशत हो गई। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) डिफ्लेटर के संदर्भ में

मुद्रास्फीति अगस्त में 2.3 प्रतिशत से घटकर सितंबर में 2.1 प्रतिशत हो गई। यूरो क्षेत्र में हेडलाइन मुद्रास्फीति सितंबर में 1.7 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 2.0 प्रतिशत हो गई (चार्ट ॥.8ए)। ईएमई के बीच, ब्राजील और रूस में मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन अक्टूबर में चीन में कम हो गई (चार्ट ॥.8बी)। अधिकांश एई में कोर और सेवा मुद्रास्फीति हेडलाइन से अधिक रही (चार्ट ॥.8सी और 8डी)।

भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के साथ-साथ अमेरिका और जापान में चुनाव परिणामों को देखते हुए अक्टूबर में वैश्विक इक्विटी बाजारों में गिरावट आई। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) वैश्विक सूचकांक में अक्टूबर में 2.3 प्रतिशत (म-द-म) की गिरावट दर्ज की गई, जबकि उभरते बाजारों के सूचकांक में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट ॥.9ए)। ईएमई इक्विटी बाजारों में गिरावट चीन में

चार्ट ॥.8: मुद्रास्फीति – एई और ईएमई



स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

गिरावट के कारण हुई क्योंकि सितंबर में घोषित प्रोत्साहन उपायों के बाद बाजार में तेजी से गिरावट आई। अमेरिकी चुनाव नतीजों (5 से 12 नवंबर के बीच) के बाद, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़त के कारण इक्विटी बाजारों में काफी तेजी आई, एमएससीआई वैश्विक सूचकांक में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

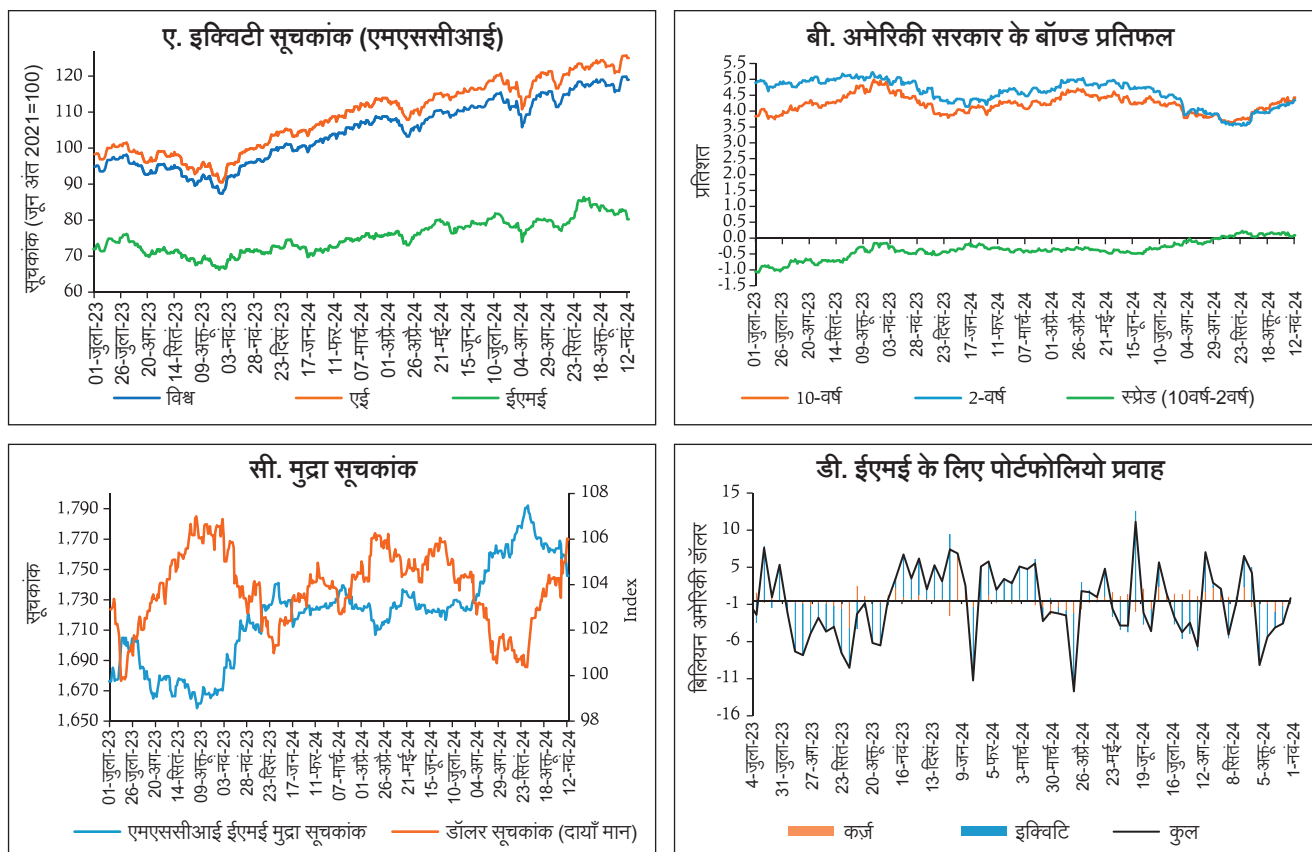
अक्टूबर में 10-वर्षीय और 2-वर्षीय बॉण्ड दोनों में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल क्रमशः 50 बीपीएस और 53 बीपीएस तक बढ़ गए, क्योंकि विभिन्न डेटा रिलीज के बीच यूएस जीडीपी सहित प्रमुख दर में कटौती की उम्मीद कम हो गई, जो अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित ताकत का संकेत देती है (चार्ट 11.9बी)। नवंबर में प्रतिफल और बढ़े क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद बाजार ने अमेरिका में उच्च बजट घाटे को ध्यान में रखना शुरू कर दिया। 05 नवंबर से (12 नवंबर तक) 10-वर्षीय और 2-वर्षीय दोनों

प्रतिफल में क्रमशः 16 बीपीएस और 17 बीपीएस की वृद्धि हुई।

मुद्रा बाजारों में, अक्टूबर में अमेरिकी डॉलर में 3.2 प्रतिशत (म-द-म) वृद्धि हुई, जबकि ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक में अक्टूबर में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण इक्विटी सेगमेंट में पूंजी का बहिर्वाह था। नतीजों के बाद, अमेरिकी डॉलर सूचकांक में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 11.9सी और 11.9डी)।

ईई केंद्रीय बैंकों में, यूएस फेडरल रिज़र्व ओपन मार्केट्स कमेटी (एफओएमसी) ने 07 नवंबर 2024 को फेडरल फंड्स रेट के लिए लक्ष्य सीमा को 25 आधार अंकों तक कम करने का फैसला किया और संकेत दिया कि "मुद्रास्फीति ने समिति के 2 प्रतिशत उद्देश्य की ओर प्रगति की है लेकिन कुछ हद तक अधिक बनी हुई है"।⁸ यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर में अपनी नीति दरों

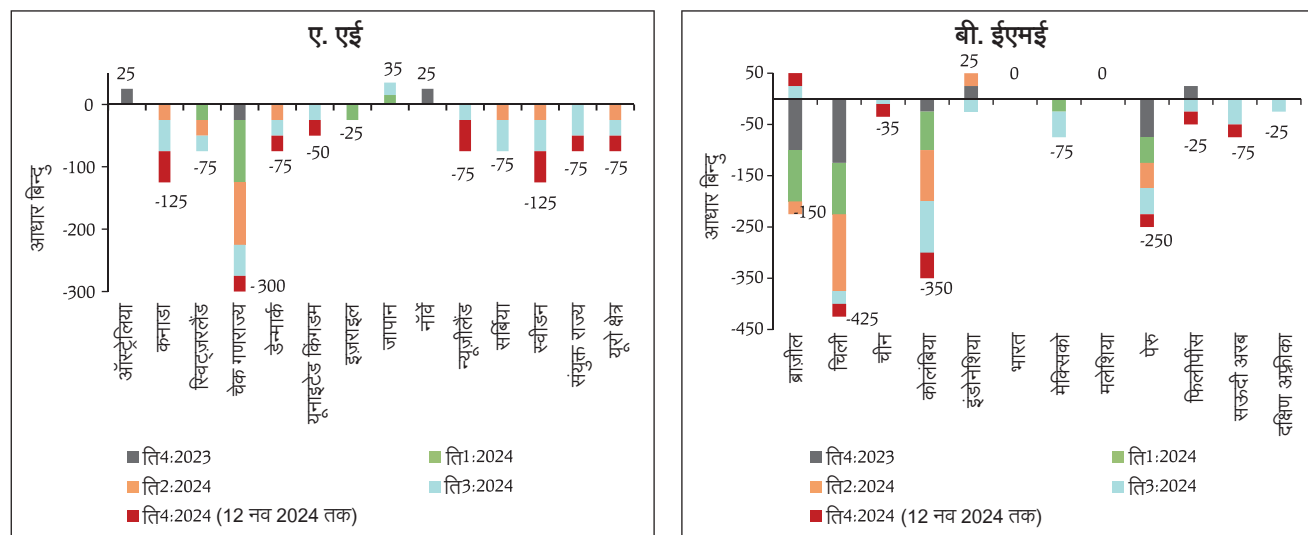
चार्ट 11.9: वैश्विक वित्तीय बाजार



स्रोत: ब्लूमबर्ग; और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ)।

⁸ <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20241107a.htm>

चार्ट II.10: नीतिगत दरों में परिवर्तन



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

में 25 बीपीएस की कटौती की, जबकि स्वीडन और कनाडा ने क्रमशः नवंबर और अक्टूबर में अपनी बेंचमार्क दरों में 50 बीपीएस की कटौती की। जापान, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया ने विराम जारी रखा (चार्ट II.10 ए)। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, पेरू और मेक्सिको ने नवंबर में अपनी नीति दरों में 25 बीपीएस की कमी की (चार्ट II.10 बी)। चल रहे प्रोत्साहन उपायों के हिस्से के रूप में, चीन ने अपने एक वर्ष के लोन प्राइम रेट (एलपीआर) और पांच वर्ष के एलपीआर को क्रमशः 25 बीपीएस घटाकर 3.10 प्रतिशत और 3.60 प्रतिशत कर दिया। इसके विपरीत, रूस ने अक्टूबर में अपनी नीति दर को 200 आधार अंक बढ़ाकर 21.0 प्रतिशत कर दिया तथा ब्राजील ने मुद्रास्फीति दबावों से निपटने के लिए नवंबर में अपनी दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 11.25 प्रतिशत कर दिया।

III. घरेलू गतिविधियां

बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों के बावजूद, भारत के सामने आने वाले आपूर्ति शृंखला दबाव अक्टूबर में कम हो गए, जो ऐतिहासिक औसत स्तरों से नीचे गिर गए (चार्ट III.1ए)। हमारा आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई)⁹, उच्च आवृत्ति संकेतकों की एक शृंखला के आधार पर, 2024-25

⁹ सूचकांक उद्योग, सेवाओं, वैश्विक और विविध गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 मासिक संकेतकों में अंतर्निहित गतिशील सामान्य कारक को निकालता है।

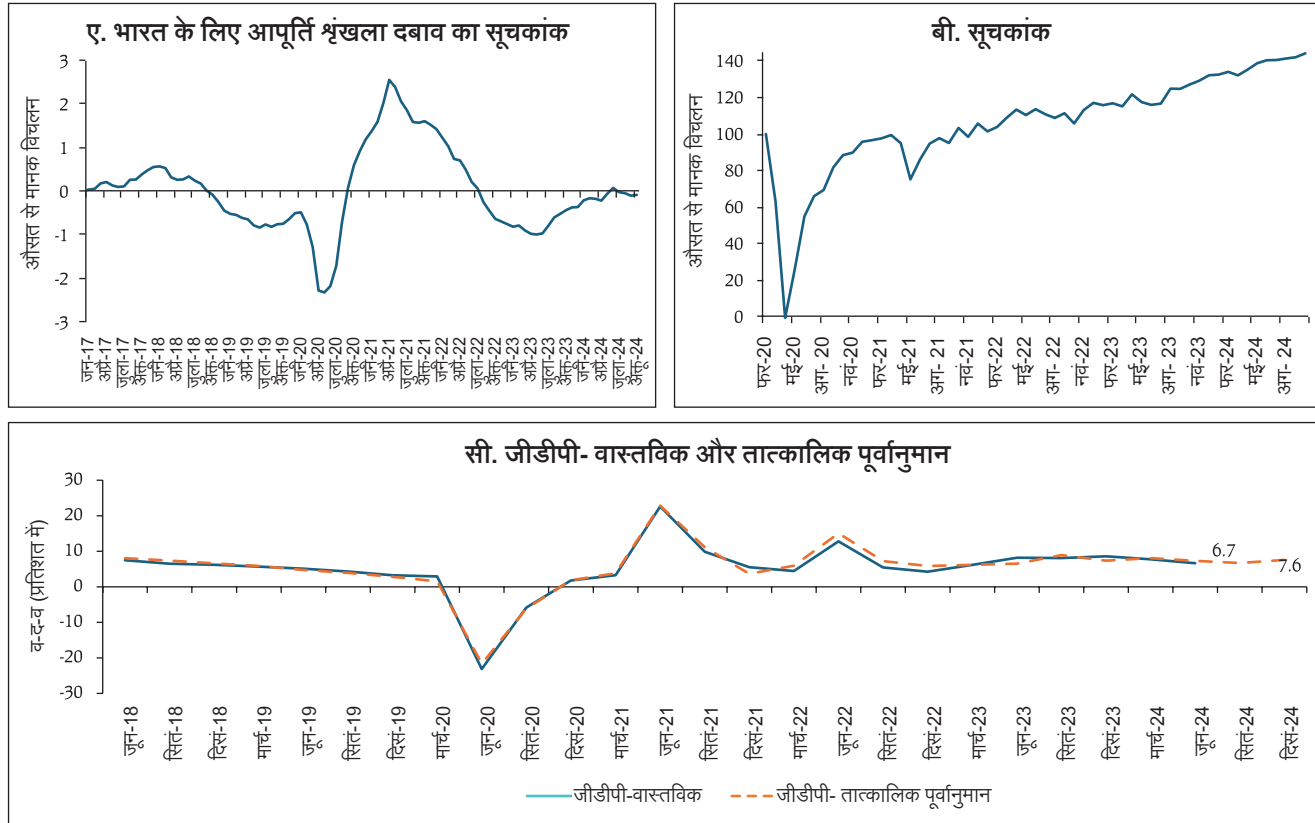
की दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाता है। (चार्ट III.1बी और III.1सी)।

सकल मांग

उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि अक्टूबर 2024 में कुल मांग ने फिर से जोर पकड़ा, जो त्योहारी सीजन की मांग से बढ़ा था। ई-वे बिलों में वर्ष-दर-वर्ष 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो उच्च आपूर्ति शृंखला गतिविधि को दर्शाती है (चार्ट III.2ए)। मूल्य के संदर्भ में टोल संग्रह में 10.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) और मात्रा के संदर्भ में 7.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.2बी)।

ऑटोमोबाइल की बिक्री में 11.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई क्योंकि त्योहारी सीजन के खर्च और वाहन निर्माताओं से छूट ने मांग को बढ़ावा दिया (चार्ट III.3ए)। विशेष रूप से, यात्री वाहन खंड और दोपहिया वाहनों में बिक्री ने समग्र वृद्धि को गति दी। घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री में भी 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मई 2011 के बाद से सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई। (चार्ट III.3बी)। परिवहन और गैर-परिवहन दोनों क्षेत्रों में वाहन पंजीकरण में वृद्धि हुई (चार्ट III.3सी)। विमानन टरबाइन ईंधन और मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) की मांग में वृद्धि से प्रेरित लगातार

चार्ट III.1 : आर्थिक गतिविधि और जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक पूर्वानुमान

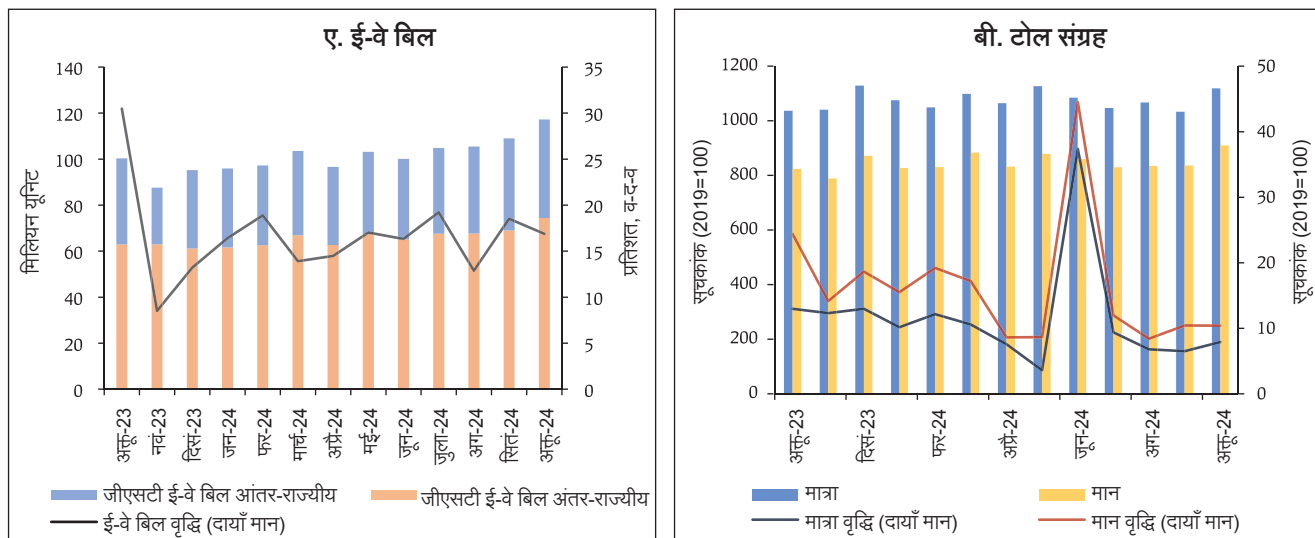


टिप्पणी: आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण एक गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों को अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। फरवरी 2020 में ईएआई को 100 और अप्रैल 2020 में 0 तक बढ़ाया गया, जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना था।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

दो महीनों के संकुचन के बाद पेट्रोलियम की खपत में तेजी आई [चार्ट III.3डी]।

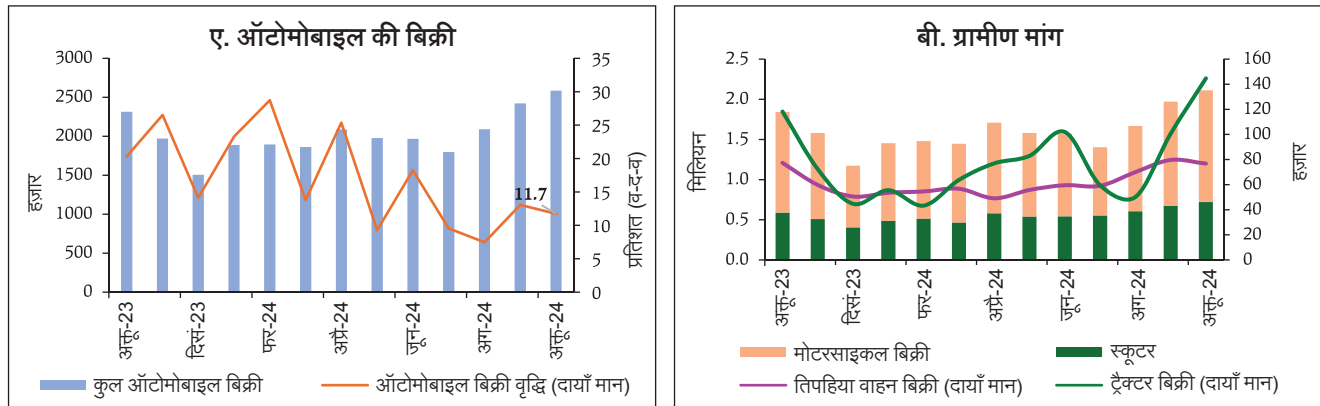
अक्टूबर 2024 में 55.7 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की अब तक की सबसे अधिक

चार्ट III.2: ई-वे बिल और टोल संग्रह



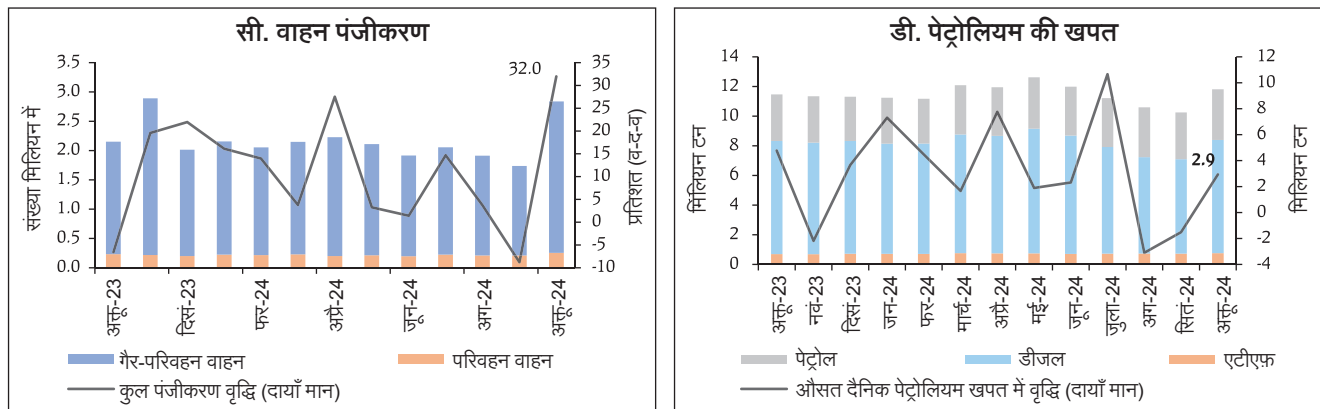
स्रोत: जीएसटीएन; आरबीआई

चार्ट III.3: ऑटोमोबाइल क्षेत्र संकेतक



स्रोत: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम)।

स्रोत: सियाम; और ट्रैक्टर मेकनाइजेशन एसोसिएशन (टीएमए)।



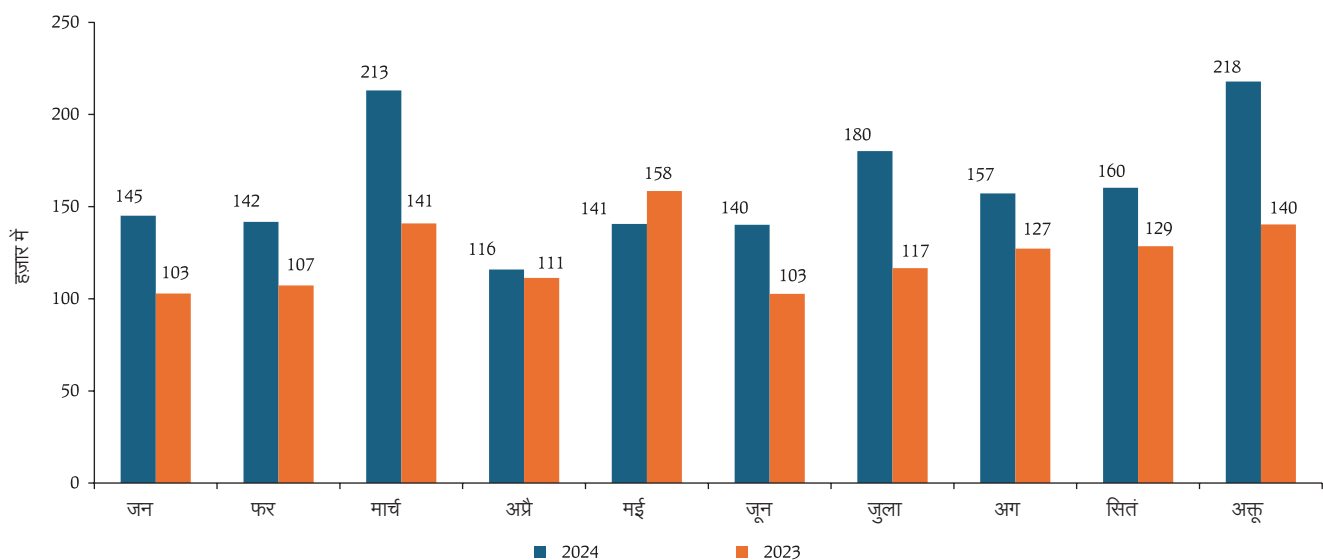
स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ।

बिक्री भी देखी गई (चार्ट III.4)। जनवरी-अक्टूबर 2024 के दौरान कुल ईवी बिक्री पहले ही 2023 में कुल ईवी बिक्री को पार कर

चुकी है। नीति समर्थन पहल के साथ ईवी अपनाने में दृढ़ता से वृद्धि हो रही है (बॉक्स 1)।

चार्ट III.4 इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री



स्रोत: वाहन पोर्टल।

बॉक्स 1: भारत में 2डबल्यू-ईवी अपनाने पर राज्य-स्तरीय नीतियों के प्रभाव का आकलन

भारत में ईवी नीति के विकास को इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से पहलों (प्रोत्साहन, सब्सिडी और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं) की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया है (सारणी 1 ए)। केंद्र सरकार की पहल पर निर्माण करते हुए, अधिकांश राज्यों ने अपनी ईवी नीतियां पेश की हैं।¹⁰ केंद्र द्वारा हाल ही में घोषित अभिनव वाहन संवर्द्धन में इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति (पीएम ई-ड्राइव) योजना का उद्देश्य पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में और तेजी लाना है।¹¹

उच्च अग्रिम लागत को देखते हुए, अध्ययनों से पता चला है कि छूट, कर क्रेडिट और कम पंजीकरण शुल्क जैसे मौद्रिक प्रोत्साहन उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभिक खरीद लागत को कम करके ईवी अपनाने को बढ़ाते हैं (जेन एवं अन्य., 2018; और सिएर्ज़चुला एवं अन्य., 2014)।

2-व्हीलर ईवी (2डबल्यू-ईवी) को अपनाने पर राज्य-स्तरीय ईवी नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, एक एडॉप्शन रैशियो (एआर) का निर्माण निम्नानुसार किया गया:

$$AR = \frac{2W-EVs \text{ registered during a period}}{\text{Total non-electric } 2Ws \text{ registered during a period}} * 100$$

एक उच्च एआर गैर-ईवी के सापेक्ष ईवी बिक्री का एक बड़ा हिस्सा दर्शाता है और इसलिए एक गहरी बाजार पैठ है। सहायक ईवी नीतियों के कार्यान्वयन ने ईवी अपनाने को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जैसा कि एआर में उल्लेखनीय वृद्धि से स्पष्ट है (चार्ट 1ए)।

मार्च 2021 से दिसंबर 2023 तक 23 भारतीय राज्यों के तिमाही आंकड़ों पर विचार किया गया। प्रत्येक राज्य के लिए नीति प्रोत्साहन के लिए एक चर बनाया गया जो नीति लागू होने के बाद की अवधि के लिए 1 का मान लेता है और अन्यथा 0। बाइनरी-स्तरीय नीति संकेतक नीतिगत उपायों के विविध सेट को समाहित करता है, जिसमें मांग प्रोत्साहन, अवसंरचना गतिविधियों की लागत, आर एंड डी, और संबंधित पहलू शामिल हैं जो समग्र रूप से ईवी नीति के प्रभाव को इंगित करते हैं। इसके बाद, निम्नलिखित प्रतिगमन समीकरण का अनुमान लगाया गया:

$$AR_{(it)} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Policy.Indicator}_{(it)} + \alpha_1 + \epsilon_{(it)}$$

सारणी 1ए: भारत में ईवी नीति का विकास

नीति	लक्ष्य	प्रोत्साहन
भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन (एएफएसटी) (2011)	स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।	प्रत्यक्ष अंतिम उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में केंद्रीय वित्तीय सहायता; अनुसंधान एवं विकास तथा घरेलू विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 (2013 में लॉन्च)	वर्ष 2020 से वर्ष दर वर्ष इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री करना।	कर प्रोत्साहन; चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्थन; पायलट परियोजनाएं; बाजार निर्माण; और आर एंड डी समर्थन।
भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना चरण I (2015) (एनईएमएमपी के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया)	चार मुख्य क्षेत्र: ● मांग निर्माण ● प्रौद्योगिकी मंच ● पायलट परियोजनाएं ● चार्जिंग के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर।	ईवीएस के खरीदारों के लिए अग्रिम रूप से कम खरीद मूल्य, पायलट परियोजनाओं के तहत विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान, आर एंड डी / प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के रूप में मांग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन।
फेम इंडिया योजना चरण- II (2019) (फेम इंडिया योजना चरण- I का विस्तार)	ईवी को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करना; ईवी के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना; विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का संचालन।	खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन की पेशकश करके खरीदारों को वित्तीय सब्सिडी; केंद्रीय सब्सिडी के अलावा राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन; और आर एंड डी समर्थन।
अभिनव वाहन वृद्धि में इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति (पीएम ई-ड्राइव) [2024]	विद्युत गतिकी को बढ़ावा देना, परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार; ईवी को अपनाने में तेजी लाना; कुशल, प्रतिस्पर्धी और आघात-सहनीय ईवी विनिर्माण।	2डबल्यू-ईवी, 3डबल्यू-ईवी, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी के लिए सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन; उच्च ईवी प्रवेश और राजमार्गों के साथ चुनिंदा शहरों में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना।

स्रोत: पीआईबी; बीईई¹²; और लेखकों का संकलन।

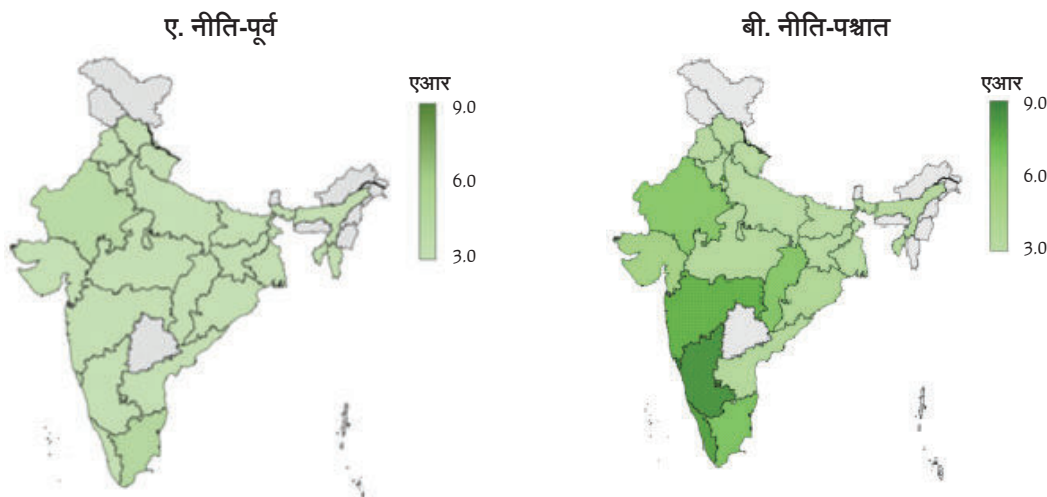
(Contd.)

¹⁰ <https://evyatra.beeindia.gov.in/state-govt/>

¹¹ https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/docs/policy_document/257594.pdf

¹² <https://evyatra.beeindia.gov.in/central-govt-initiatives/>

चार्ट 1ए: भारत में 2डबल्यू-ईवी को अपनाना (राज्य ईवी नीति लागू होने से पहले और बाद में)



- टिप्पणीयां:** 1. प्रत्येक राज्य के लिए नीति-पूर्व अंगीकरण के अनुपात की गणना ईवी नीति अधिसूचना तिमाही से पहले की पांच तिमाहियों के औसत जकरण के अनुपात के रूप में की जाती है।
2. इसी तरह, प्रत्येक राज्य के लिए नीति-पश्चात अंगीकरण के अनुपात को ईवी नीति घोषणा तिमाही के बाद की तिमाहियों के लिए अंगीकरण के अनुपात का औसत निकालकर निर्धारित किया जाता है।
3. उन राज्यों के लिए जहां अध्ययन अवधि से पहले ईवी नीति लागू की गई थी, नीति-पश्चात अंगीकरण के अनुपात की गणना मार्च 2021 तिमाही से शुरू होने वाले अंगीकरण के अनुपात के औसत के रूप में की जाती है।

स्रोत: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएम), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो; और लेखकों की गणना।

जहां β_1 नीति अपनाने के बाद अपनाने के अनुपात में परिवर्तन को मापता है।

नीति संकेतक के लिए एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण मूल्य इंगित करता है कि भारत में 2डबल्यू-ईवी को अपनाने में एक सहायक ईवी नीति व्यवस्था में तेजी आई है (सारणी 1बी)¹³

संदर्भ:

- Jenn, A., Springel, K., and Gopal, A. R. (2018). Effectiveness of electric vehicle incentives in the United States. *Energy Policy*, 119, 349-356.
- Sierzechula, W., Bakker, S., Maat, K., and Van Wee, B. (2014). The influence of financial incentives and other socio-economic factors on electric vehicle adoption. *Energy Policy*, 68, 183-194.
- Atal Singh, Satyam Kumar, Abhyuday Harsh and Tista Tiwari (2024). Impact of State-Level Policies on 2W-EV Adoption in India, *Mimeo*.

सारणी 1 बी: पैनल प्रतिगमन परिणाम

आश्रित चर: अंगीकरण अनुपात (23 राज्यों के लिए राज्य-वार)

	अवधि (मार्च 2021- दिसंबर 2023) नमूना आकार = 276
व्याख्यात्मक चर	
नीति संकेतक	3.1*** (0.52)

टिप्पणी: *, ** और *** 10, 5 और 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्व दर्शाते हैं। कोष्ठक में आंकड़े मानक त्रुटियां हैं।

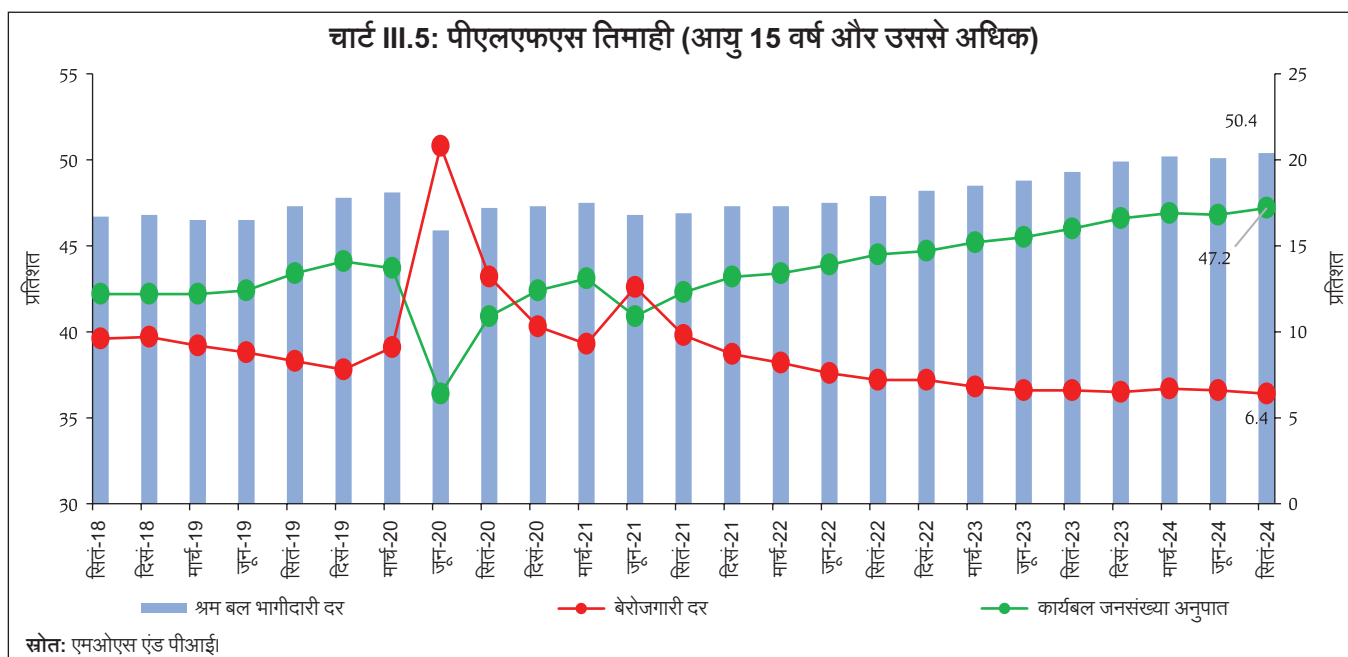
स्रोत: लेखकों का अनुमान।

नवीनतम तिमाही शहरी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट¹⁴ के अनुसार, भारत में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर (यूआर) जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही में घटकर 6.4 प्रतिशत हो गई – जो जून 2018 में पीएलएफएस श्रृंखला की स्थापना के बाद से सबसे कम है – जो पिछली तिमाही में 6.6

प्रतिशत थी (चार्ट III.5)। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) दोनों में वृद्धि के साथ पुरुष और महिला दोनों श्रमिकों के लिए बेरोजगारी में गिरावट आई। समग्र रोजगार में नियमित वेतनभोगी श्रमिकों की हिस्सेदारी तिमाही में बढ़ी जबकि स्व-नियोजित श्रमिकों और

¹³ हालांकि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि नीति अपनाने से पहले और बाद में अपनाने की दर में अंतर के लिए कई अन्य कारकों की भी भूमिका हो सकती है, जो आगे के अध्ययन की गुंजाइश प्रदान करता है।

¹⁴ तिमाही बुलेटिन पीएलएफएस_जुलाई_सितंबर_2024.पीडीएफ।

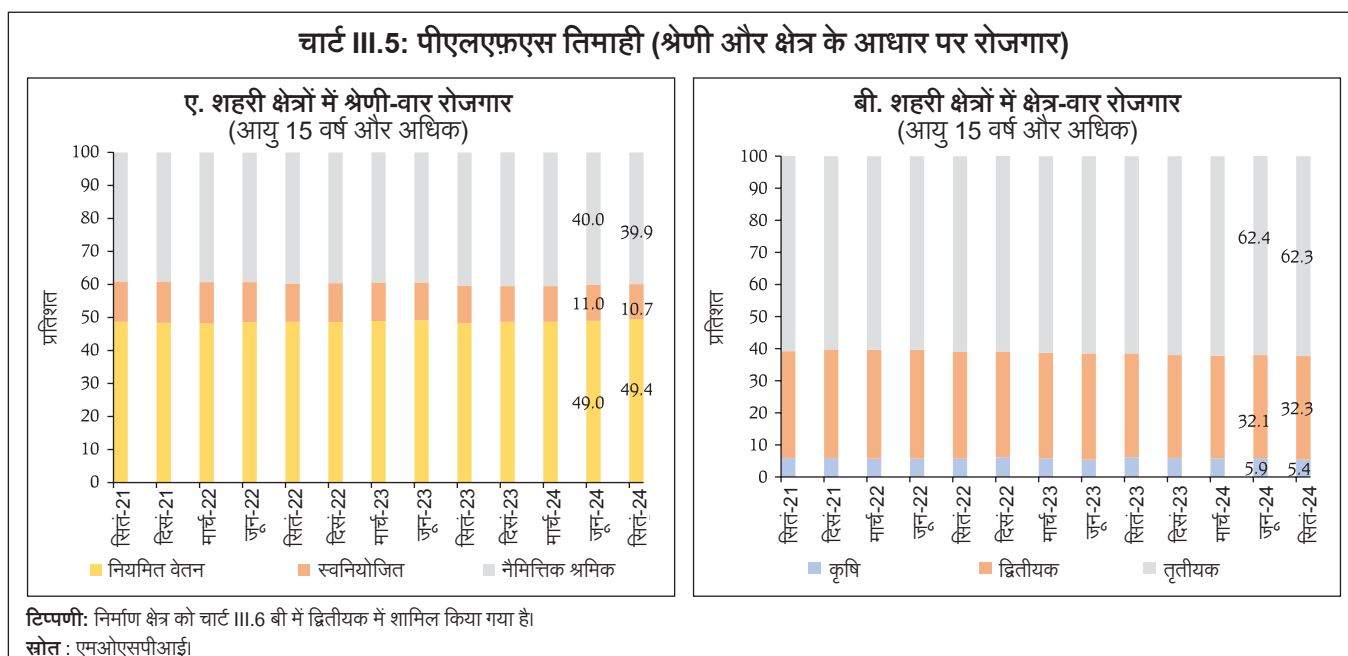


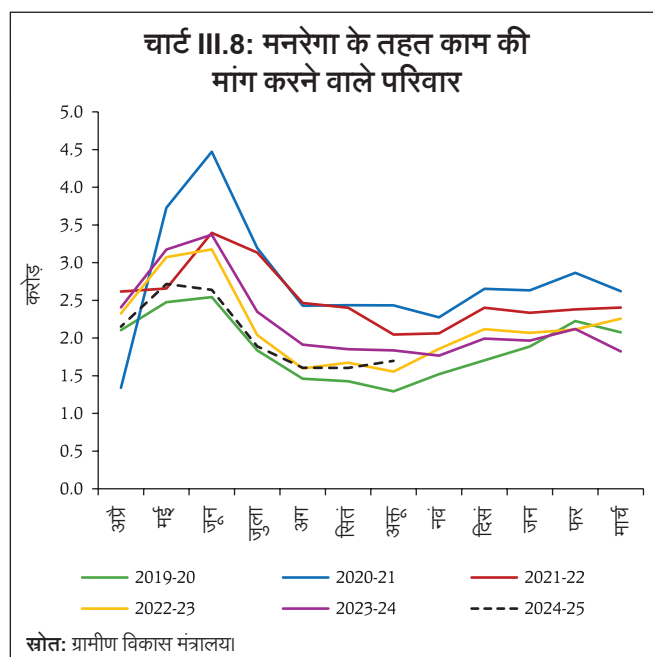
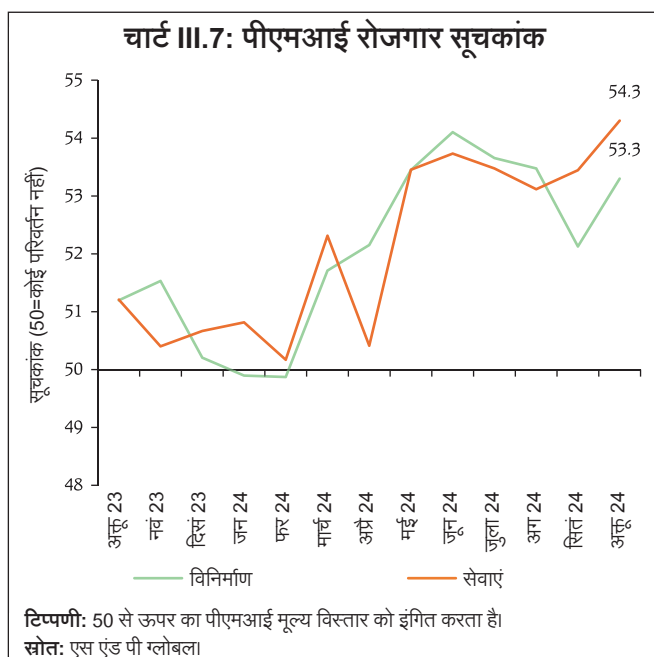
आकस्मिक श्रमिकों की हिस्सेदारी में पिछली तिमाही से गिरावट दर्ज की गई (चार्ट III.6ए)। भारत में नगरीय क्षेत्रों के लगभग दो-तिहाई श्रमिक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में नियोजित हैं (चार्ट III-6बी)।

पीएमआई रोजगार सूचकांकों के अनुसार, संगठित विनिर्माण रोजगार ने अक्टूबर में त्वरण दर्ज किया और लगातार आठवें

महीने विस्तारवादी क्षेत्र में बना रहा (चार्ट III.7)। सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की दर में दो वर्षों में सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

2024-25 के दौरान अब तक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत परिवारों की काम की मांग आम तौर पर महामारी के बाद के अधिकांश

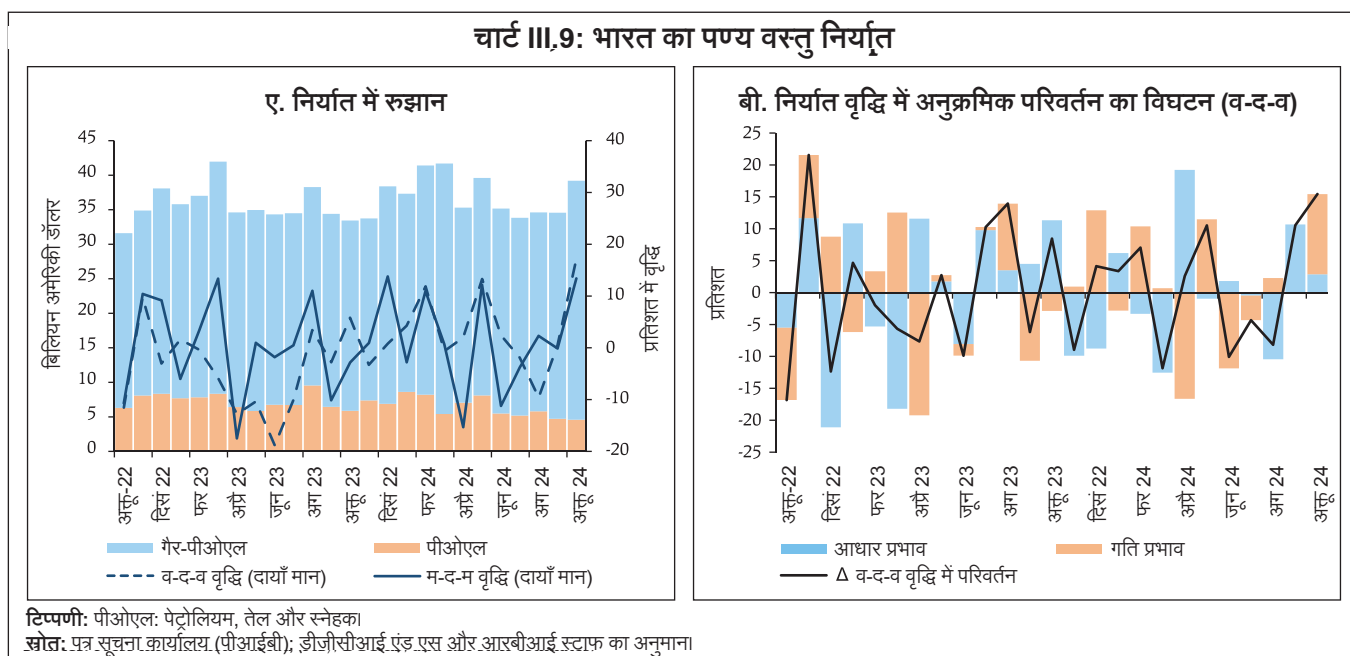




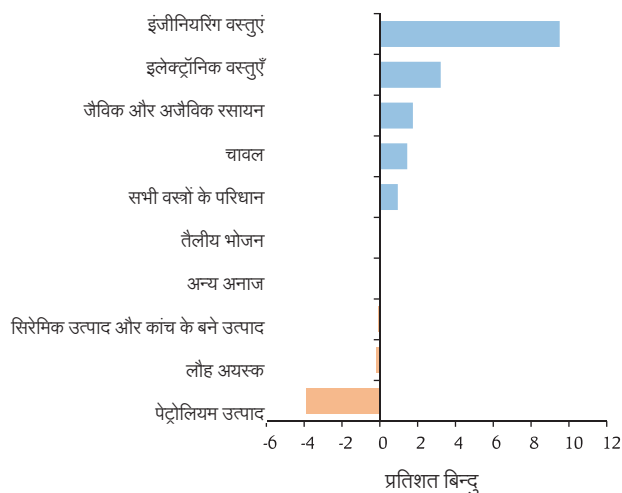
वर्षों की तुलना में कम रही है (चार्ट III.8)। हालांकि अक्टूबर में एक क्रमिक वृद्धि देखी गई थी, यह एक वर्ष पहले दर्ज किए गए स्तरों से कम रही है, जो वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की उपलब्धता में वृद्धि का संकेत देती है।

अक्टूबर 2024 में भारत का पण्य वस्तु निर्यात 39.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो मजबूत गति और अनुकूल आधार प्रभाव दोनों से प्रेरित है (चार्ट III.9)।

अक्टूबर में 30 प्रमुख जिंसों में से 25 (निर्यात बास्केट का 72.8 प्रतिशत हिस्सा) का निर्यात सालाना आधार पर बढ़ा। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, चावल और सभी वस्त्रों के रेडीमेड वस्त्र (आरएमजी) निर्यात वृद्धि के मुख्य वाहक रहे, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों, लौह अयस्क, और सिरेमिक उत्पादों और कांच के बने पदार्थ ने कमी दर्ज की (चार्ट III.10)। अप्रैल-अक्टूबर 2024



चार्ट III.10: भारत का पण्य वस्तु निर्यात – सापेक्ष योगदान (अक्टूबर 2023 की तुलना में अक्टूबर 2024)



स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

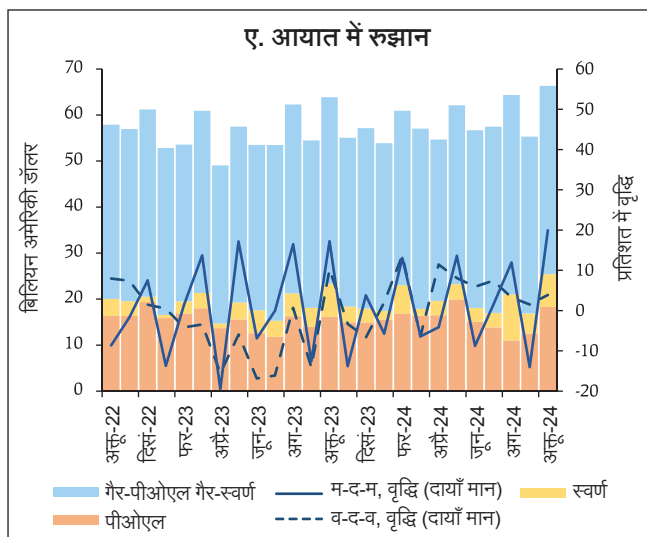
के दौरान, भारत का पण्य निर्यात 3.2 प्रतिशत बढ़कर 252.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका कारण मुख्य रूप से इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवा और औषधि, रसायन और सभी वस्त्रों के रेडीमेड ने किया, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न और आभूषण, लौह अयस्क और समुद्री उत्पादों ने निर्यात वृद्धि को कम कर दिया।

अक्टूबर में 20 प्रमुख गंतव्यों में से 17 का निर्यात वार्षिक आधार पर बढ़ा। अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान, 20 प्रमुख गंतव्यों में से 13 के निर्यात में विस्तार देखा गया, जिसमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड शीर्ष तीन निर्यात गंतव्य थे।

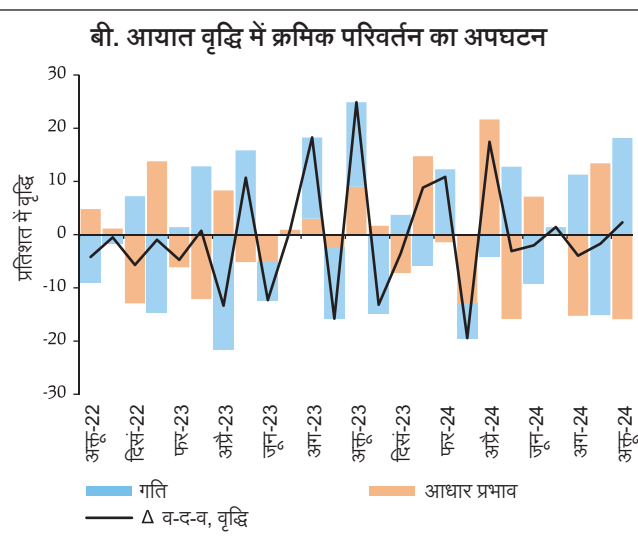
पण्य वस्तुओं के आयात में अक्टूबर में लगातार सातवें महीने विस्तार हुआ और यह सकारात्मक गति के कारण 3.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि के साथ 66.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक मासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया (चार्ट III.11)। 30 प्रमुख जिनसे में से 20 जिनसे (आयात बास्केट का 68.4 प्रतिशत हिस्सा) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विस्तार दर्ज किया गया।

पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वनस्पति तेल, अलौह धातु, और मशीनरी ने सकारात्मक योगदान दिया, जबकि चांदी, कोयला, कोक और ब्रिकेट, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों, परिवहन उपकरण और स्वर्ण ने अक्टूबर में आयात वृद्धि में नकारात्मक योगदान दिया (चार्ट III.12)। अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान, 416.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत के पण्य आयात में 5.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसका कारण मुख्य रूप से पीओएल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्वर्ण, अलौह धातु और मशीनरी रहे। मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, कोयला, कोक और ब्रिकेट,

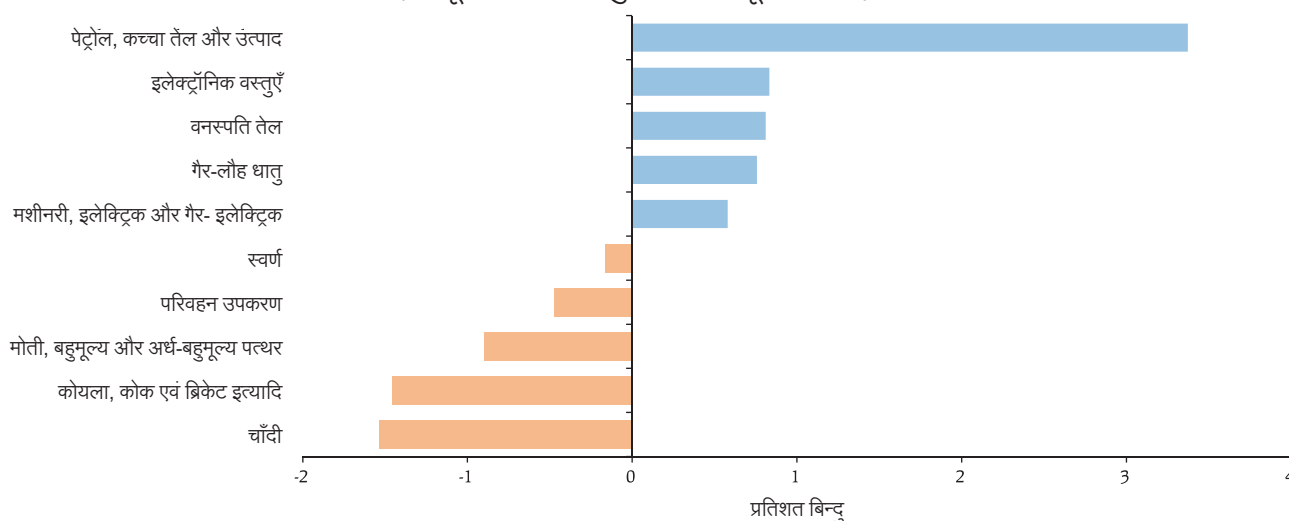
चार्ट III.11: भारत का पण्य वस्तु आयात



स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।



चार्ट III.12 भारत का पण्य वस्तु आयात-सापेक्ष योगदान
(अक्टूबर 2023 की तुलना में अक्टूबर 2024)



स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई कर्मचारियों का अनुमान।

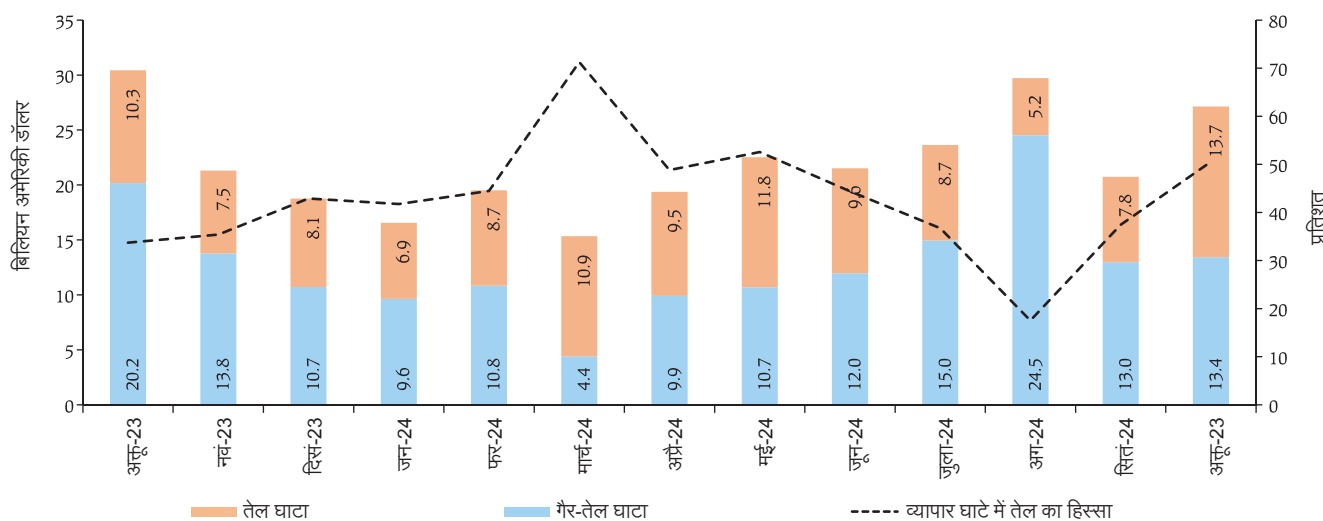
रासायनिक सामग्री और उत्पाद, उर्वरक, और रंगाई, टैनिंग और रंग सामग्री ने नकारात्मक योगदान दिया।

अक्टूबर में 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 11 से आयात में विस्तार हुआ, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 13 से आयात में वृद्धि हुई।

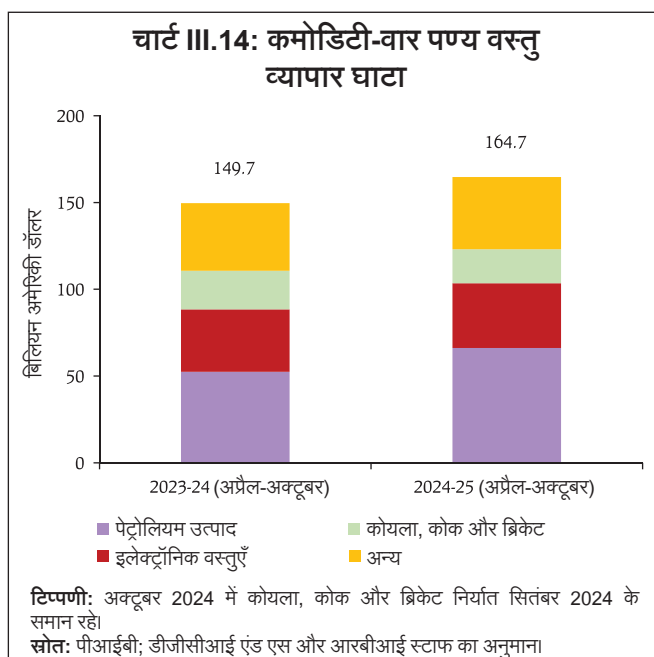
अक्टूबर 2024 में 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पण्य वस्तु व्यापार घाटा अक्टूबर 2023 में 30.4 बिलियन अमेरिकी

डॉलर से कम था, जबकि पिछले महीने से इसमें क्रमिक वृद्धि हुई थी। अक्टूबर में तेल घाटा एक वर्ष पहले के 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नतीजतन, पण्य वस्तु व्यापार घाटे में तेल घाटे का हिस्सा एक वर्ष पहले के 33.7 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 50.5 प्रतिशत हो गया। गैर-तेल घाटा एक वर्ष पहले के 20.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अक्टूबर में 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.13)।

चार्ट III.13: भारत के पण्य वस्तु व्यापार घाटे का अपघटन



स्रोत: पीआईबी; और डीजीसीआईएस।

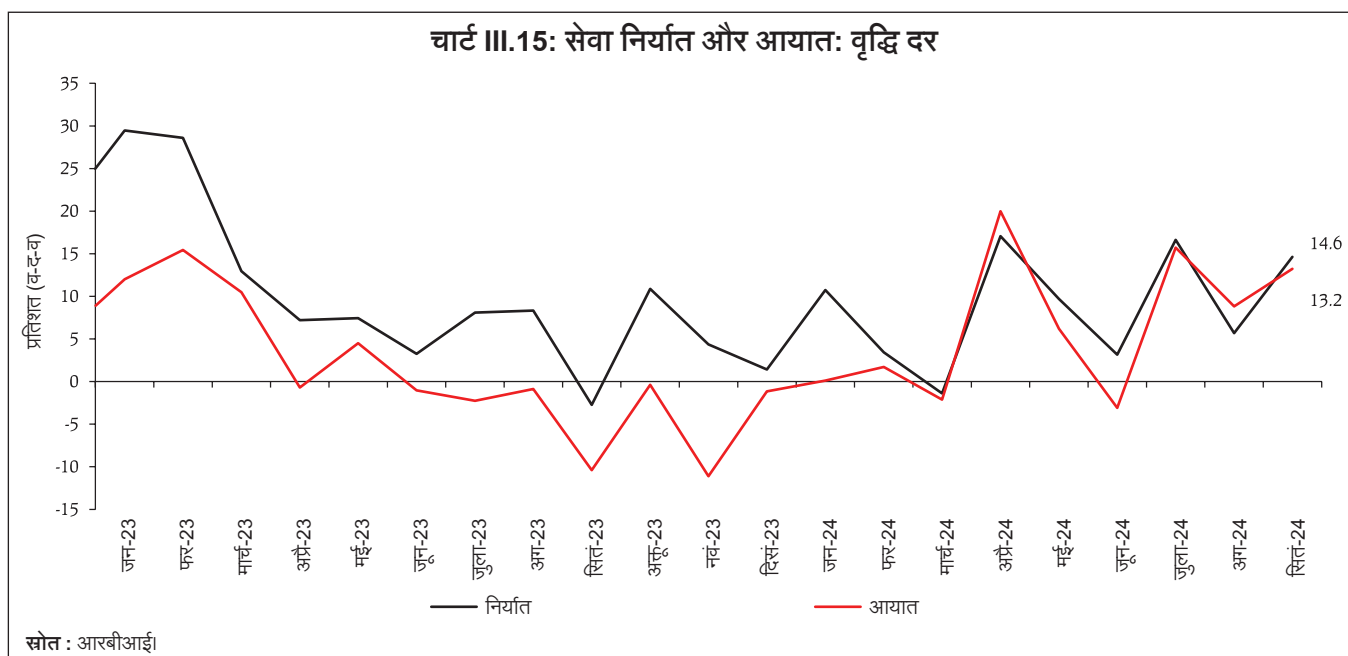


अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान, भारत का पण्य व्यापार घाटा एक वर्ष पहले के 149.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 164.7 बिलियन हो गया। घाटे का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम उत्पाद थे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान थे (चार्ट III.14)।

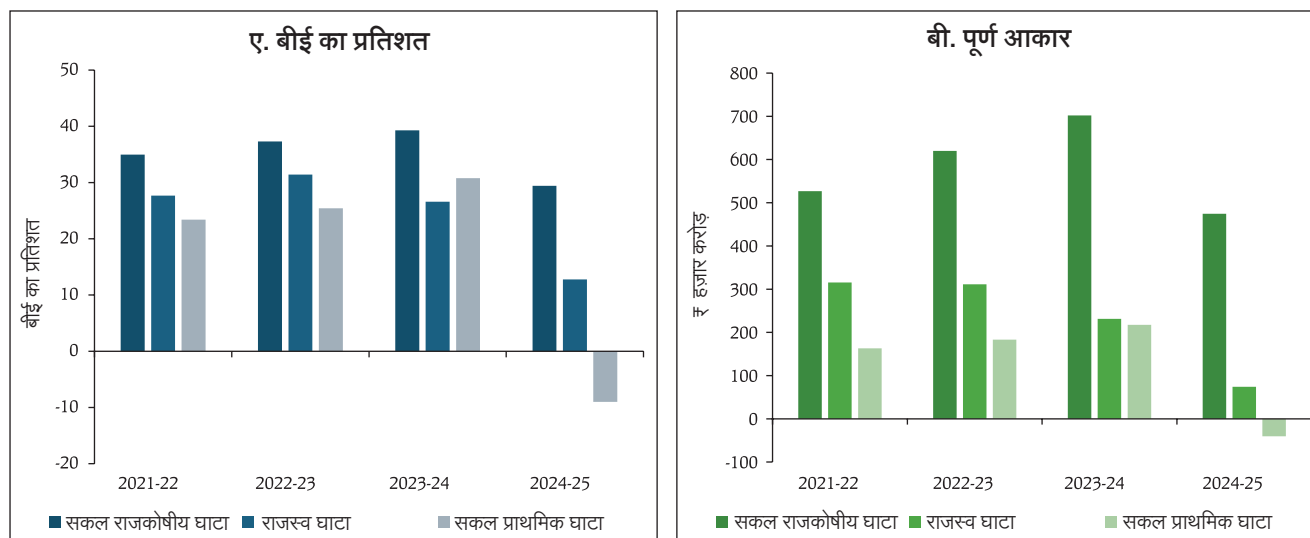
सितंबर 2024 के दौरान सेवा निर्यात 14.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 32.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि

सेवाओं का आयात 13.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.15)। इससे निवल सेवा निर्यात आय में 16.1 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई और यह इस माह के उच्चतम स्तर 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई। अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान, भारत की निवल सेवा निर्यात आय एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान 75.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 84.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

केंद्र सरकार के सभी प्रमुख प्रमुख घाटे के संकेतक, अर्थात्, सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), राजस्व घाटा (आरडी), और प्राथमिक घाटे (पीडी) ने 2024-25 की पहली छमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि (यानी, 2023-24 की पहली छमाही) की तुलना में सुधार दर्ज किया [दोनों निरपेक्ष रूप से और साथ ही बजट अनुमानों (बीई) का प्रतिशत]। जीएफडी 2024-25 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 29.4 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 39.3 प्रतिशत था (चार्ट III.16ए और 16बी)। 2024-25 की पहली छमाही के दौरान यह सुधार राजस्व प्राप्ति में मजबूत वृद्धि के कारण दर्ज किया गया। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का कुल व्यय (लगभग ₹21.1 लाख करोड़) पिछले वर्ष की इसी अवधि के सापेक्ष सामान्य रहा।



चार्ट III.16: बजटीय घाटा (अप्रैल-सितंबर)



स्रोत : महालेखा नियंत्रक (सीजीए); तथा केंद्रीय बजट दस्तावेज।

2024-25 की पहली छमाही के दौरान राजस्व व्यय वृद्धि घटकर 4.2 प्रतिशत हो गई, जो 2023-24 की पहली छमाही में दर्ज 10.0 प्रतिशत थी, जबकि पूंजीगत व्यय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी। पूंजीगत व्यय में संकुचन को आंशिक रूप से 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान आम चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के साथ-साथ जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान भारी मानसून की बारिश के प्रभाव के कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान, हालांकि, पूंजीगत व्यय में 10.3 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ उछाल आया। प्रमुख सब्सिडी (खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम) पर व्यय में 2024-25 की पहली छमाही में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो खाद्य सब्सिडी व्यय में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित है, जबकि आंशिक रूप से अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों में गिरावट के कारण उर्वरक सब्सिडी 18.8 प्रतिशत तक संकुचित हुई।

प्राप्तियों के पक्ष में, सकल कर राजस्व में 2024-25 की पहली छमाही के दौरान 12.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह मुख्य रूप से आयकर (25.0 प्रतिशत) और माल और सेवा कर (जीएसटी) [10.4 प्रतिशत] में मजबूत वृद्धि से प्रेरित था। इसी प्रकार, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रह

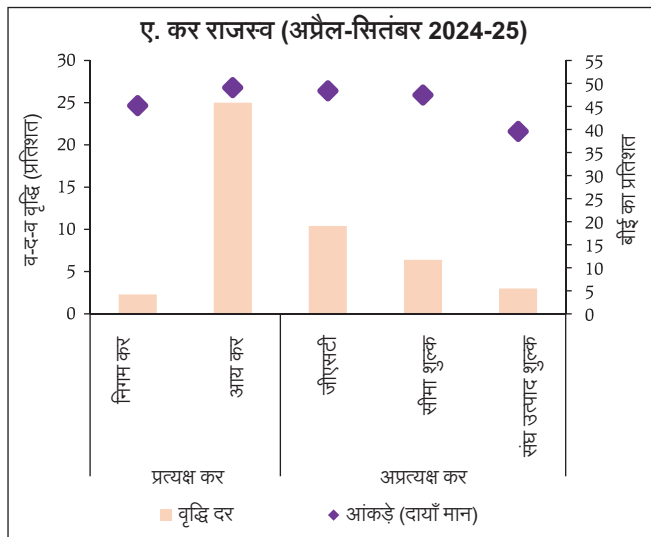
जैसे अप्रत्यक्ष करों में भी उच्च वृद्धि देखी गई (चार्ट III.17ए)। रिजर्व बैंक द्वारा ₹2.1 लाख करोड़ के उच्च अधिशेष अंतरण के कारण गैर-कर राजस्व में 50.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.17बी)। विनिवेश प्राप्तियों और ऋणों की वसूली में गिरावट के कारण गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में वार्षिक आधार पर 27.6 प्रतिशत की गिरावट आई। कुल मिलाकर, कुल प्राप्तियों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2024-25 की पहली छमाही में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

अक्टूबर 2024 के माह के लिए सकल जीएसटी संग्रह (केंद्र संग राज्य) 1.87 लाख करोड़ रुपये (अप्रैल 2024 के बाद दूसरा सबसे अधिक मासिक संग्रह) था, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.18)। रिफंड के लिए लेखांकन के बाद, सितंबर 2024 के लिए निवल जीएसटी संग्रह ₹1.68 लाख करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.9 प्रतिशत बढ़ रहा था। अप्रैल-अक्टूबर 2024 के लिए संचयी सकल जीएसटी संग्रह 12.7 लाख करोड़ रुपये (अप्रैल-अक्टूबर 2023 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ) रहा।

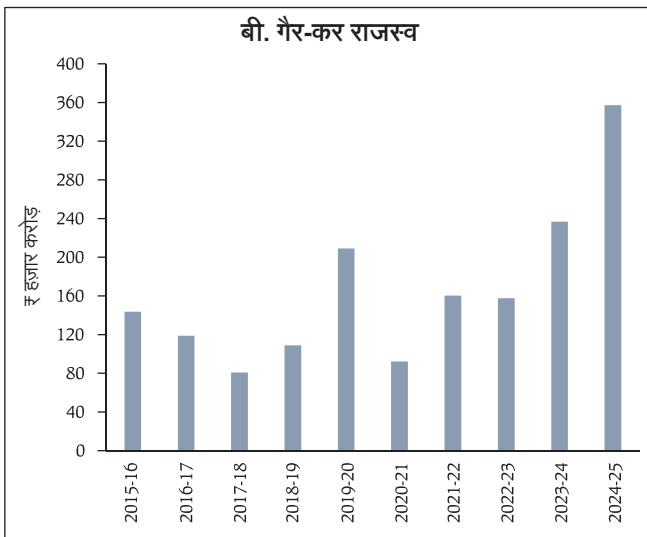
राज्यों का जीएफडी 2024-25 की पहली छमाही के दौरान बजट अनुमानों का 43.9 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष के स्तर से कम है (चार्ट III.19)¹⁵

¹⁵ आंकड़े 22 राज्यों से संबंधित हैं।

चार्ट III.17: केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति (अप्रैल-सितंबर)



स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

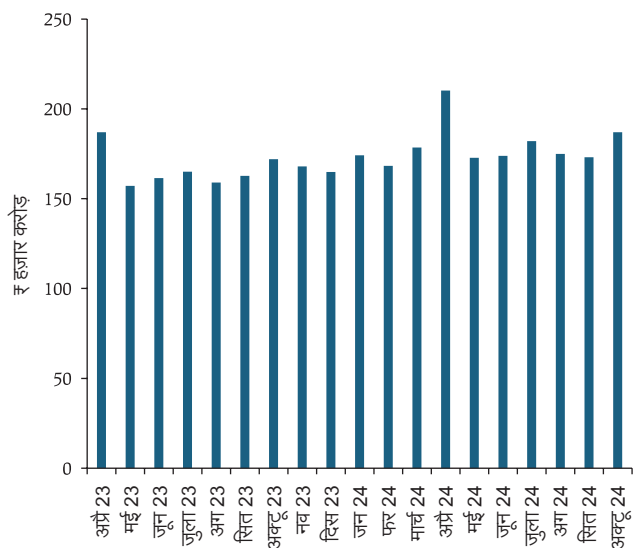


कर राजस्व में दोहरे अंकों की वृद्धि से प्रेरित राजस्व प्राप्ति में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि केंद्र सरकार से गैर-कर राजस्व और अनुदान संकुचित हुए (चार्ट III.20ए)। इस अवधि के दौरान राज्यों के राजस्व व्यय में तेजी आई, जबकि पूंजीगत व्यय में गिरावट आई (चार्ट III.20बी)। हालांकि, पूंजीगत व्यय ने वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान सुधार के संकेत दिखाए।

सकल आपूर्ति

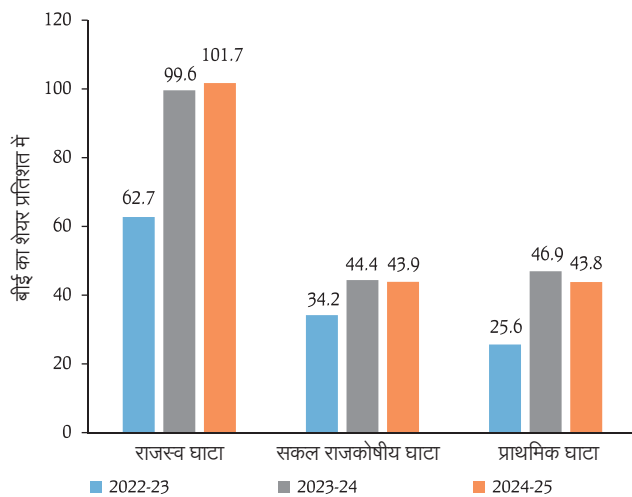
वर्ष 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों (ईई) के अनुसार, खरीफ खाद्यान्न (चावल, मोटे अनाज और दलहन) का उत्पादन रिकॉर्ड 164.7 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 के अंतिम अनुमानों की तुलना में 5.7 प्रतिशत अधिक है, जो इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडबल्यूएम) के मौसम के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा गतिविधि के

चार्ट III.18: मासिक जीएसटी राजस्व



स्रोत: पीआईबी; और जीएसटी पोर्टल।

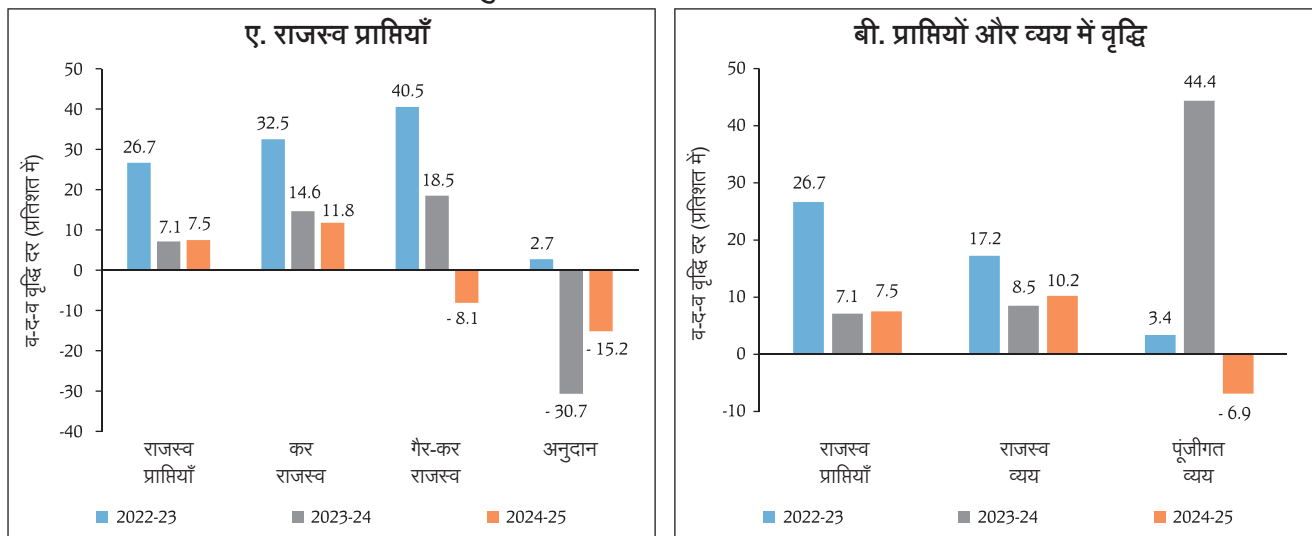
चार्ट III.19: राज्यों के राजकोषीय संकेतक (अप्रैल-सितंबर)



टिप्पणियाँ: डेटा 22 राज्यों से संबंधित है।

स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक।

चार्ट III.20: प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-सितंबर)



टिप्पणी: डेटा 22 राज्यों से संबंधित है।

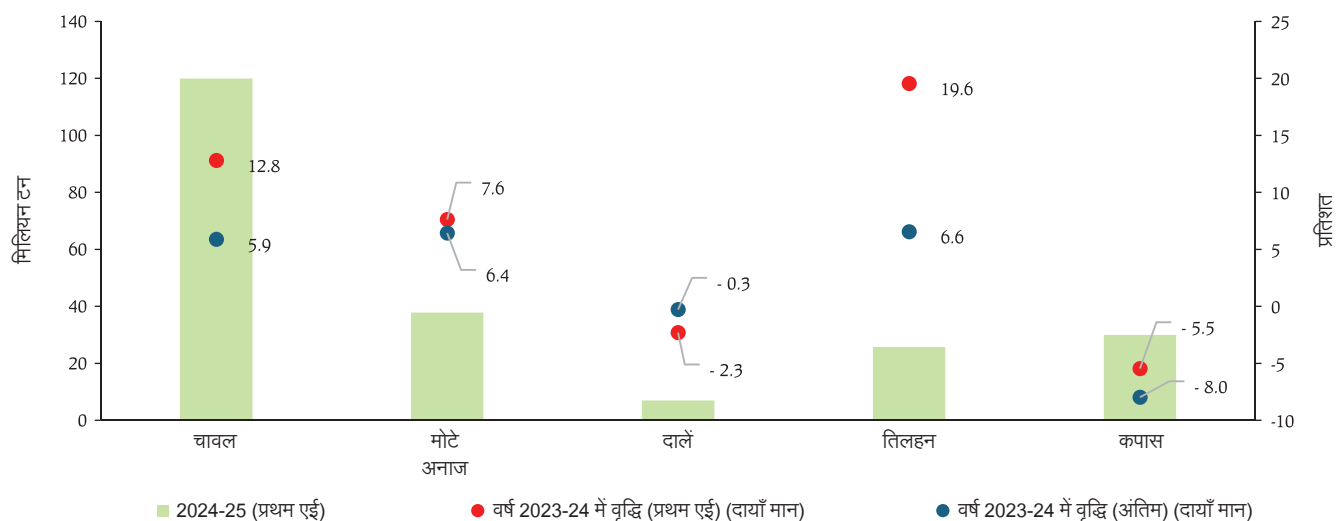
स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षका

सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट III.21)। प्रमुख खरीफ फसलों में चावल, मक्का और मूँगफली के उत्पादन का भी रिकॉर्ड स्तर पर अनुमान लगाया गया है।

एसडबल्यूएम 15 अक्टूबर 2024 को पूरे देश से हट गया, जिसने दक्षिण-पूर्व प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूर्वोत्तर मानसून (एनईएम) वर्षा गतिविधि की एक साथ शुरुआत को भी चिह्नित किया। 01 अक्टूबर-नवम्बर 2017 के दौरान एनईएम की संचयी वर्षा

दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 10 प्रतिशत कम थी जबकि पिछले वर्ष यह एलपीए से 27 प्रतिशत कम थी। 07 नवंबर 2024 तक, अखिल भारतीय औसत जल भंडारण (155 प्रमुख जलाशयों पर आधारित) कुल क्षमता का 86 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष और दशकीय औसत की तुलना में क्रमशः 25.2 प्रतिशत और 16.0 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.22ए)। पर्याप्त बारिश और जलाशयों के स्तर से रबी उत्पादन की संभावनाएं मजबूत होती दिख रही हैं।

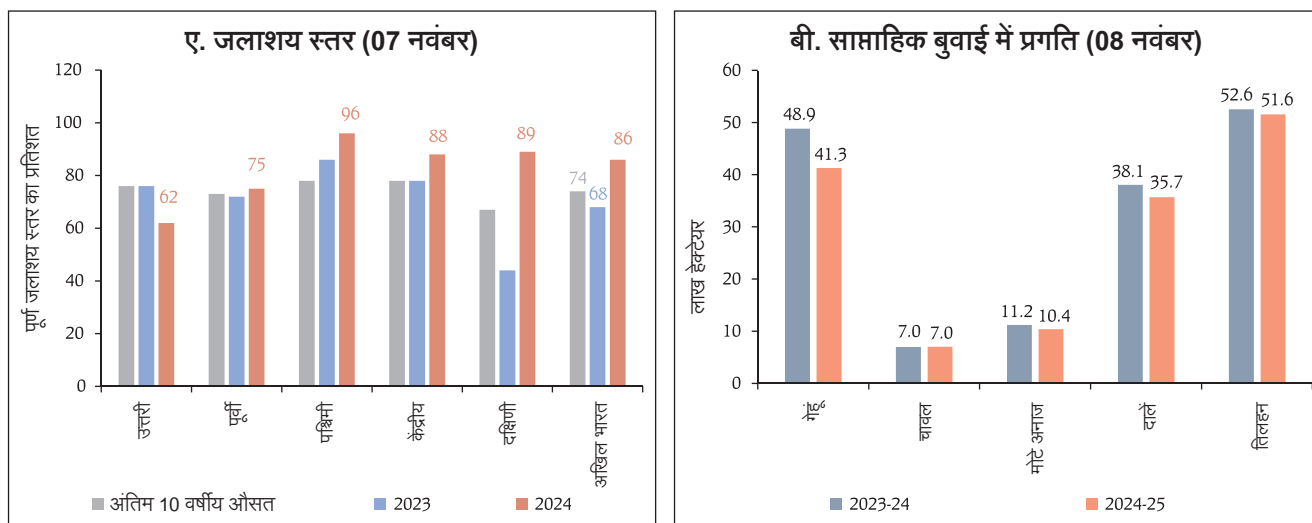
चार्ट III.21 खरीफ उत्पादन



टिप्पणी: कपास को प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन गांठों के रूप में मापा जाता है।

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

चार्ट III.22: रबी सीजन के लिए परिदृश्य



स्रोत: केंद्रीय जल आयोग

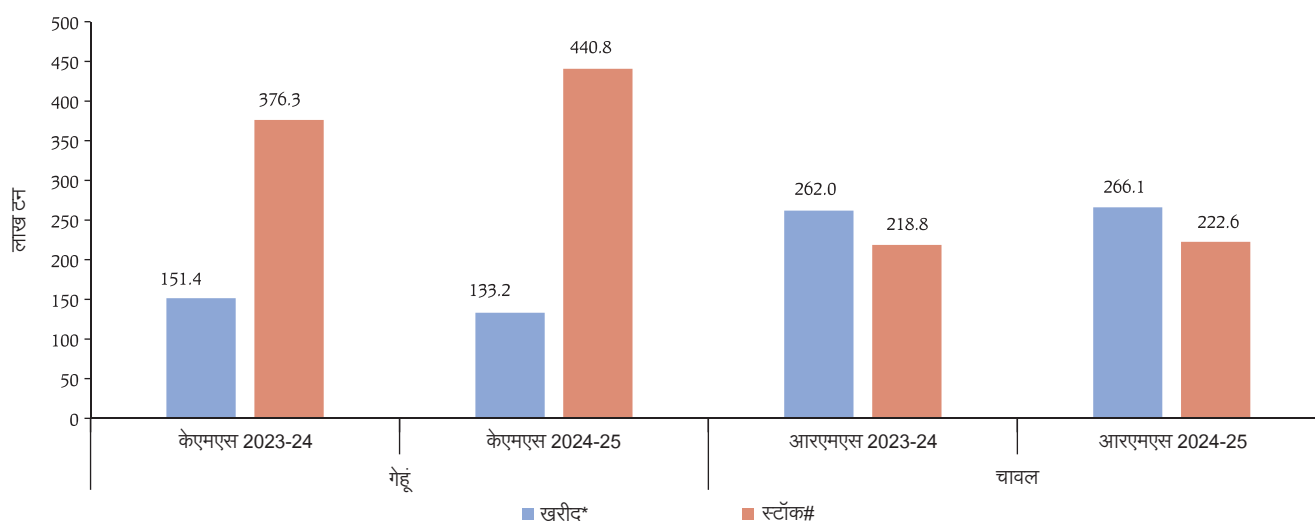
स्रोत: https://agriwelfare.gov.in/Documents/CWWGDATA/mom21_0.doc

08 नवंबर 2024 तक कुल रबी बुवाई क्षेत्र 146.1 लाख हेक्टेयर (पूर्ण मौसम सामान्य क्षेत्र का 23.0 प्रतिशत) था, जो पिछले वर्ष के इसी सप्ताह के दौरान बोए गए 157.7 लाख हेक्टेयर से कम था (चार्ट III.22बी)।

खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) वर्ष 2024-25 के लिए चावल की खरीद 30 सितंबर 2024 को शुरू हुई। 12 नवंबर

तक, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 151.4 लाख टन की तुलना में 133.2 लाख टन था (चार्ट III.23)। चावल का बफर स्टॉक¹⁶ 01 नवंबर 2024 तक 440.8 लाख टन (मानक का 4.3 गुना) था, जबकि गेहूं का स्टॉक 222.6 लाख टन (मानक का 1.1 गुना) रहा।

चार्ट III.23: केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली: खरीद और स्टॉक

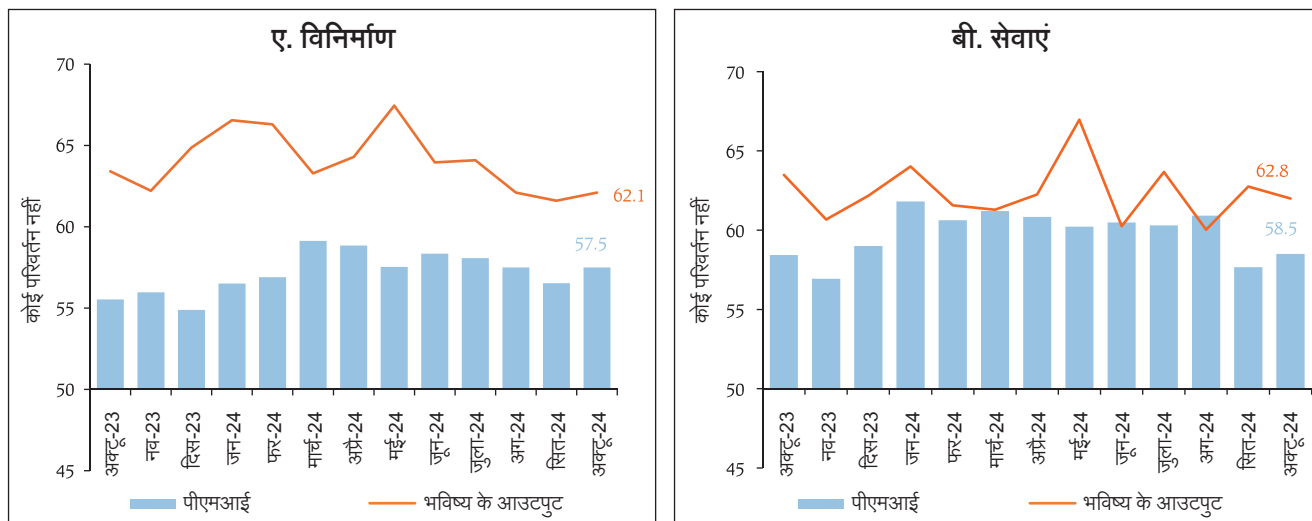


टिप्पणी: *: 12 नवंबर तक; #: 01 नवंबर तक।

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम

¹⁶ जिसमें अनमिल्ड धान समकक्ष भी शामिल है।

चार्ट III.24: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)



टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने के अनुरूप है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

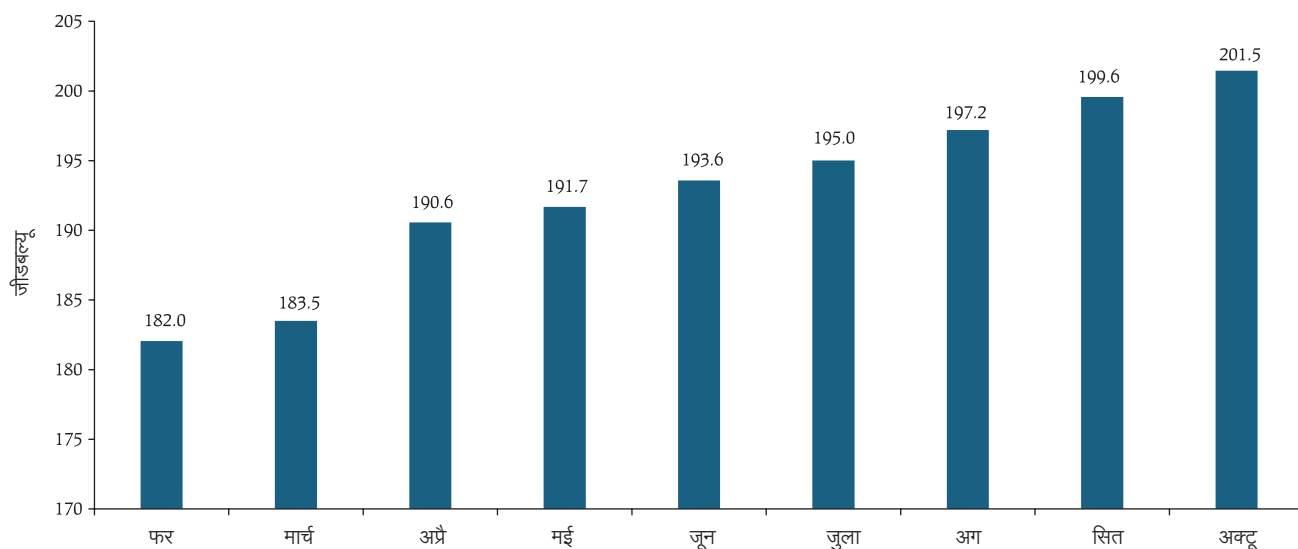
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

ऑर्डर, रोजगार और नए आउटपुट में वृद्धि के कारण अक्टूबर 2024 में भारत का विनिर्माण पीएमआई तेज हुआ (चार्ट III.24ए)। सेवा पीएमआई भी अक्टूबर 2024 में बढ़कर 58.5 हो गया, जो सितंबर में 10 महीने के निचले स्तर 57.7 पर था, जो मजबूत मांग की स्थिति से प्रेरित था (चार्ट III.24बी)। विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक अपेक्षाओं में सुधार प्रदर्शित

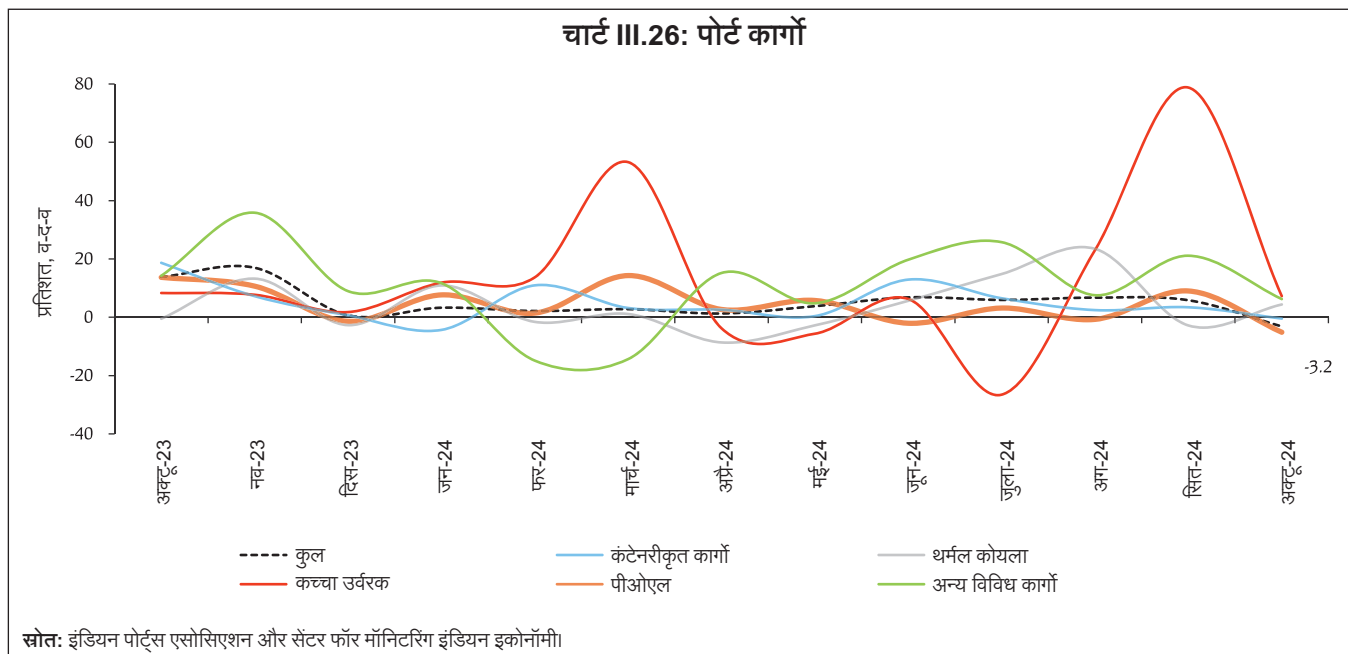
हुआ, जबकि भविष्य की व्यावसायिक गतिविधि सेवाओं में कमी हुई।

स्वच्छ ऊर्जा संचरण की दिशा में भारत की प्रगति ने अक्टूबर 2024 में अक्षय उत्पादन क्षमता 200 गीगावाट (जीडबल्यू) को पार करने के साथ एक उपलब्धि हासिल की, जो कुल स्थापित क्षमता का 46.3 प्रतिशत है (चार्ट III.25)।

चार्ट III.25: नवीकरणीय स्थापित क्षमता



स्रोत: नीति आयोग डैशबोर्ड

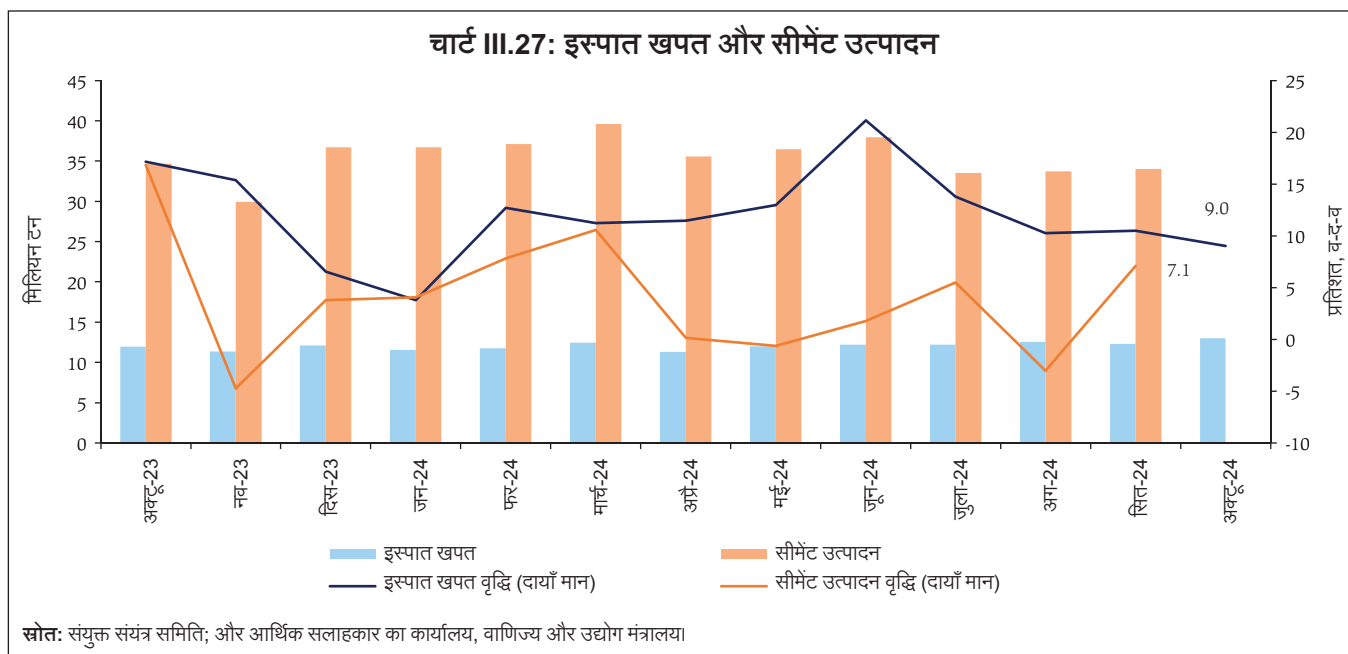


जैसा कि परिचयात्मक खंड में वर्णित है, हाल के वर्षों में सौर और पवन क्षमता परिवर्धन के कारण, भारत अक्षय क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। चार राज्यों, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक ने भारत में अक्षय क्षमता का लगभग आधा हिस्सा लिया।

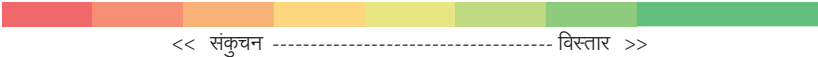
अक्टूबर 2024 में पोर्ट ट्रैफिक संकुचित हुआ, जो पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक द्वारा संचालित था (चार्ट III.26)।

अक्टूबर में इस्पात की खपत में 9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि और सितंबर 2024 में सीमेंट उत्पादन में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निर्माण क्षेत्र ने गति पकड़ी (चार्ट III.27)।

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक सितंबर/अक्टूबर 2024 में आर्थिक गतिविधि में कर्षण को दर्शाते हैं। त्योहारी सीजन और एसडब्ल्यूएम की मंदी के कारण, लॉजिस्टिक्स गतिविधि में वृद्धि हुई जैसा कि ई-वे बिल और



सारणी III.2 : उच्च आवृत्ति संकेतक - सेवाएं														
		वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)												
क्षेत्र	संकेतक	अक्टू- 23	नव- 23	दिस- 23	जन- 24	फर- 24	मार्च- 24	अप्रै- 24	मई -24	जून- 24	जुल- 24	अग- 24	सित- 24	अक्टू- 24
शहरी मांग	यात्री वाहनों की बिक्री	33.9	21.0	21.7	31.9	27.0	26.0	1.3	4.0	3.1	-2.5	-1.8	-1.4	0.9
ग्रामीण मांग	दोपहिया वाहनों की बिक्री	20.1	31.3	16.0	26.2	34.6	15.3	30.8	10.1	21.3	12.5	9.3	15.8	14.2
	तिपहिया वाहनों की बिक्री	42.1	30.8	30.6	9.5	8.3	4.3	14.5	14.4	12.3	5.1	8.0	7.1	-0.2
	ट्रैक्टर की बिक्री	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-30.6	-23.1	-3.0	0.0	3.6	1.6	-5.8	3.7	22.4
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	3.2			-3.8			3.5			-11.0			
	रेलवे मालभाड़ा यातायात	8.5	4.3	6.4	6.4	10.1	8.6	1.4	3.7	10.1	4.5	0.0		
	पोर्ट कार्गो यातायात	13.8	16.9	0.6	3.2	2.1	2.7	1.3	3.8	6.8	5.9	6.7	5.8	-3.2
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात *	10.6	9.0	8.7	10.0	11.5	8.7	0.3	10.3	10.3	8.8	0.6	14.0	-13.7
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात *	15.0	4.9	12.2	19.3	30.2	22.5	16.2	19.2	19.6	24.4	20.7	20.5	-0.2
	घरेलू हवाई यात्री यातायात *	10.7	8.7	8.1	5.0	5.8	4.7	3.8	5.9	6.9	7.6	6.7	7.4	10.0
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात *	17.5	19.8	18.1	17.0	19.3	15.0	16.8	19.6	11.3	8.8	11.1	11.2	9.3
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	30.5	8.5	13.2	16.4	18.9	13.9	14.5	17.0	16.3	19.2	12.9	18.5	16.9
	जीएसटी ई-वे बिल (आंतर राज्यीय)	30.0	22.7	14.2	17.9	21.1	15.8	17.3	18.9	16.4	19.0	13.1	19.0	18.3
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	31.2	-16.2	11.4	13.8	15.0	10.7	9.6	13.6	16.3	19.6	12.5	17.7	14.4
	होटल अधिवास	9.3	-8.6	1.6	2.6	1.8	2.7	-1.4	-2.6	-3.1	3.6	0.7		
	प्रति कमरा औसत राजस्व	14.8	15.9	12.8	11.0	4.1	6.7	4.8	1.8	2.8	7.6	5.2		
	पर्यटकों का आगमन	19.8	16.8	7.8	10.4	15.8	8.0	7.7	0.3	9.0	-1.3			
निर्माण	इस्पात की खपत	15.3	14.5	13.7	12.3	7.0	12.5	11.5	13.0	21.1	13.8	10.3	10.5	9.0
	सीमेंट उत्पादन	17.0	-4.8	3.8	4.0	7.8	10.6	0.2	-0.6	1.9	5.5	-3.0	7.1	
पीएमआई सूचकांक #	सेवाएं	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6	61.2	60.8	60.2	60.5	60.3	60.9	57.7	58.5



टिप्पणी: #: डेटा स्तरों में है।
*: अक्टूबर 2024 का डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत के आधार पर है। जुलाई 2021 से अब तक के लिए प्रत्येक संकेतक का हीट-मैप बनाया गया है।
स्रोत: एसआईएम; रेल मंत्रालय; ट्रैक्टर और मशीनीकरण संघ; भारतीय पोर्ट संघ; वित्तीय सलाहकार का कार्यालय; जीएसटीएन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; एचवीएस एनरॉक; पर्यटन मंत्रालय; संयुक्त संयंत्र समिति; और आईएसएस मार्किट।

टोल संग्रह में परिलक्षित होता है। निर्माण ने भी गति पकड़ी जैसा कि इस्पात की खपत और सीमेंट की मांग में देखा गया है (सारणी III.1)

मुद्रास्फीति

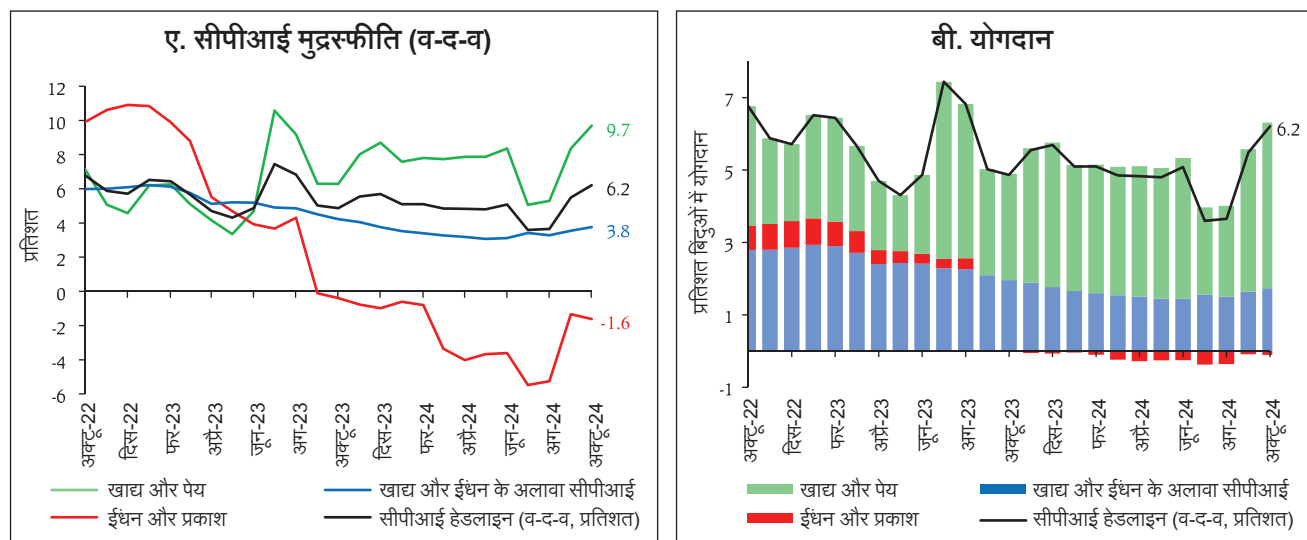
अखिल भारतीय सीपीआई¹⁷ में वर्षानुवर्ष परिवर्तनों द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति सितंबर 2024 में 5.5 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.28)। लगभग 70 आधार अंकों (बीपीएस) की मुद्रास्फीति में वृद्धि लगभग 135 बीपीएस की सकारात्मक गति से हुई, जिसे 65

आधार अंकों के अनुकूल आधार प्रभाव द्वारा आंशिक रूप से संतुलित किया गया था। सीपीआई खाद्य और सीपीआई कोर (यानी, सीपीआई खाद्य और ईंधन को छोड़कर) समूहों ने क्रमशः 2.2 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत की म-द-म वृद्धि दर्ज की, जबकि सीपीआई ईंधन सूचकांक अपरिवर्तित रहा।

अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर में 8.4 प्रतिशत थी। उप-समूहों के संदर्भ में, सब्जियों और खाद्य तेलों ने म-द-म और व-द-व दोनों आधार पर महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.29)। फलों, अनाजों और उत्पादों, मांस और मछली, गैर-मादक पेय पदार्थों

¹⁷ एनएसओ द्वारा 12 नवंबर 2024 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट III.28: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और वाहक

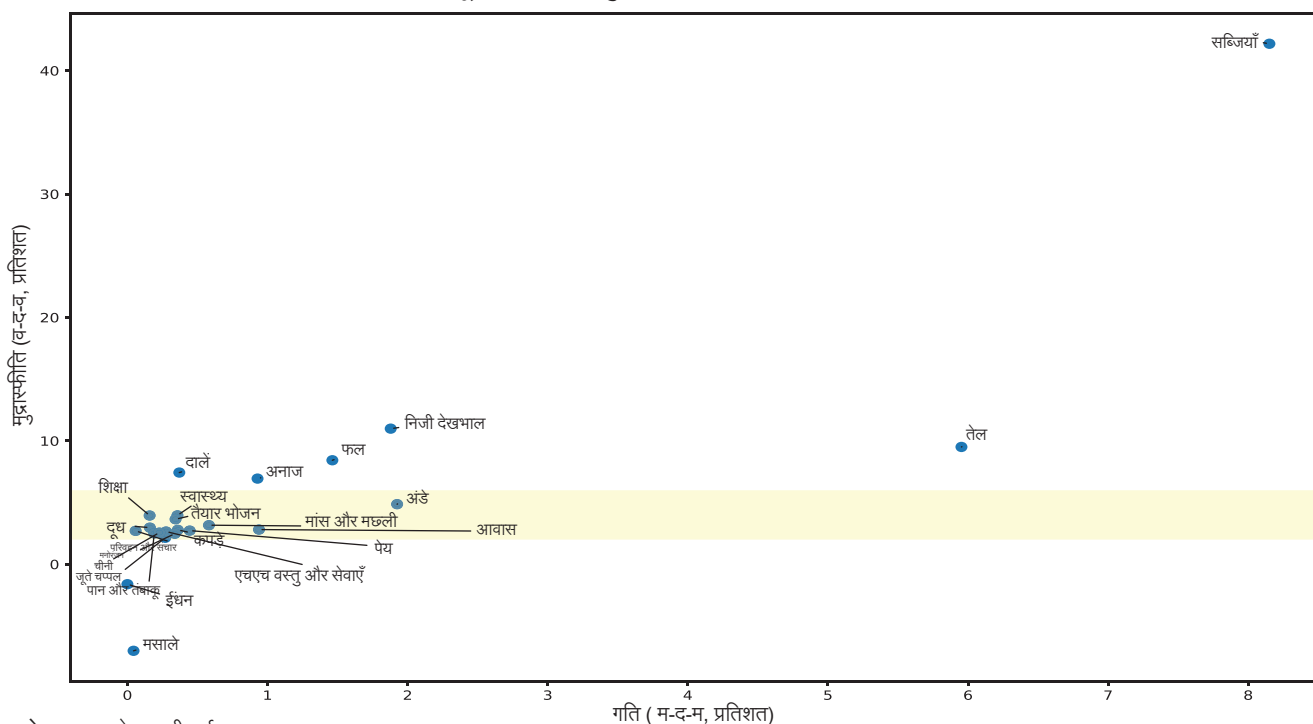


स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

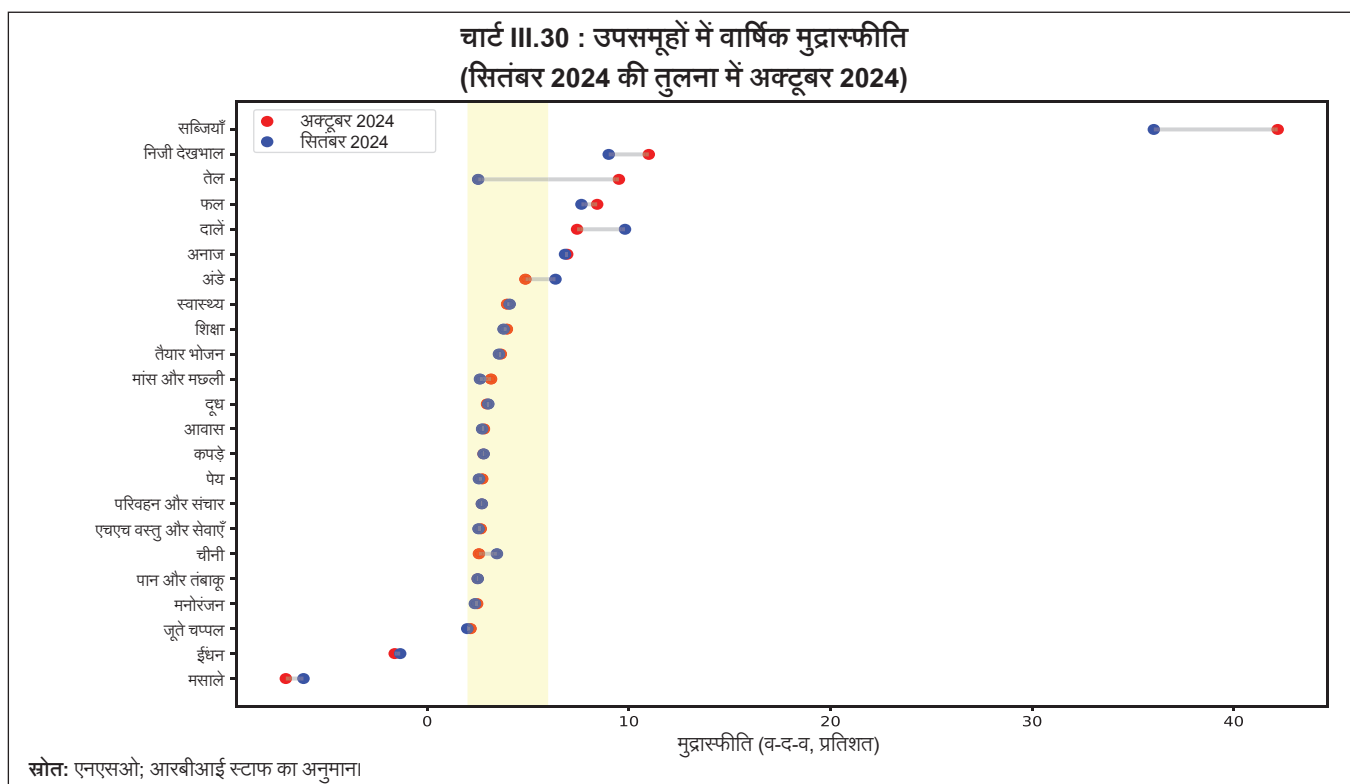
और तैयार भोजन के संबंध में कीमतें बढ़ीं, जबकि वे दालों और उत्पादों, अंडे और चीनी में सामान्य रहीं (चार्ट III.30)। दूध और उससे बने उत्पादों की मुद्रास्फीति में कोई बदलाव नहीं हुआ जबकि मसालों की कीमतों में गिरावट आई।

केरोसिन में अपस्फीति बढ़ने से ईंधन व प्रकाश अवस्फीति अक्टूबर में बढ़कर शून्य से 1.6 प्रतिशत नीचे हो गई, जो सितंबर में शून्य से 1.4 प्रतिशत नीचे थी। दूसरी ओर, विद्युत, और जलाऊ लकड़ी और चिप्स की कीमतों में

चार्ट III.29: उपसमूहों में वार्षिक मूद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) और गति (एम-ओ-एम)



स्रोत: एनएसओ; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।



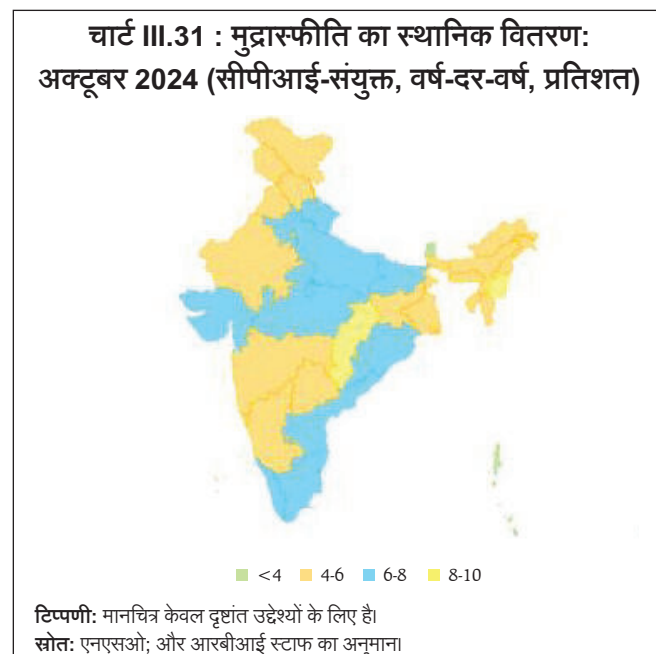
मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई। एलपीजी मूल्य मुद्रास्फीति स्थिर रही।

अक्टूबर में कोर मुद्रास्फीति बढ़कर 3.8 फीसदी हो गई, जो सितंबर में 3.6 फीसदी थी। जबकि मुद्रास्फीति उप-समूहों जैसे कपड़े और जूते, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, और परिवहन और संचार के लिए स्थिर रही, यह खेल-कूद और मनोरंजन, आवास, घरेलू सामान और सेवाओं, शिक्षा और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों के संबंध में बढ़ी। स्वास्थ्य उप-समूह की कीमतों में मुद्रास्फीति में कमी दर्ज की गई।

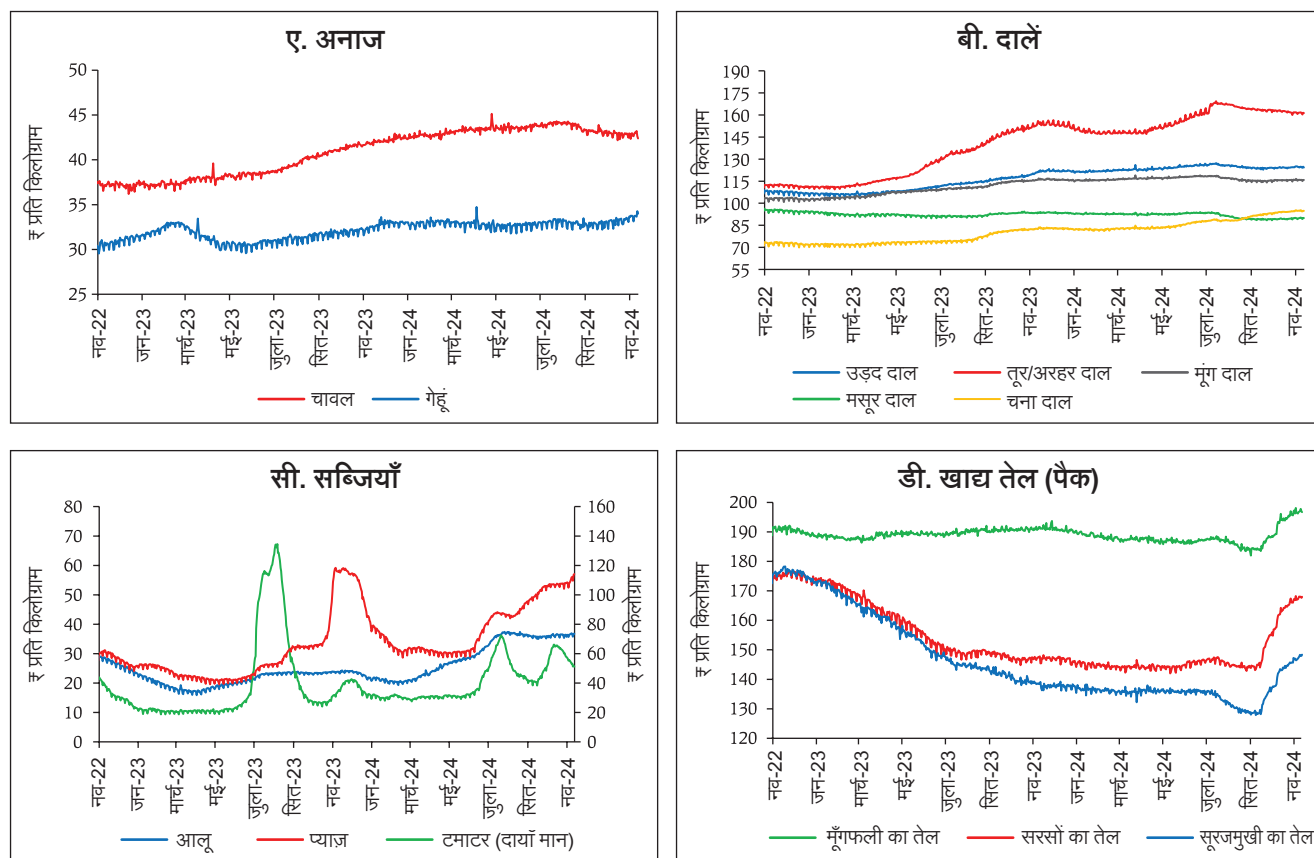
क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, अक्टूबर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जिसमें ग्रामीण मुद्रास्फीति 6.7 प्रतिशत थी, जो शहरी मुद्रास्फीति से 5.6 प्रतिशत से अधिक थी। अधिकांश राज्यों ने मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम दर्ज की (चार्ट III.31)।

नवंबर के लिए अब तक (12 तारीख तक) खाद्य मूल्य के उच्च आवृत्ति के आंकड़े अनाज में वृद्धि (मुख्य रूप से गेहूं और

आटे द्वारा संचालित) और खाद्य तेल की कीमतों में व्यापक दबाव दिखाते हैं। दालों की कीमतों में भी तेजी देखी गई (तुअर को छोड़कर)। प्रमुख सब्जियों में, आलू और प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई, जबकि टमाटर की कीमतों में तेजी से कमी दर्ज की गई (चार्ट III.32)।



चार्ट III.32: डीसीए आवश्यक कमोडिटी की कीमतें



स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य नवंबर में अब तक (12 तारीख तक) मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहे। जबकि मिट्टी के तेल की कीमतों में दो महीने की कमी के बाद वृद्धि हुई, एलपीजी की कीमतों को अपरिवर्तित रखा गया (सारणी III.2)।

अक्टूबर 2024 के लिए पीएमआई ने विनिर्माण और सेवा फर्मों में इनपुट लागत में विस्तार की दर में और वृद्धि का संकेत दिया। पिछले दो महीनों में विस्तार की दर में मंदी के बाद, विनिर्माण और सेवा फर्मों में बिक्री मूल्य दबाव भी बढ़ गए (चार्ट III.33)।

सारणी III.2: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

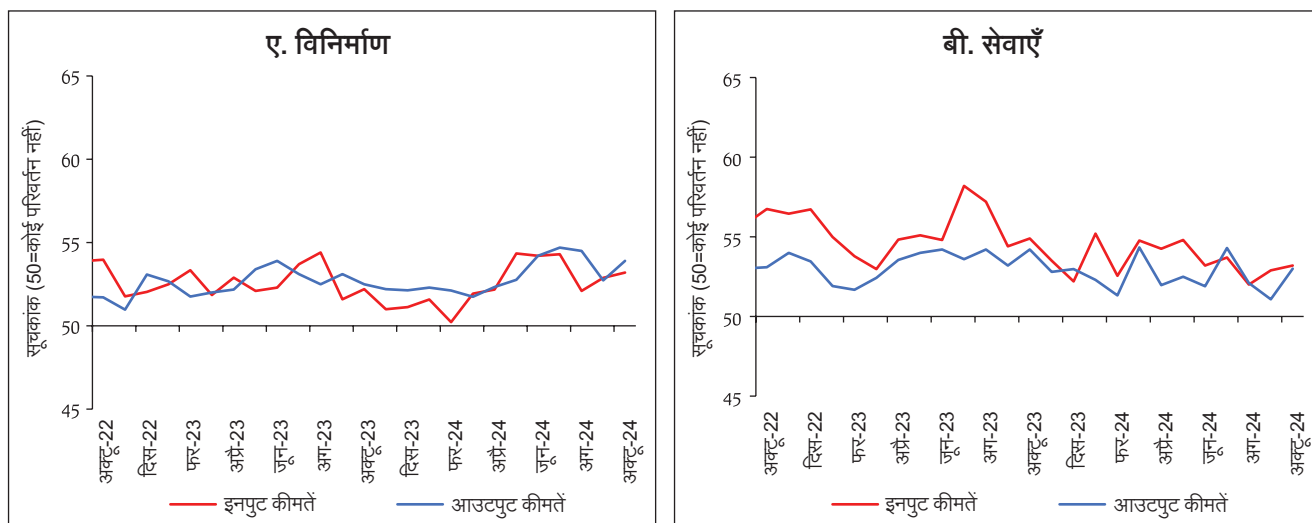
मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		नव-23	अक्तू-24	नव-24 [^]	अक्तू-24	नव-24 [^]
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	100.97	100.99	0.0	0.0
डीजल	₹/लीटर	92.72	90.42	90.45	0.0	0.0
केरोसिन (सब्सिडी)	₹/लीटर	55.21	42.93	43.95	-6.2	2.4
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	913.25	813.25	813.25	0.0	0.0

[^]: 1-12 नवंबर 2024 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.33: पीएमआई इनपुट और आउटपुट कीमतें



टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने के अनुरूप है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

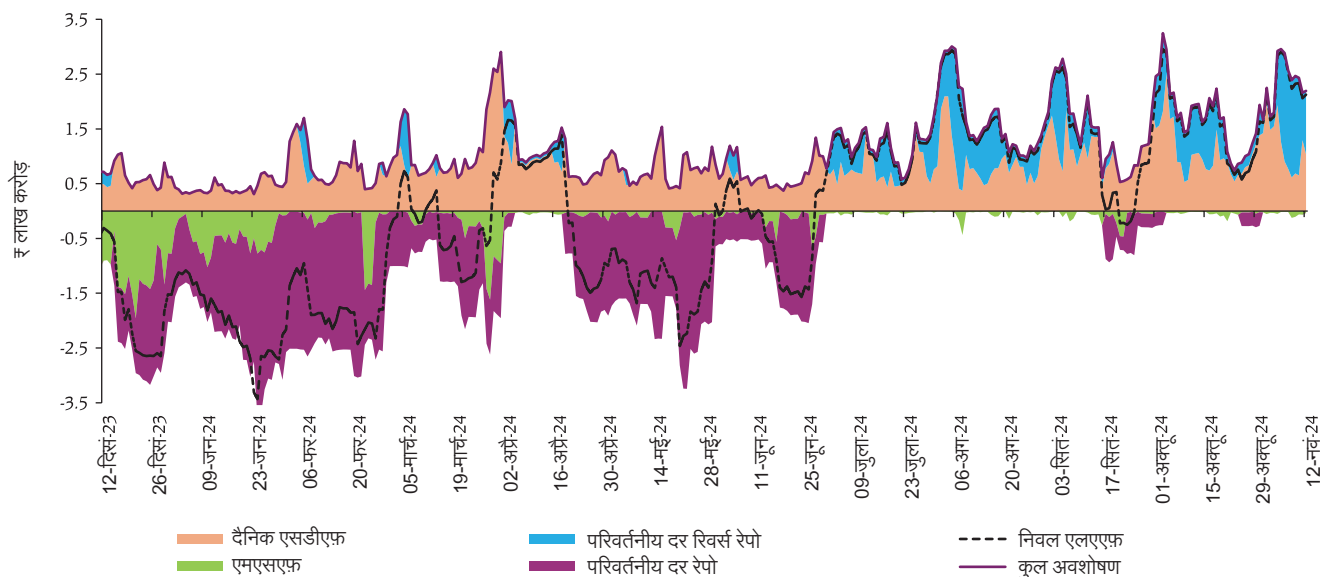
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

उच्च जीएसटी संग्रह¹⁸ और संचलन में मुद्रा में त्योहार संबंधी विस्तार के कारण सरकारी नकद शेष में वृद्धि के साथ अक्टूबर के उत्तरार्ध में व्यवस्था में चलनिधि में कमी आई। सरकारी व्यय ने नवंबर की शुरुआत में चलनिधि की स्थिति को सहज बना दिया। कुल मिलाकर, अक्टूबर की दूसरी छमाही और नवंबर की

शुरुआत के दौरान व्यवस्था चलनिधि अधिशेष में रही, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण 16 अक्टूबर से 18 नवंबर 2024 के दौरान बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 16 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 के दौरान 1.14 लाख करोड़ रुपये था (चार्ट IV.1)। रिजर्व बैंक ने 16 अक्टूबर से 19 नवंबर 2024 के दौरान तीन मुख्य और

चार्ट IV.1: चलनिधि परिचालन



स्रोत: आरबीआई

¹⁸ अक्टूबर 2024 के लिए जीएसटी संग्रह ₹1.87 लाख करोड़ था, जो 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद दूसरा उच्चतम स्तर था।

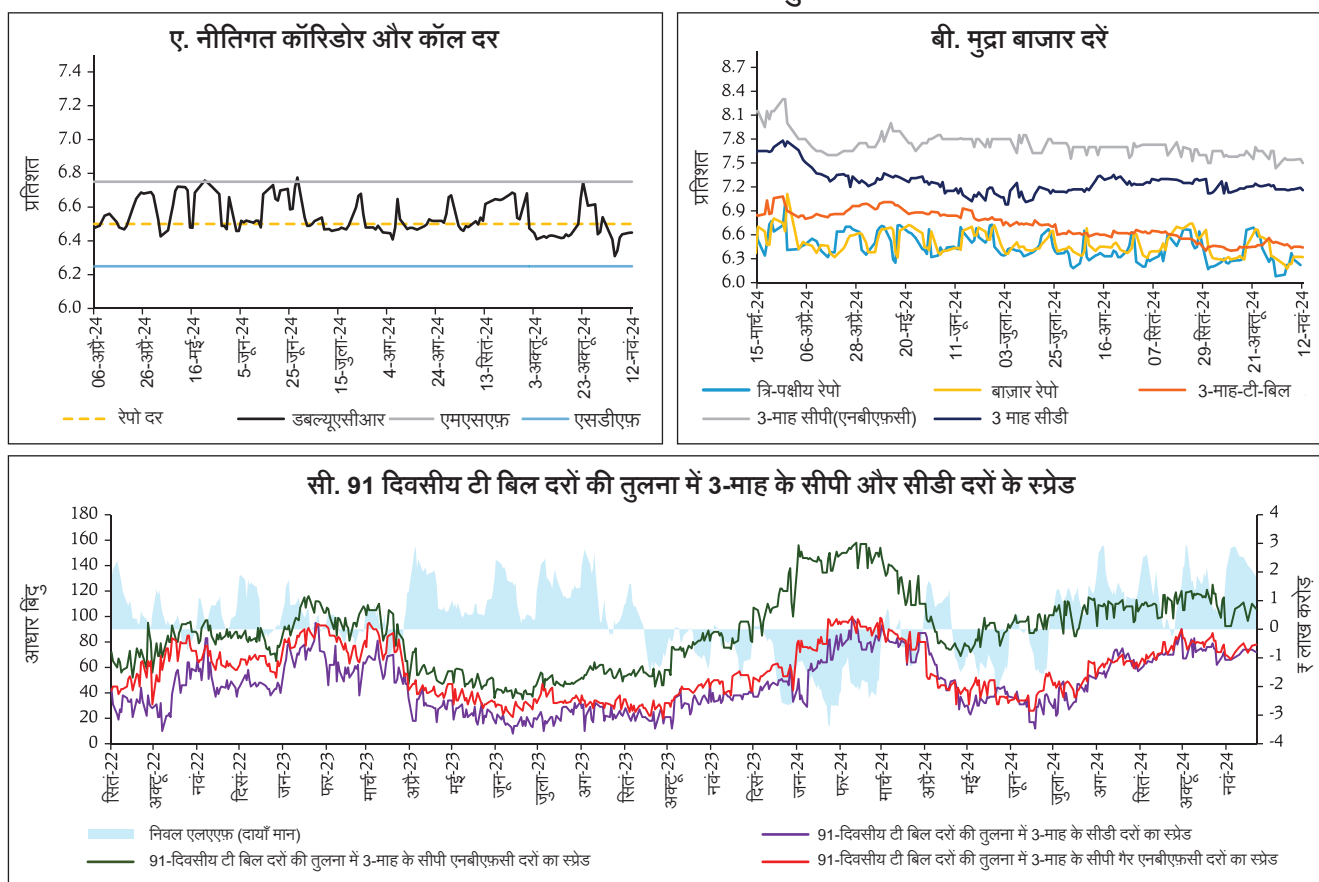
सोलह सही ताल-मेल से परिवर्ती दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) परिचालन किए, जिसमें बैंकिंग प्रणाली से संचयी रूप से 8.38 लाख करोड़ रुपये अवशोषित करने के लिए एकदिवस से 4-दिन तक की परिपक्वता अवधि थी। हालांकि, महीने के अंत में चलनिधि की तंगी को कम करने के लिए, 25 अक्टूबर को 6 दिनों की परिपक्वता वाला एक सही ताल-मेल से परिवर्ती दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) परिचालन आयोजित किया गया।

16 अक्टूबर से 18 नवंबर 2024 के दौरान औसत कुल अवशोषण में से, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत निधियों का निवेश लगभग 61 प्रतिशत था। जैसे-जैसे चलनिधि की स्थिति सहज हुई, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत औसत दैनिक उधारी 16 सितंबर और 15 अक्टूबर 2024 के दौरान ₹0.08 लाख करोड़ से घटकर 16 अक्टूबर से 18 नवंबर 2024 के दौरान ₹0.05 लाख करोड़ रह गई।

एकदिवसीय मुद्रा बाजार में, भारत औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर) एलएएफ कॉरिडोर के भीतर रही, जो 16 अक्टूबर और 18 नवंबर, 2024 के दौरान औसतन 6.48 प्रतिशत रही, जो 16 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2024 के दौरान लगभग समान थी (चार्ट IV.2ए)। हालांकि, डबल्यूएसीआर, अपेक्षाकृत तंग चलनिधि स्थितियों के कारण थोड़े समय (22-28 अक्टूबर) के लिए मजबूत हुई, हालांकि यह नीतिगत कॉरिडोर के भीतर रही। संपार्श्विक खंड में, त्रि-पक्षीय रेपो और बाजार रेपो दरें क्रमशः 15 बीपीएस और 13 बीपीएस औसत रहीं, जो उसी अवधि के दौरान नीतिगत रेपो दर से कम थीं (चार्ट IV.2बी)।

अल्पावधि मुद्रा बाजार खंड में, 3 महीने के खजाना बिल (टी-बिल) पर प्रतिफल 16 अक्टूबर और 18 नवंबर के दौरान मोटे तौर पर स्थिर रहा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3-माह के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और 3

चार्ट IV.2 : नीतिगत कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दरें



स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल; और ब्लूमबर्ग।

महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर दरें कम हुईं (चार्ट IV.2बी)। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3-माह के सीपी और 91-दिवसीय टी-बिल दरों के बीच स्प्रेड) में 4 बीपीएस की गिरावट आई।

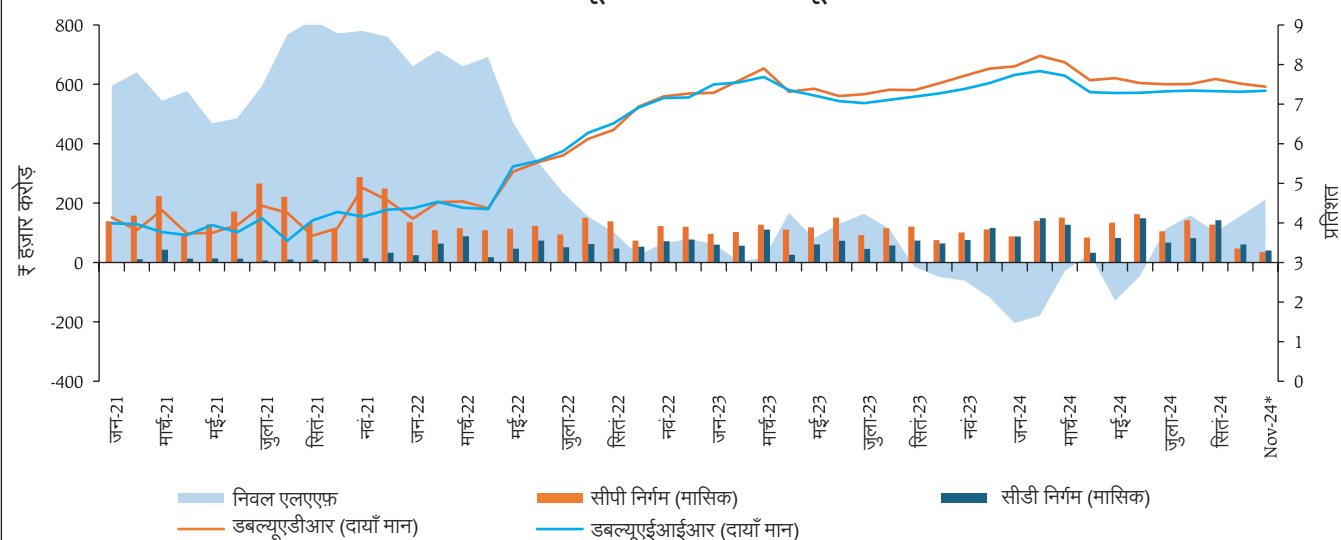
द्वितीयक बाजार में, 91-दिवसीय टी-बिल दर पर 3-माह के सीपी (एनबीएफसी) और सीडी दरों का स्प्रेड नवंबर 2024 (12 नवंबर तक) के दौरान क्रमशः 103 बीपीएस और 71 बीपीएस रहा - जो एक वर्ष पहले 85 बीपीएस और 36 बीपीएस से अधिक था (चार्ट IV.2सी)। हालाँकि अधिशेष चलनिधि की अवधि के दौरान स्प्रेड कम हो जाता है, लेकिन हाल के महीनों में वे मुख्य रूप से 91-दिवसीय टी-बिल दरों में गिरावट के कारण बढ़े हैं।

नवंबर 2024 (12 नवंबर तक) में सीपी की भारित औसत छूट दर (डबल्यूएडीआर) 7.44 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 7.70 प्रतिशत से कम है, क्योंकि एनबीएफसी ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में उच्च वृद्धि की स्थिरता पर चिंताओं और भविष्य में कम ब्याज दरों की अपेक्षाओं के कारण निर्गमों को कम कर दिया (चार्ट IV.3)। ऋण और जमा वृद्धि के बीच अंतर कम होने के कारण सीडी की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डबल्यूईआईआर) एक वर्ष पहले के 7.39 प्रतिशत से कम होकर 7.34 प्रतिशत (12 नवंबर तक) हो गई।

प्राथमिक बाजार में, वर्ष 2024-25 में (1 नवंबर तक) के दौरान सीडी जारी करने की मात्रा 57 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹6.01 लाख करोड़ हो गई, ताकि वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा किया जा सके, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹3.91 लाख करोड़ से काफी अधिक है (चार्ट IV.4)। वर्ष 2024-25 (31 अक्टूबर तक) के दौरान सीपी जारी करने की मात्रा ₹8.70 लाख करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹7.84 लाख करोड़ से अधिक थी। रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाने के साथ, ये संस्थाएं वित्तपोषण में विविधता लाने के लिए वैकल्पिक बाजार लिखतों पर निर्भर हो रही हैं।

10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई, जो अमेरिकी खजाना प्रतिफल में उतार-चढ़ाव और हेडलाइन मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को दर्शाता है (चार्ट IV.5ए)। 16 अक्टूबर - 18 नवंबर के दौरान, औसत अवधि स्प्रेड (10-वर्षीय से 91-दिवसीय टी-बिल घटाकर) 16 सितंबर - 15 अक्टूबर के दौरान 29 बीपीएस से बढ़कर 36 बीपीएस हो गया। जी-सेक प्रतिफल वक्र अवधि संरचना के लघु से मध्यम अवधि में ऊपर की ओर बढ़ा, हालांकि यह बहुत लंबे समय तक मोटे तौर पर स्थिर रहा (चार्ट IV.5बी)।

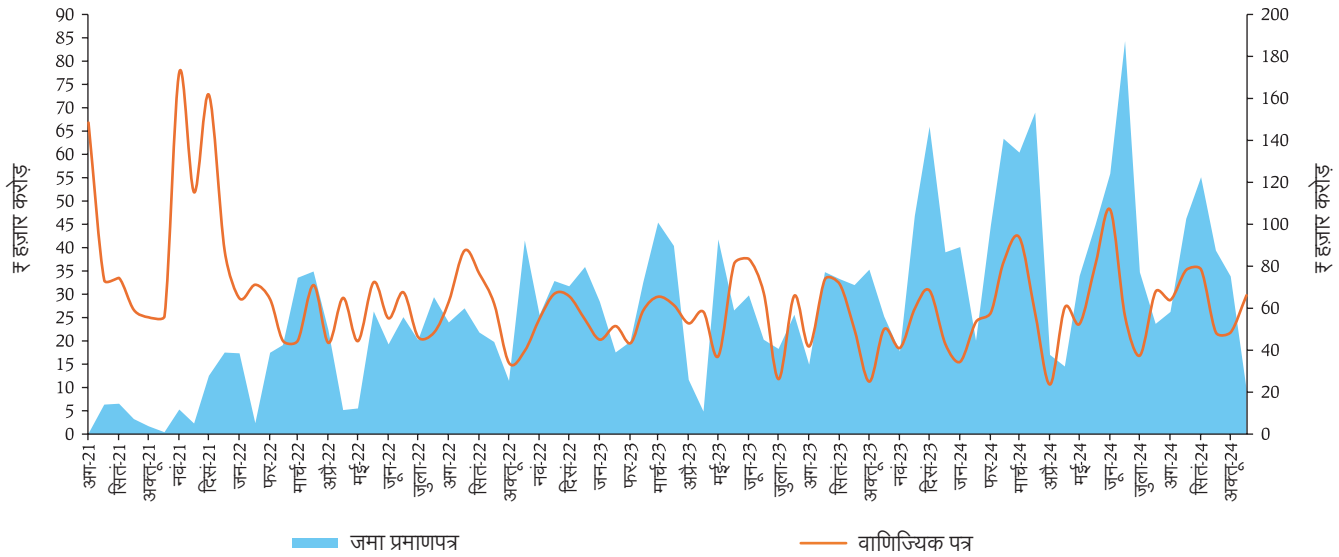
चार्ट IV.3: डबल्यूएडीआर और डबल्यूईआईआर



टिप्पणी: *: 12 नवंबर 2024 तक।

स्रोत: आरबीआई, और सीसीआईएल-एफटीआरएसी।

चार्ट IV.4: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - पाक्षिक निर्गम

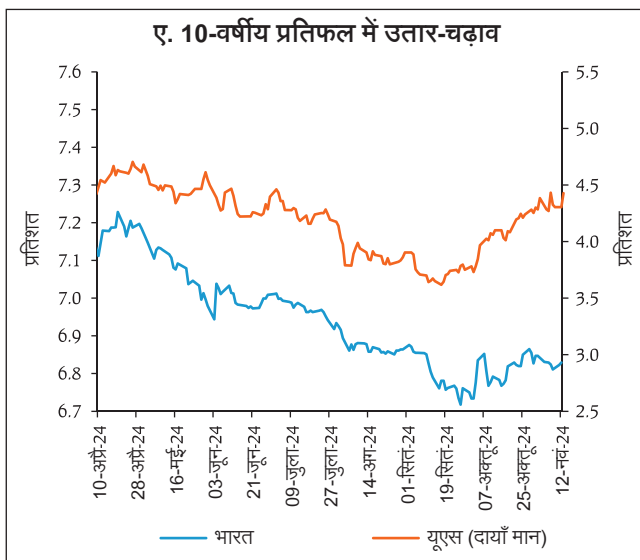


स्रोत: आरबीआई

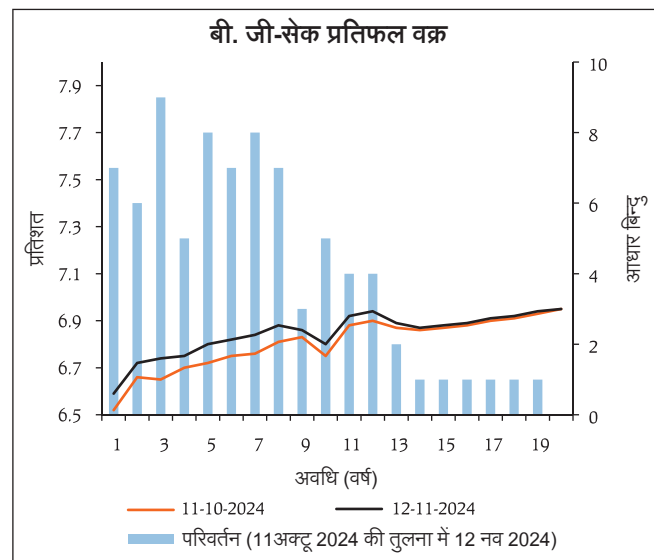
10 वर्षीय भारतीय जी-सेक प्रतिफल का 10 वर्षीय अमेरिकी बॉण्ड पर स्प्रेड 12 नवंबर 2024 को 240 बीपीएस तक गिर गया, जो सितंबर के मध्य में 310 बीपीएस और एक वर्ष पहले 264 बीपीएस था। अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में तेजी भारतीय जी-सेक प्रतिफल की तुलना में बहुत तेज रही है। भारतीय बॉण्ड बाज़ार में प्रतिफल की अस्थिरता भी अमेरिकी खजाना के सापेक्ष कम रही है (चार्ट IV.6)।

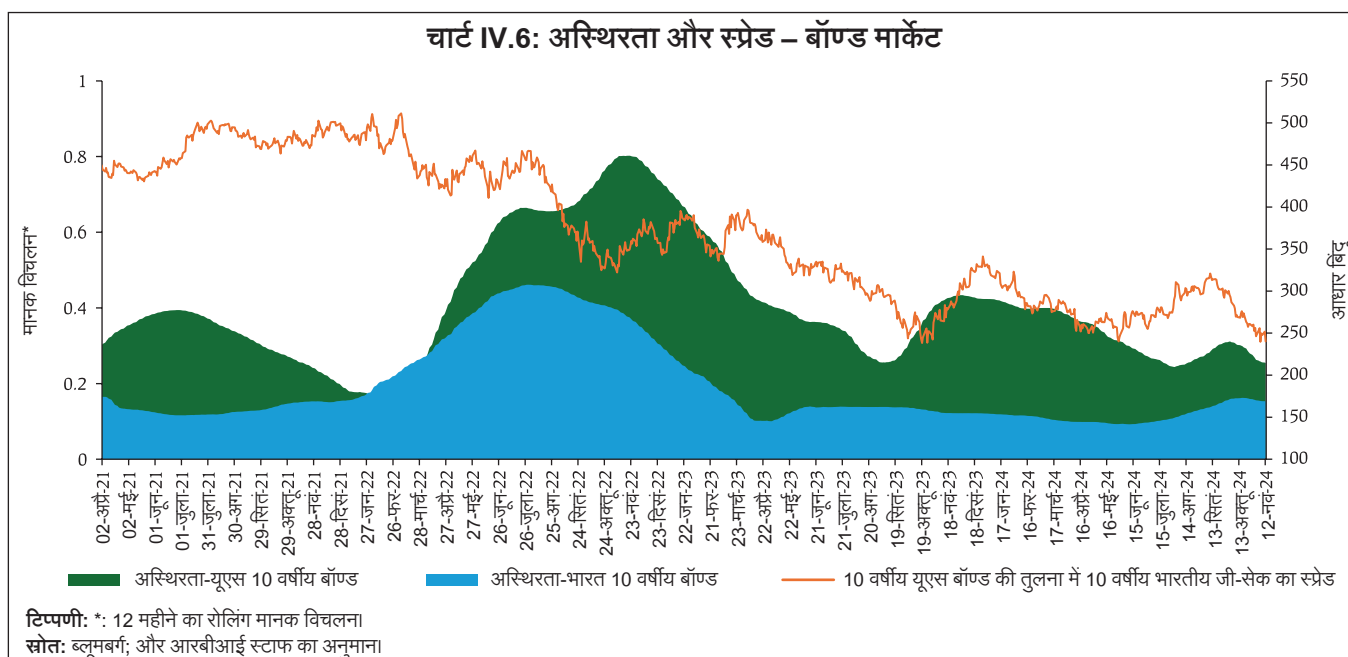
सितंबर 2024 के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करने की संख्या बढ़कर ₹1.30 लाख करोड़ हो गई (जो कि चालू वित्त वर्ष में अब तक का सबसे अधिक है) क्योंकि कॉरपोरेट्स ने फंडिंग स्रोतों में विविधता लाने के लिए कम प्रतिफल का लाभ उठाया। कुल मिलाकर, वर्ष 2024-25 (सितंबर तक) के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करने की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹3.92 लाख करोड़ की तुलना में ₹4.62 लाख

चार्ट IV.4: जी-सेक बाजार में गतिविधियां



स्रोत: ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।





करोड़ अधिक थी। रेटिंग और अवधि स्पेक्ट्रम में कॉर्पोरेट बॉण्ड के प्रतिफल ने मिश्रित गति दिखाई, जबकि संबंधित जोखिम प्रीमियम आम तौर पर अक्टूबर की दूसरी छमाही से नवंबर 2024 की शुरुआत तक कम हो गया (सारणी IV.1)।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 8 नवंबर 2024 तक 6.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पहले 7.0 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]। आरएम के सबसे बड़े घटक, प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि 8 नवंबर 2024

को 6.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी, जो सितंबर 2024 के अंत में 5.9 प्रतिशत से अधिक थी, जो मौसमी त्यौहार-संबंधी मांग में वृद्धि को दर्शाती है।

स्रोत पक्ष (आस्तियों) पर, आरएम में रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियां (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) शामिल हैं। 8 नवंबर 2024 तक विदेशी मुद्रा आस्तियों में 13.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट IV.8)। स्वर्ण - एनएफए का एक प्रमुख घटक - में 50.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण स्वर्ण की कीमतों पर पुनर्मूल्यांकन लाभ है,

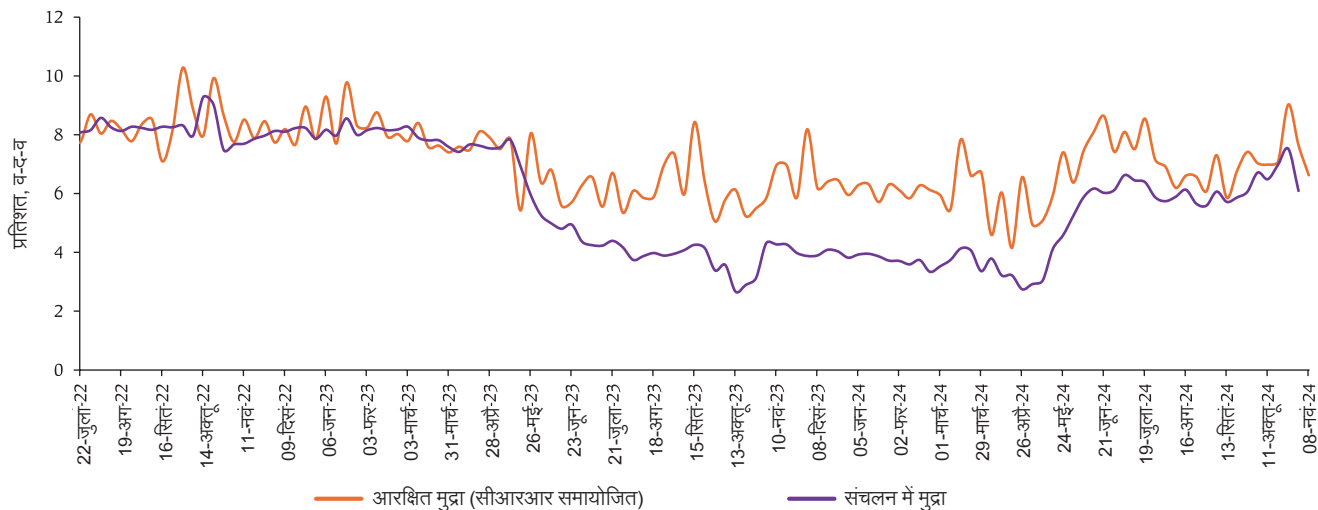
सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस)		
				(संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	16 सित 2024 – 15 अक्टू 2024	16 अक्टू 2024 – 18 नव 2024	विभिन्नता	16 सित 2024 – 15 अक्टू 2024	16 अक्टू 2024 – 18 नव 2024	विभिन्नता
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉर्पोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.83	7.82	-1	117	113	-4
(ii) एएए (3 वर्ष)	7.74	7.77	3	95	93	-2
(iii) एएए (5 वर्ष)	7.65	7.63	-2	83	75	-8
(iv) एए (3 वर्ष)	8.49	8.52	3	170	169	-3
(v) बीबीबी- (3 वर्ष)	12.07	12.17	10	528	533	5

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के लिए औसत के रूप में की जाती है।

स्रोत: एफआईएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट IV.7: आरक्षित मुद्रा और संचलन में मुद्रा



टिप्पणी: आरक्षित मुद्रा का नवीनतम डेटा 8 नवंबर 2024 से संबंधित है।

स्रोत: आरबीआई

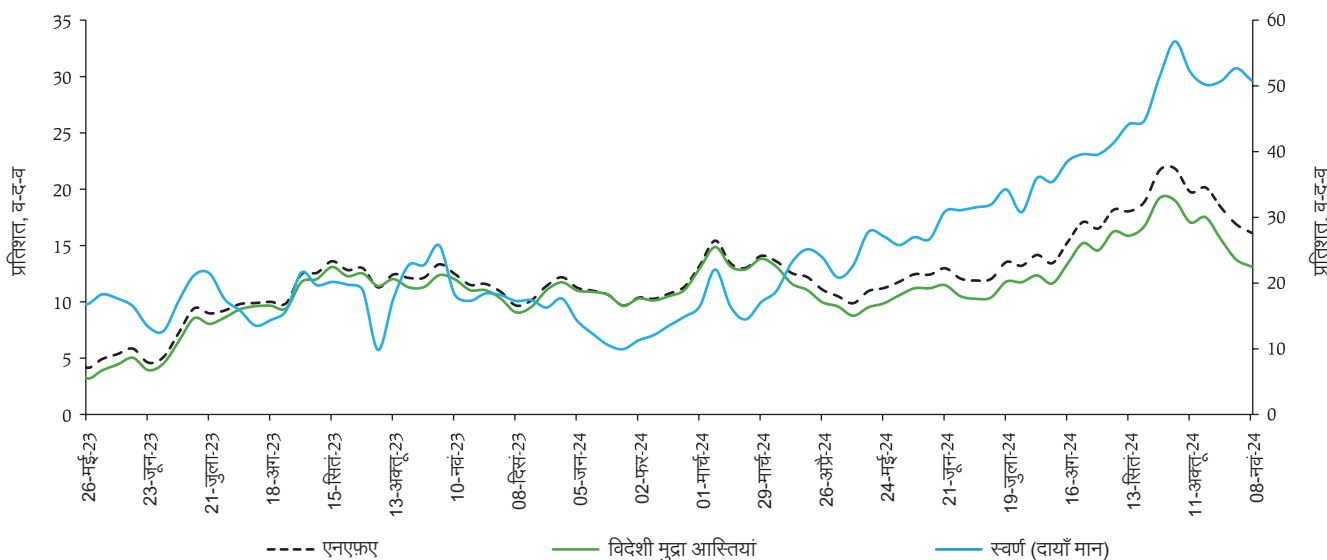
जिसके कारण अक्टूबर 2023 के अंत तक एनएफए में इसकी हिस्सेदारी 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 8 नवंबर 2024 तक 10.3 प्रतिशत हो गई।

1 नवंबर 2024 तक मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में 11.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 11.0 प्रतिशत)।¹⁹ बैंकों के पास कुल जमाराशि, जो एम₃ का लगभग 86 प्रतिशत

है, में 11.6 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 12.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण 01 नवंबर 2024 तक 13.2 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 16.0 प्रतिशत) तक कम हो गई (चार्ट IV.9)।

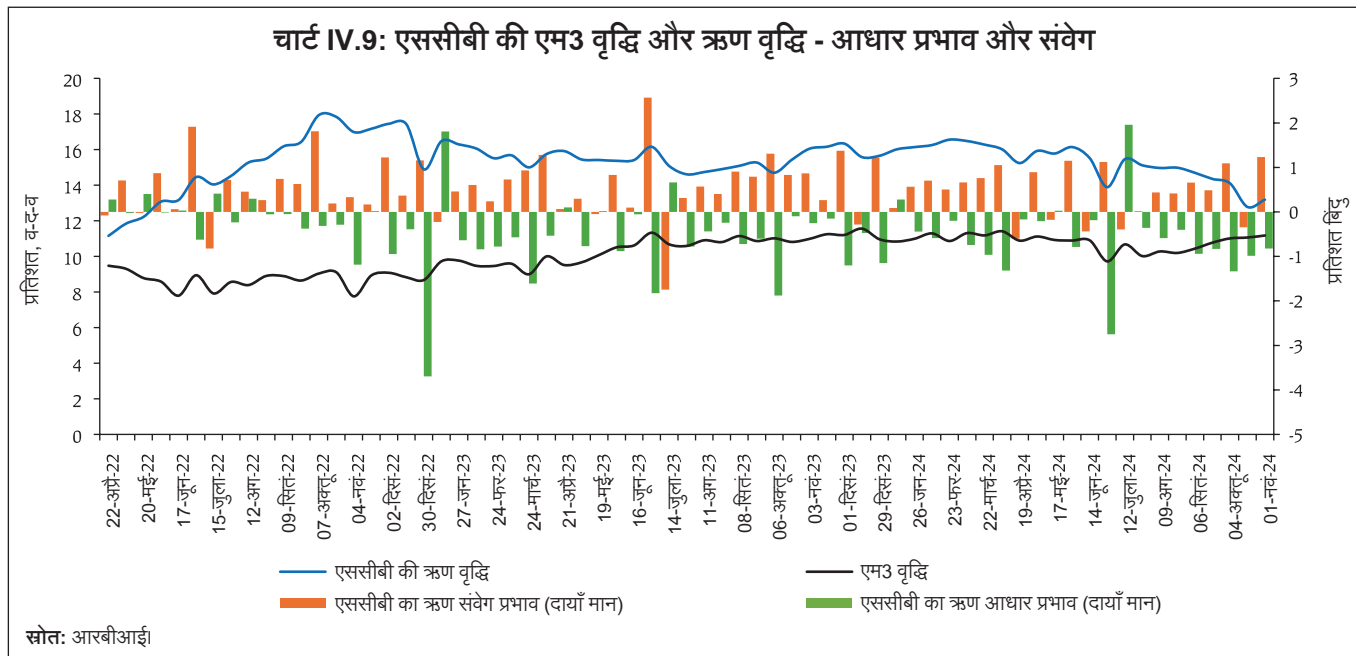
एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर) अगस्त 2024 के अंत में 11.3 प्रतिशत से बढ़कर 01 नवंबर

चार्ट IV.8: आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (एनएफए) - वृद्धि



स्रोत: आरबीआई

¹⁹ बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई 2023 से प्रभावी)।

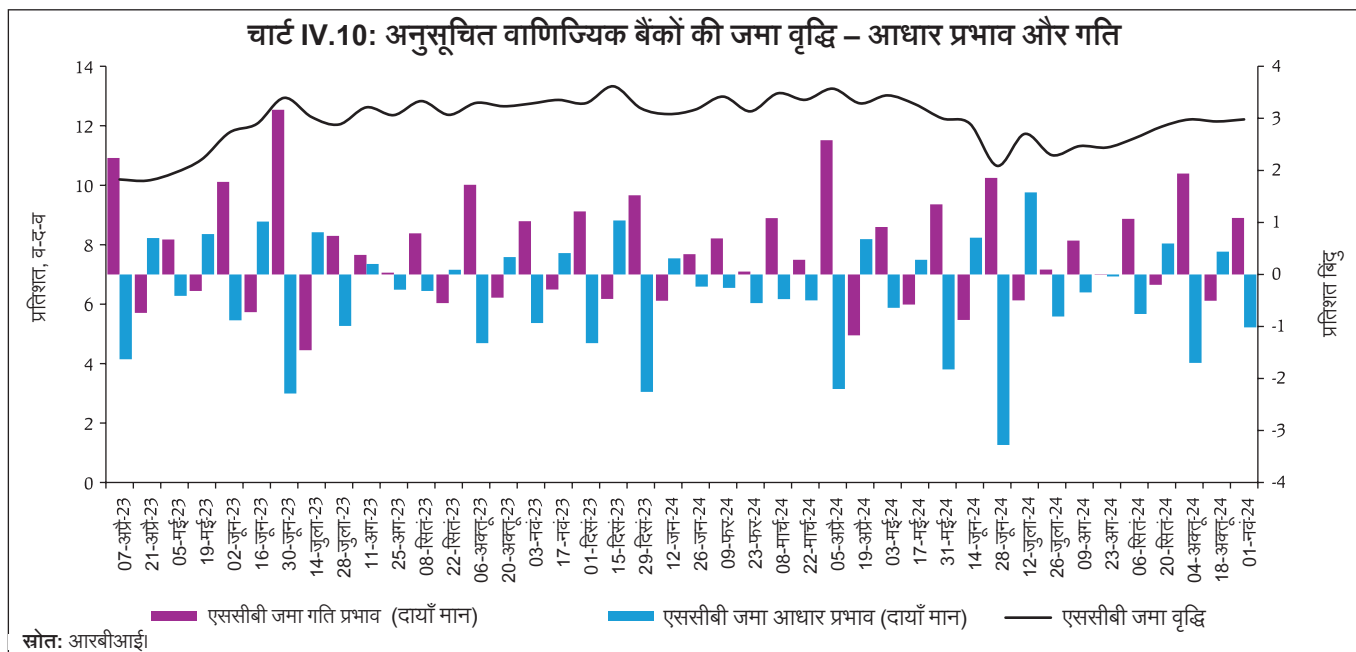


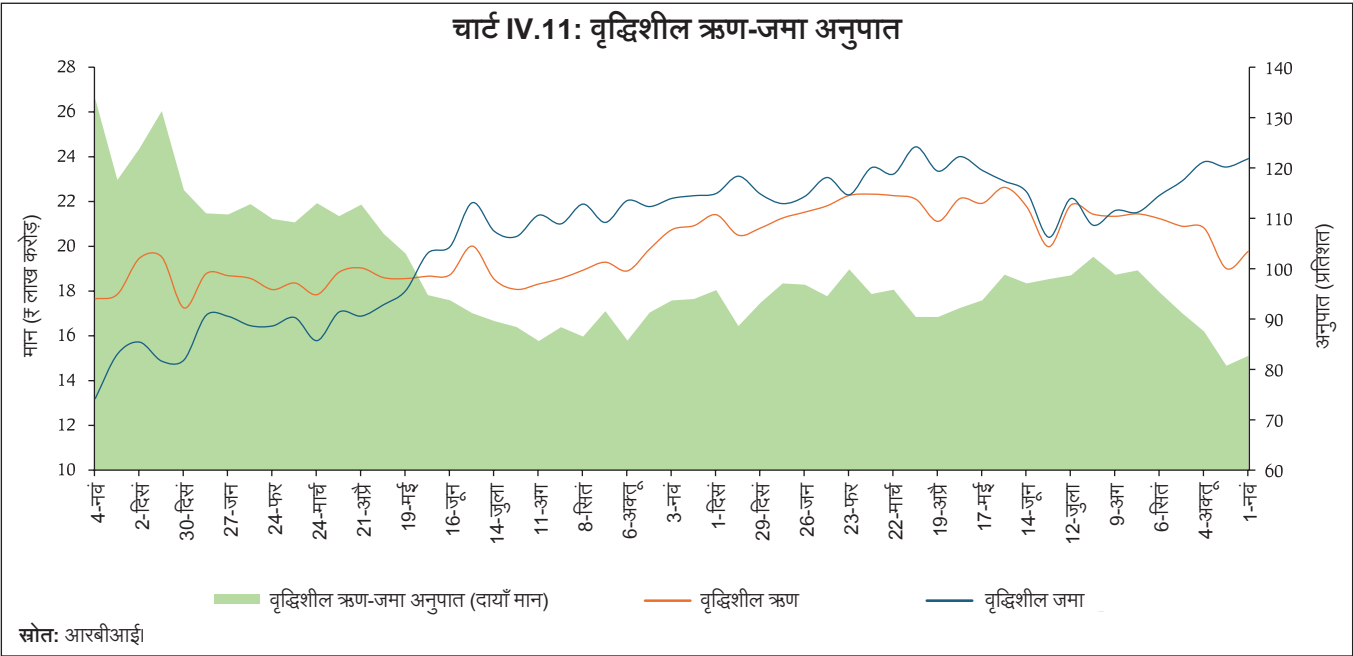
2024 को 12.2 प्रतिशत हो गई, जिसे मजबूत गति और कम आधार प्रभाव का समर्थन प्राप्त हुआ (चार्ट IV.10)।

एससीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात मार्च 2024 के अंत में 95.8 से घटकर 01 नवंबर 2024 को 82.7 हो गया, जिसमें वृद्धिशील जमा अगस्त-अक्टूबर 2024 के दौरान वृद्धिशील ऋण से आगे निकल गया (चार्ट IV.11)। सीआरआर और एसएलआर

के लिए क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सांविधिक आवश्यकताओं के साथ, 01 नवंबर 2024 तक ऋण विस्तार के लिए बैंकिंग प्रणाली में लगभग 77 प्रतिशत जमा उपलब्ध थे।

मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों (बीपीएस) की बढ़ोतरी के जवाब में, बैंकों ने अपने रेपो-आधारित बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को समान





परिमाण से संशोधित किया। एससीबी की औसत 1-वर्षीय सीमांत लागत-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) मई 2022 से अक्टूबर 2024 के दौरान 170 बीपीएस बढ़ गई। नतीजतन, नए और बकाया रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएलआर) में मई 2022 से सितंबर 2024 के दौरान क्रमशः 186 बीपीएस और 118 बीपीएस की वृद्धि हुई। जमा दरों के मामले में, एससीबी की नई और बकाया रुपया मियादी जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में इसी अवधि के दौरान क्रमशः 251 बीपीएस और 192 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

बैंक समूहों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में जमा दरों में वृद्धि निजी बैंकों की तुलना में अधिक थी; तथापि, बकाया रुपया ऋणों के मामले में, इसी अवधि के दौरान नीतिगत दर वृद्धि का संचरण निजी बैंकों के लिए अधिक था (चार्ट IV.12)।

गैर-वित्तीय निजी कॉर्पोरेट्स की बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष), यानी, प्रारंभिक रिपोर्टिंग सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों की बिक्री वृद्धि पिछली तिमाही में 7.1 प्रतिशत से वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान 5.2 प्रतिशत तक कम हो गई। प्रमुख क्षेत्रों में, विनिर्माण कंपनियों की बिक्री वृद्धि घटकर 3.3 प्रतिशत (पिछली तिमाही में 6.3 प्रतिशत) रह गई, जबकि

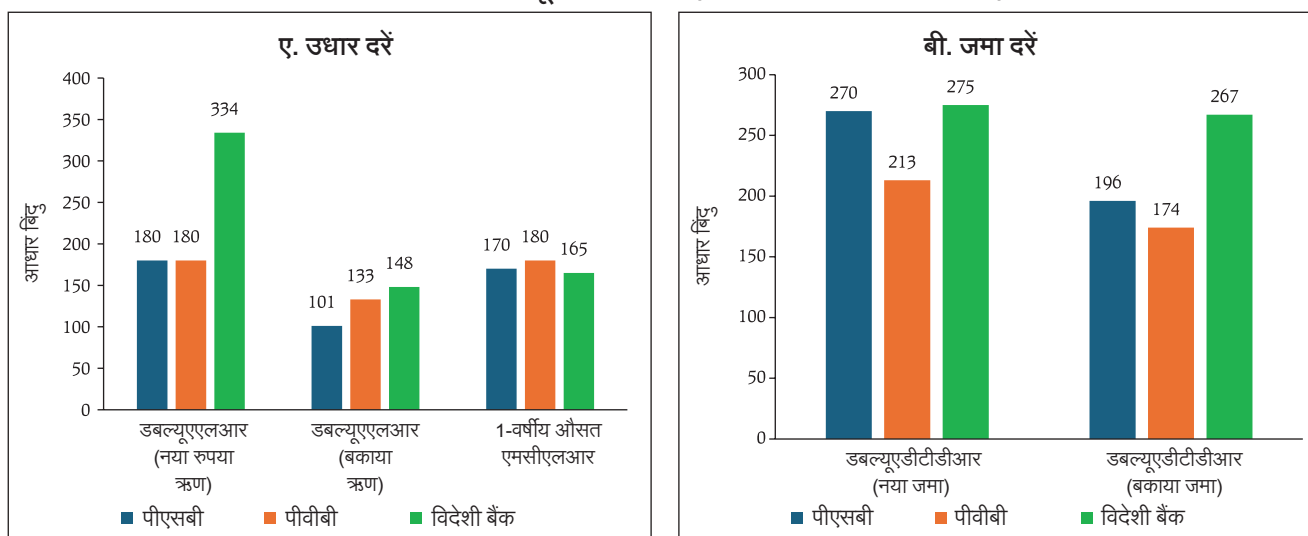
सारणी IV.2: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंकों में भिन्नता)

अवधि	रेपो दर	मीयादी जमा दरें		उधार दरें			
		डब्ल्यूएडीटीडीआर – नया जमा	डब्ल्यूएडीटीडीआर- बकाया जमा	ईबीएलआर	1-वर्ष एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएलआर- नया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर- बकाया रुपया ऋण
सहजता चरण फरवरी 2019 से मार्च 2022 तक	-250	-259	-188	-250	-155	-232	-150
सख्त अवधि मई 2022 से सितंबर* 2024	+250	251	192	250	170	186	118

टिप्पणियाँ: ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।
*: ईबीएलआर और एमसीएलआर पर डेटा अक्टूबर 2024 से संबंधित है।
डब्ल्यूएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर;
एमसीएलआर: फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाह्य बेंचमार्क आधारित ऋण
स्रोत: आरबीआई

चार्ट IV.12: बैंक समूहों में संचरण (मई 2022 से सितंबर 2024)



टिप्पणी: *1-वर्ष के माध्यिका एमसीएलआर पर डेटा मई 2022 से अक्टूबर 2024 तक से संबंधित है।

स्रोत: आरबीआई

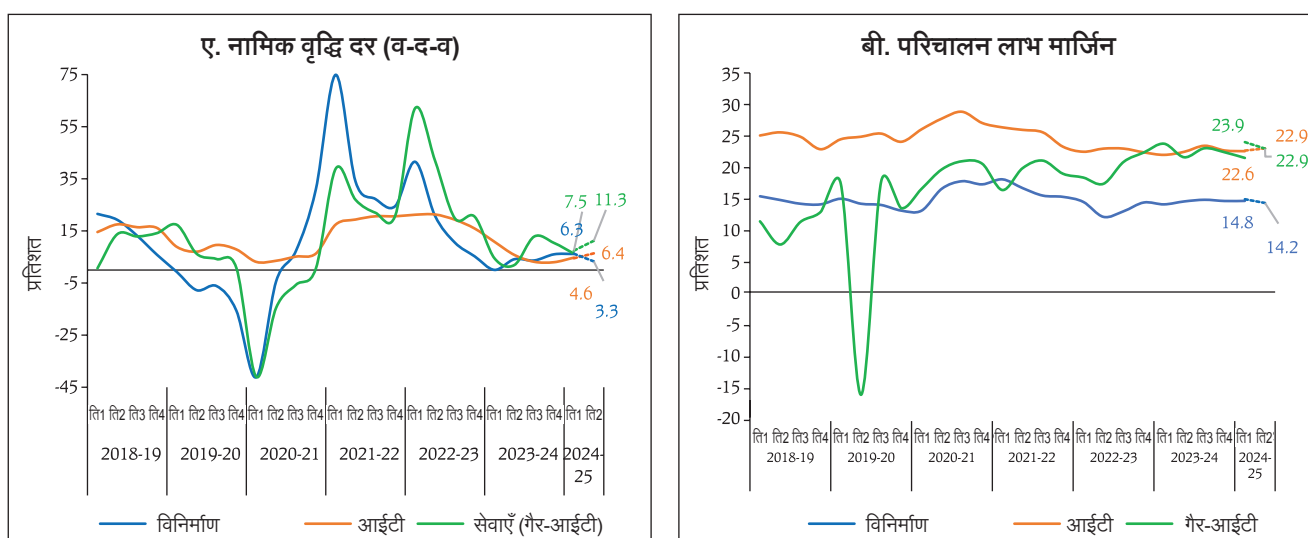
आईटी और गैर-आईटी सेवा कंपनियों के लिए यह क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 11.3 प्रतिशत रही (चार्ट IV.13ए)।

विनिर्माण कंपनियों के लाभ मार्जिन में वार्षिक और क्रमिक दोनों आधार पर कमी आई। गैर-आईटी सेवा कंपनियों ने भी कम लाभ मार्जिन दर्ज किया, लेकिन लागत युक्तिकरण ने आईटी

कंपनियों को अपने परिचालन लाभ मार्जिन को बनाए रखने में मदद की (चार्ट IV.13बी)।

सूचीबद्ध बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों ने कुछ कंपनी-विशिष्ट विशिष्टताओं के बावजूद स्थिर और स्वस्थ आय की सूचना दी। राजस्व, जिसमें मुख्य रूप

चार्ट IV.13: कॉर्पोरेट प्रदर्शन

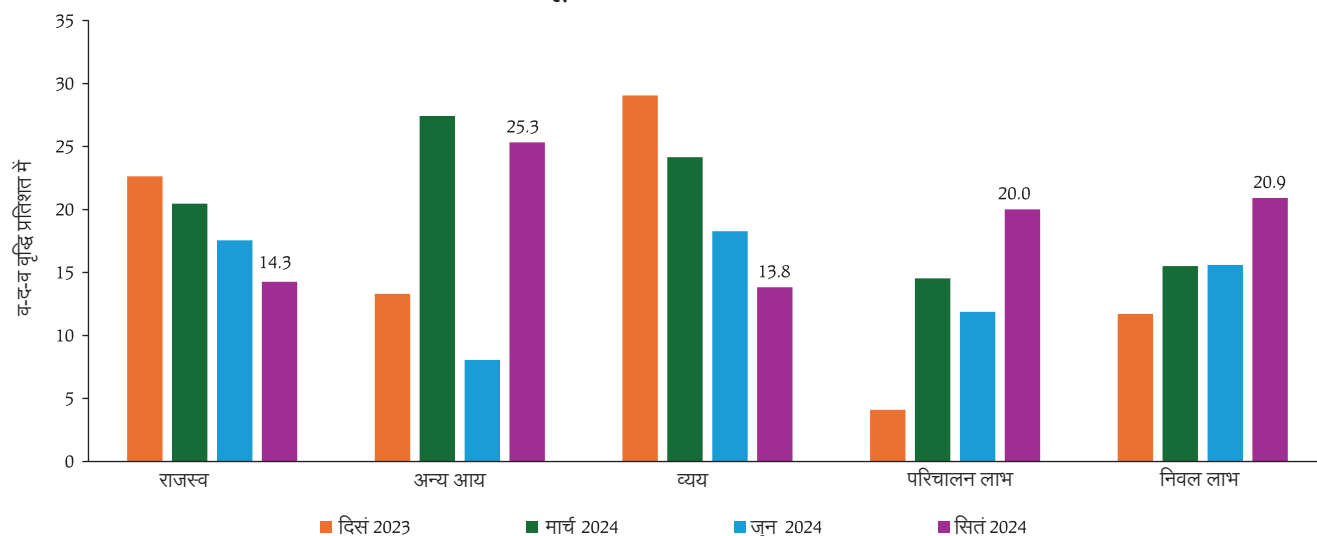


टिप्पणी: 2014 के शुरुआती परिणामों के आधार पर सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियाँ।

स्रोत: सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के तिमाही वित्तीय परिणाम; कैपिटालाइन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

20 वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए 329 बैंकिंग और अन्य वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के परिणामों के आधार पर, इस क्षेत्र के कुल बाजार पूंजीकरण का लगभग 79.1 प्रतिशत है।

चार्ट IV.14: सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन



टिप्पणी: इसमें जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक से संबंधित डेटा शामिल नहीं है।

स्रोत: सीएमआईआई प्रोवेस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

से बैंकों के मामले में ब्याज आय शामिल है, ने कुछ क्रमिक कमी देखने के बावजूद दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की। अन्य आय, जिसमें शुल्क/कमीशन से आय, निवेश की बिक्री से लाभ और हानि शामिल है, ने भी दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की, जिससे कुल आय में वृद्धि हुई। व्यय में वृद्धि थोड़ी धीमी रही, जिसके परिणामस्वरूप तिमाही के लिए परिचालन लाभ वृद्धि में सुधार हुआ। तिमाही के दौरान प्रावधान लागत में तेजी से वृद्धि हुई; हालांकि, कर व्यय में मामूली वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप तिमाही के दौरान सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों के निवल लाभ (कर के बाद) में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि हुई (चार्ट IV.14)।

सूचीबद्ध गैर-वित्तीय विनिर्माण कंपनियों का लीवरेज, जैसा कि उनके ऋण-से-इक्विटी अनुपात में परिलक्षित होता है, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान मध्यम²¹ बना रहा, जिसका मुख्य कारण लाभ का उच्च पूंजीकरण था। पेट्रोलियम, लोहा और इस्पात, तथा सीमेंट उद्योग विनिर्माण कंपनियों की अचल आस्तियों में वृद्धि का कारण रहे, जो कुल अचल संपत्तियों में लगभग 47 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ 7.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी (चार्ट IV.15)।

प्रतिधारित आय निधि का प्रमुख स्रोत बनी रही। पहली छमाही के दौरान जुटाए गए फंड का उपयोग मुख्य रूप से गैर-वर्तमान निवेश²², अचल आस्तियों और व्यापार प्राप्तियों को बढ़ाने में किया गया (चार्ट IV.16ए और 16बी)।

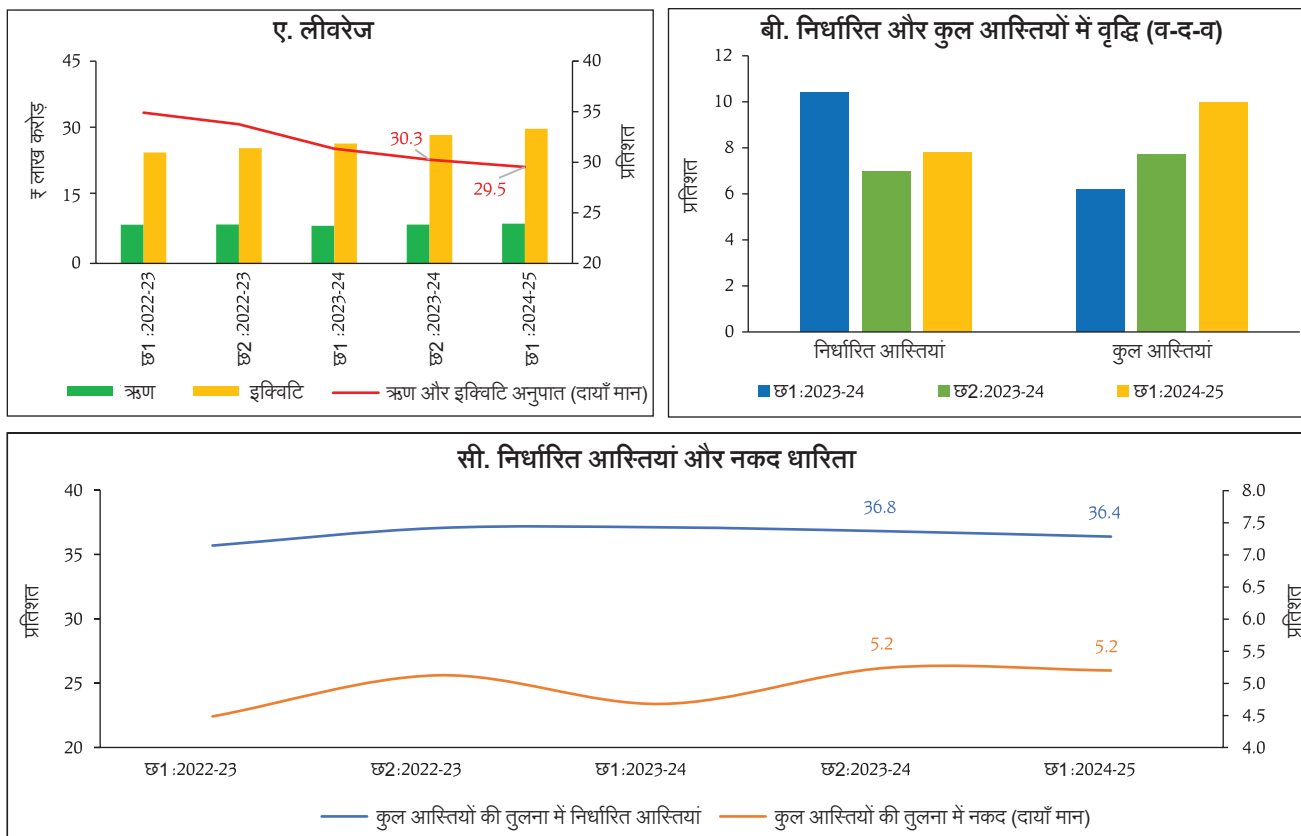
भारतीय इक्विटी बाजार में अक्टूबर 2024 के दूसरे पखवाड़े और नवंबर की शुरुआत में लगातार एफपीआई बिकवाली के बीच गिरावट दर्ज की गई (चार्ट IV.17)। भू-राजनीतिक अनिश्चितता, उच्च मूल्यांकन और अपेक्षाओं से कम वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के आय परिणामों ने निवेशकों की भावनाओं को कमजोर कर दिया। अक्टूबर 2024 के लिए उम्मीद से ज़्यादा घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट ने भी धारणा को प्रभावित किया। कुल मिलाकर, सितंबर के अंत से बीएसई सेंसेक्स में 8 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 14 नवंबर 2024 को 77,580 पर बंद हुआ।

इक्विटी बाजार में हालिया गिरावट एफपीआई द्वारा सितंबर के अंत से लेकर 14 नवंबर 2024 तक इक्विटी से लगभग ₹1.2 लाख करोड़ के संचयी निवल बहिर्वाह का परिणाम

²² गैर-चालू निवेश दीर्घकालिक आस्तियां हैं जिनमें निवेश आस्तियों में इक्विटी उपकरण, वरीयता शेयर, सरकारी या ट्रस्ट प्रतिभूतियां, डिबेंचर या बांड, म्यूचुअल फंड, साझेदारी फर्मों में निवेश; सहायक कंपनियों आदि में निवेश शामिल हैं।

²¹ 1689 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों के संक्षिप्त तुलन-पत्र के आधार पर।

चार्ट IV.15: विनिर्माण



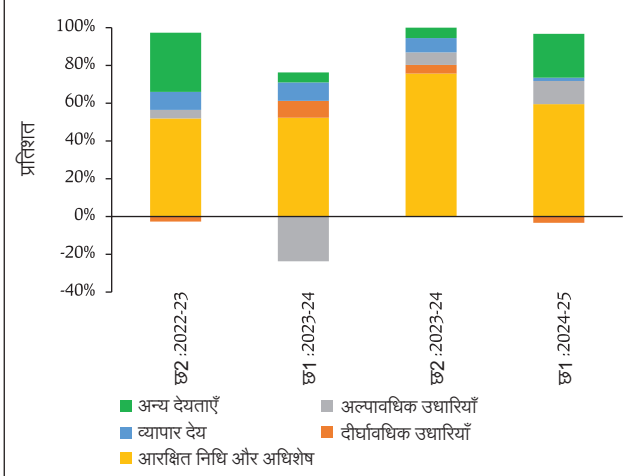
टिप्पणी: प्रारंभिक परिणाम 1689 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों पर आधारित हैं।

स्रोत: सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों का छमाही तुलन पत्र; कैपिटालाइन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

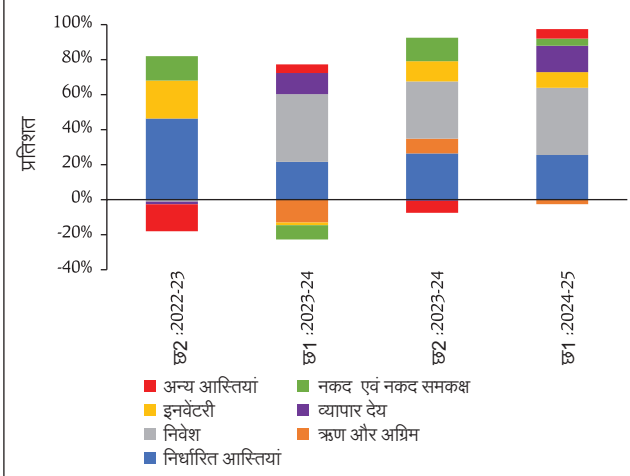
थी - जो निरपेक्ष रूप से अब तक का सबसे अधिक है। सापेक्ष आधार पर, यानी, जब एफपीआई बहिर्वाह को कुल बाजार

पूँजीकरण के संबंध में मापा जाता है, हालांकि, पिछले प्रकरणों में हुई बिकवाली की तुलना में बहिर्वाह का यह प्रकरण अब

चार्ट IV.16ए: निधियों के स्रोत (अर्ध-वार्षिक परिवर्तन)

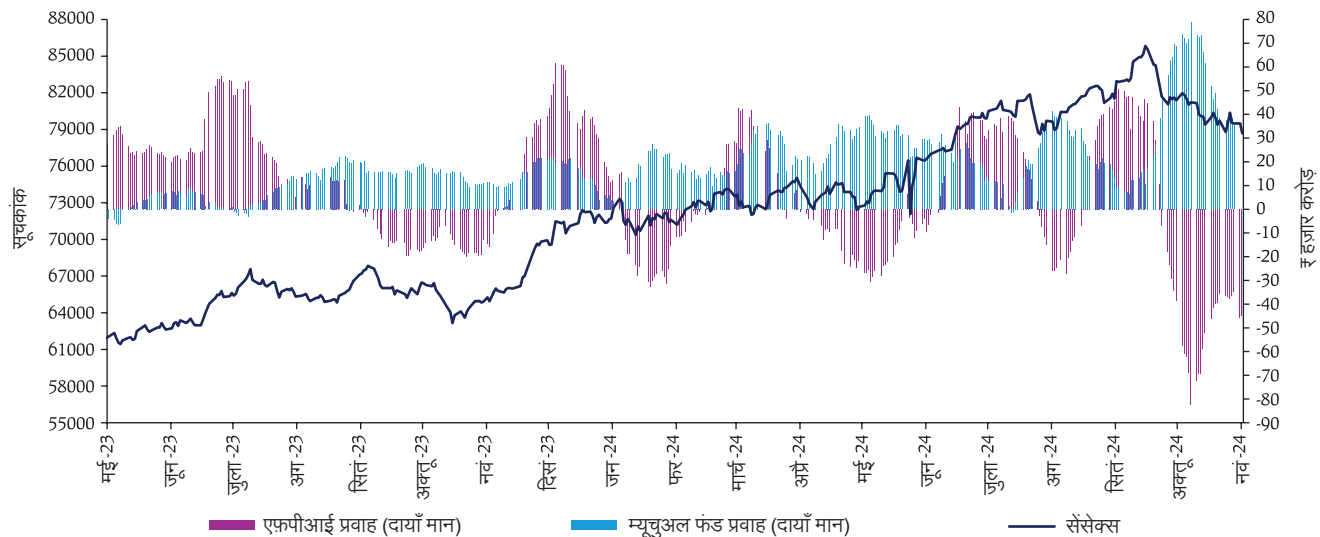


चार्ट IV.16बी: निधियों का उपयोग (अर्ध-वार्षिक परिवर्तन)



स्रोत: सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों का छमाही तुलन पत्र; कैपिटालाइन डेटाबेस; और आरबीआई कर्मचारियों का अनुमान।

चार्ट IV.17: बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह



टिप्पणी: एफपीआई और एमएफ प्रवाह 15-दिनों के रोलिंग योग के आधार पर दर्शाए जाते हैं।
स्रोत: एनएसडीएल; और बीएसई।

तक मामूली बना हुआ है (चार्ट IV.18)। बाजार में गिरावट के बीच, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों ने अक्टूबर 2024 के महीने में ₹41,865 करोड़ के उच्चतम निवल अंतर्वाह को देखा, क्योंकि घरेलू निवेशकों ने बाजार में गिरावट का लाभ उठाने की कोशिश की।

सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मजबूत वृद्धि देखी गई क्योंकि यह अप्रैल-

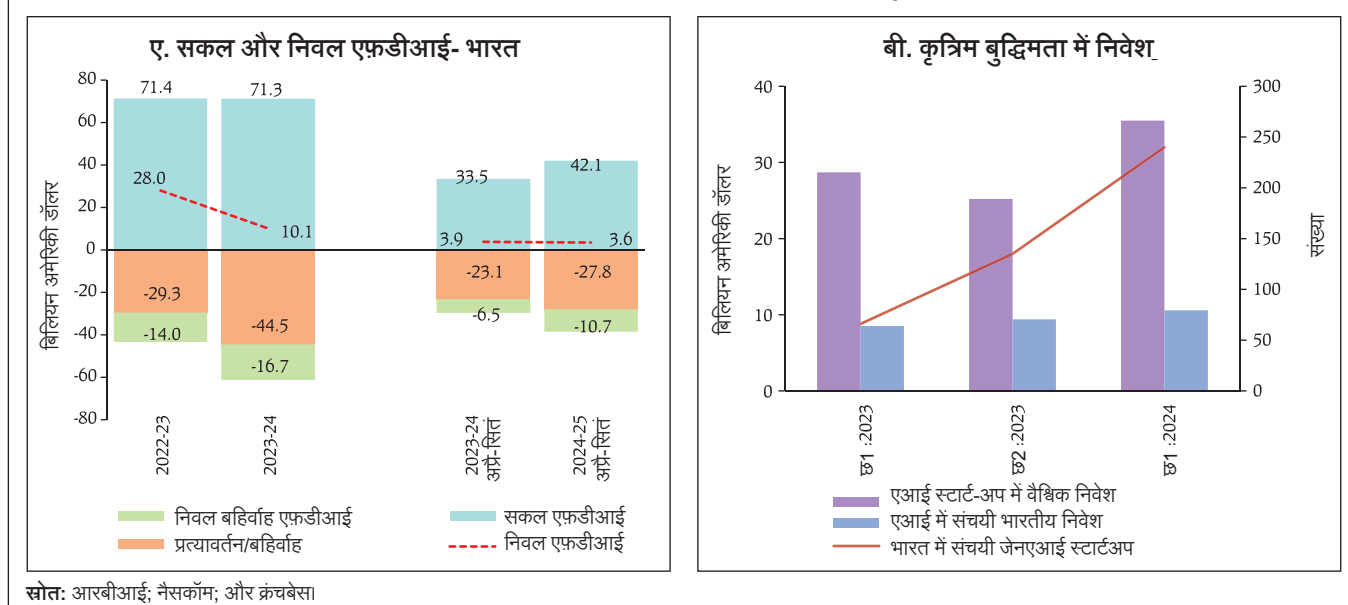
सितंबर 2024 के दौरान एक वर्ष पहले के 33.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 42.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान निवल एफडीआई एक वर्ष पहले के 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण प्रत्यावर्तन और बाहरी एफडीआई में वृद्धि है (चार्ट IV.19ए)। विनिर्माण, वित्तीय सेवाएं, बिजली और अन्य ऊर्जा क्षेत्र, और संचार सेवाओं ने

चार्ट IV.18: भारतीय इक्विटी बाजारों से एफपीआई बहिर्वाह के एपिसोड



टिप्पणी: एफपीआई बहिर्वाह को बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।
स्रोत: एनएसडीएल; बीएसई; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट IV.19: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह



सकल एफडीआई अंतर्वाह में लगभग दो-तिहाई का योगदान दिया। सिंगापुर, मॉरीशस, नीदरलैंड, यूएई और अमेरिका लगभग तीन-चौथाई प्रवाह के स्रोत थे।

दुनिया भर में एआई स्टार्ट-अप में बढ़ते निवेश के साथ, भारत अपने तेजी से बढ़ते एआई इकोसिस्टम का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है ताकि आगे और निवेश आकर्षित किया जा सके और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके (चार्ट IV.19बी)। 2023 से (छ1:2024 तक), भारत ने जनरेटिव एआई स्टार्टअप में निवेश के मामले में खुद को दुनिया की शीर्ष छह अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिया है।²³ भारत वर्ष 2013-2023 के दौरान संचयी निजी एआई निवेश में शीर्ष दस देशों में भी शुमार है।²⁴

अक्टूबर 2024 में भारतीय पूंजी बाजारों में निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह चार महीने बाद नकारात्मक हो गया, जो भू-राजनीतिक तनावों से बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और हाल ही में चीन द्वारा उठाए गए प्रोत्साहन उपायों और अमेरिका में चुनाव परिणामों के मद्देनजर वैश्विक पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा पुनर्संतुलन से प्रभावित हुआ। अक्टूबर 2024 में 11.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल

एफपीआई बहिर्वाह कोविड-19 महामारी के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जो मुख्य रूप से इक्विटी वाले भाग में पर्याप्त बहिर्वाह से प्रेरित थे (चार्ट IV.20ए)।

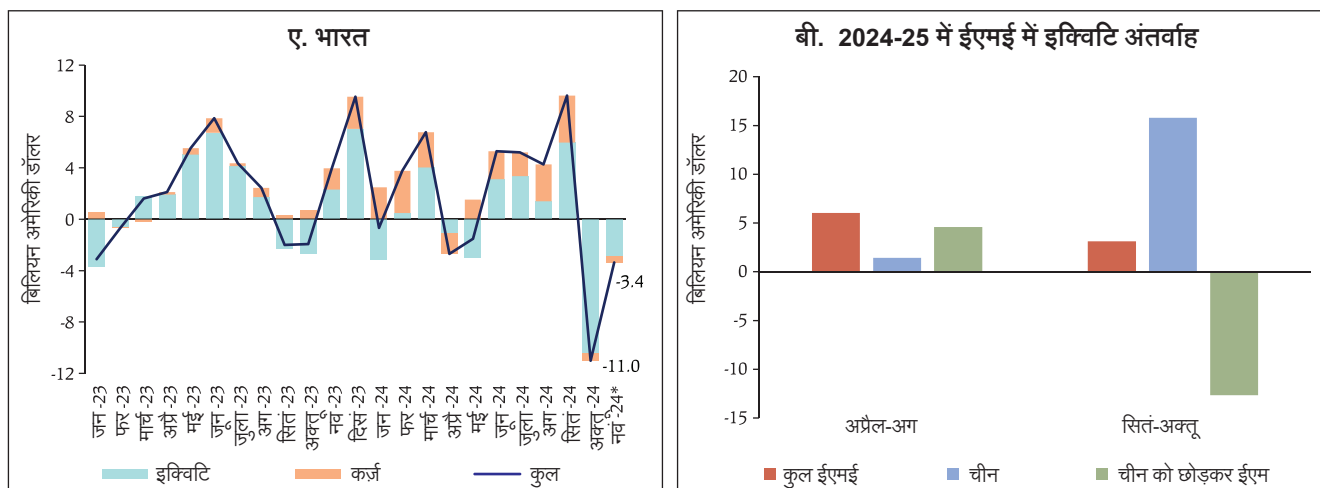
इक्विटी की बिक्री उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में व्यापक रूप से दिखाई देती है क्योंकि विदेशी निवेशकों ने पूंजी को अन्य ईएमई से हटा कर चीनी इक्विटी की ओर स्थानांतरित कर दिया और (चार्ट IV.18बी)। अक्टूबर 2024 के दौरान ऋण खंड में अपने पांच महीने के लगातार प्रवाह में विराम देखा, हालांकि निवल बहिर्वाह अपेक्षाकृत सीमित रहा। क्षेत्रों में, वित्तीय सेवाओं, तेल, गैस और उपभोग्य ईंधन, और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वस्तुओं ने अक्टूबर के दौरान सबसे अधिक बहिर्वाह दर्ज किया। नवंबर 2024 (14 नवंबर तक) में, निवल एफपीआई बहिर्वाह 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर रहा।

अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान गैर-निवासी जमाराशियों में निवल अंतर्वाह 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष पहले 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सभी तीन खातों में उच्च अंतर्वाह दर्ज किया गया, अर्थात् गैर-निवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई)आरए], गैर-निवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा गैर-निवासी [एफसीएनआर(बी)] खाते।

23 नैसकॉम- भारत का जनरेटिव एआई स्टार्टअप लैंडस्केप 2024।

24 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2024।

चार्ट IV.20: निवल पोर्टफोलियो निवेश



टिप्पणियाँ: 1. ऋण में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग और हाइब्रिड लिखतों के तहत निवेश शामिल हैं।

2. *: 14 नवंबर 2024 तक का डेटा।

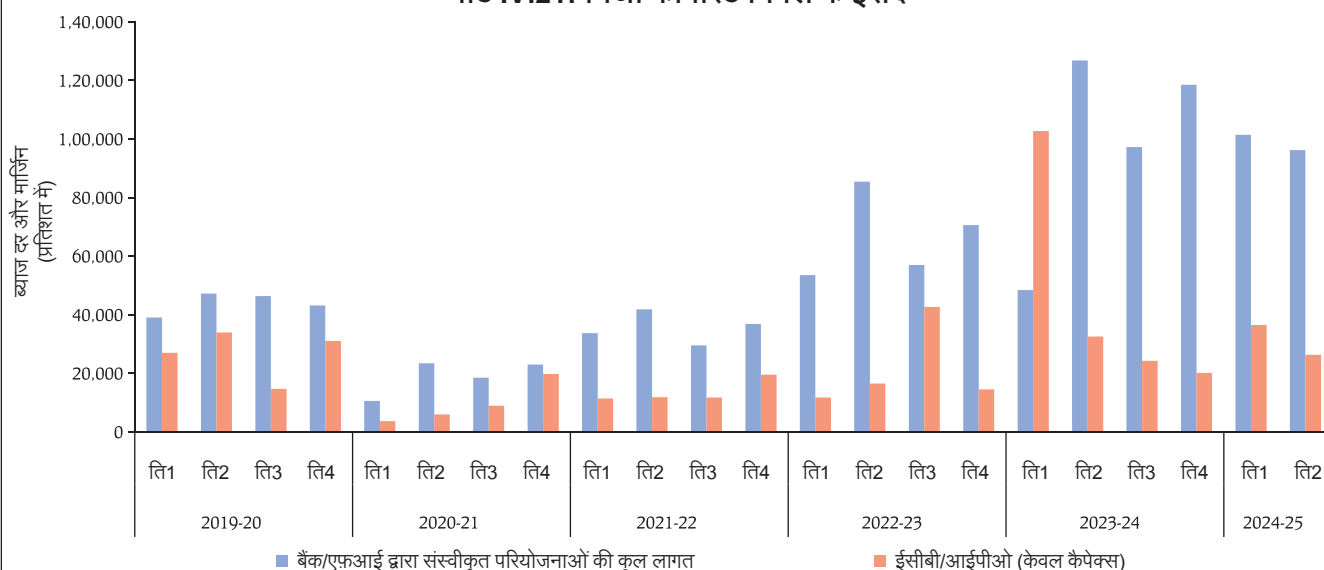
स्रोत: नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); और अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत छ1:2024-25 के दौरान ₹1,97,659 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष के ₹1,75,217 करोड़ से काफी अधिक है। इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक निवेश 'विद्युत' और 'सड़क और पुल' क्षेत्रों के लिए हैं। पूंजीगत व्यय के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से जुटाई गई

धनराशि ति2:2024-25 के दौरान ₹26,308 करोड़ थी, जो पिछली तिमाही में ₹36,489 करोड़ से अधिक थी (चार्ट IV.21)।

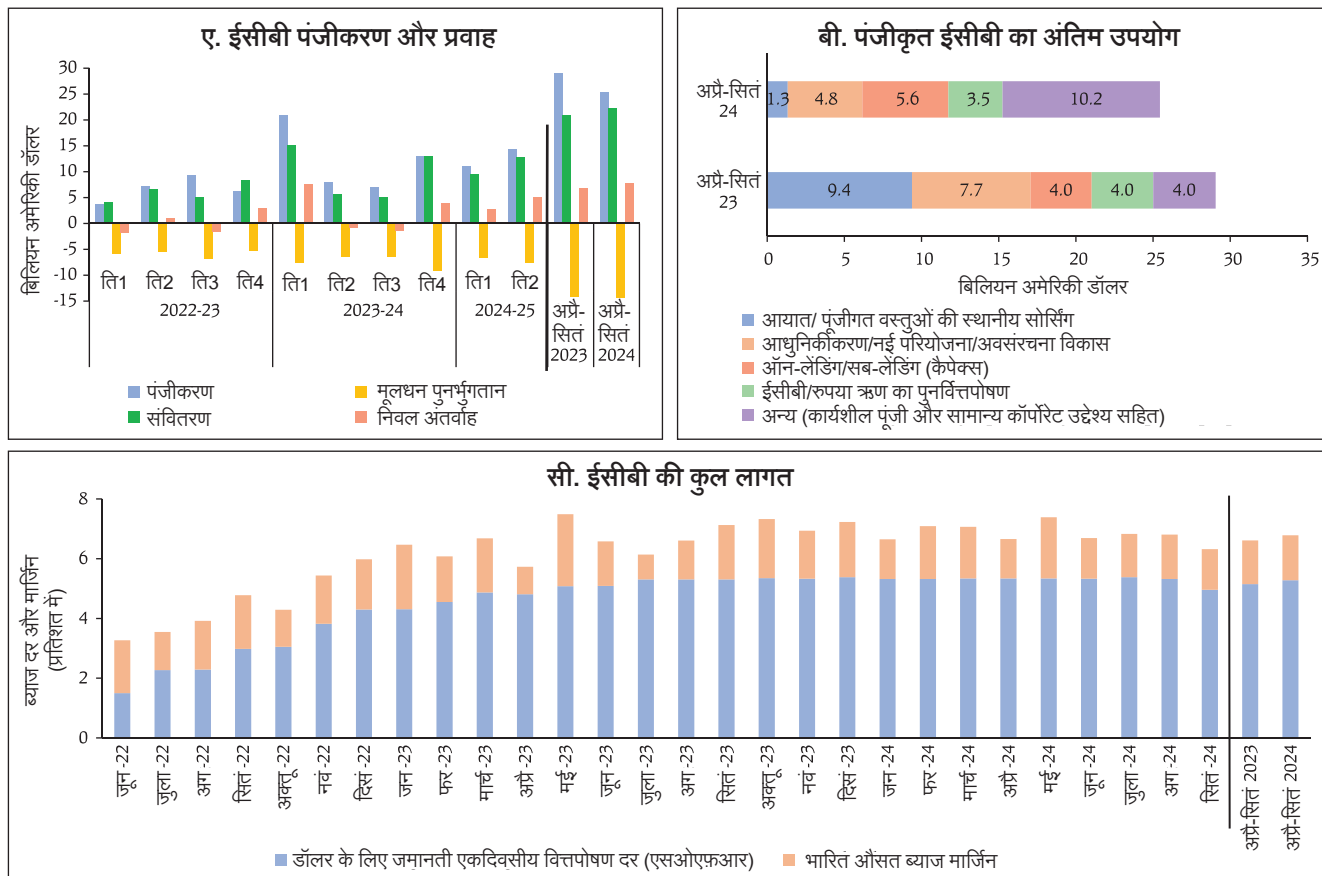
2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान नए ईसीबी ऋण पंजीकरण (14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और संवितरण (12.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पिछली तिमाही के साथ-साथ एक वर्ष पहले की इसी अवधि की तुलना में अधिक थे। वर्ष 2024-

चार्ट IV.21: निजी कॉर्पोरेट निवेश के इरादे



स्रोत: आरबीआई; बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से एकत्रित परियोजना वित्त संबंधी आंकड़े; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

चार्ट IV.22: बाह्य वाणिज्यिक उधार



स्रोत: फॉर्म ईसीबी, आरबीआई

25 की पहली छमाही के दौरान निवल अंतर्वाह (7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा (चार्ट IV.22ए)। वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान पंजीकृत नए ईसीबी में से लगभग आधे पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय के लिए ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग सहित) के लिए थे [चार्ट IV.22बी]।

हाल ही में वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दरों जैसे कि जमानती एकदिवसीय वित्तपोषण दर (एसओएफआर) में ढील के परिणामस्वरूप सितंबर 2024 के दौरान जुटाए गए ईसीबी की कुल लागत में गिरावट आई है। वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान बेंचमार्क दरों पर भारित औसत ब्याज मार्जिन (डबल्यूएआईएम) 2023-24 की पहली छमाही की तुलना में 5 बीपीएस अधिक था (चार्ट IV.22सी)।

वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान पंजीकृत ईसीबी में से तीन-चौथाई से अधिक को स्पष्ट हेजिंग, रुपया-

वर्गीकृत ऋण और विदेशी अभिभावकों से ऋण में प्रभावी रूप से हेज किया गया था, जो इस तरह के जोखिमों की ब्याज और विनिमय दर संवेदनशीलता को काफी हद तक संतुलित करता है (चार्ट IV.23)।

अक्टूबर 2024 में भारतीय रुपये (आईएनआर) में 0.3 प्रतिशत (म-द-म) की गिरावट आई, क्योंकि अधिकांश ईएमई को मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण मूल्यहास दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि, माह के दौरान आईएनआर ने प्रमुख मुद्राओं में सबसे कम अस्थिर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी (चार्ट IV.24, बॉक्स 2)।

सकारात्मक मुद्रास्फीति अंतर के साथ-साथ नाममात्र प्रभावी शर्तों में आईएनआर की वृद्धि के कारण अक्टूबर 2024 में 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में आईएनआर में 1.8 प्रतिशत (म-द-म) की वृद्धि हुई (चार्ट IV.25)।

बॉक्स 2: भारत की विनिमय दर व्यवस्था

मार्च 1993 से भारतीय रुपये (आईएनआर) की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने और व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने के लिए दो-तरफ़ा विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप (एफएक्सआई) करता है, बिना विनिमय दर के किसी विशिष्ट स्तर को लक्षित किए। यह नीति उद्देश्य 1993 से अपरिवर्तित रहा है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अस्थिर पूंजी प्रवाह के प्रभावों को सुचारु बनाने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और वास्तविक क्षेत्र में प्रभाव विस्तार को कम करने में मदद मिली है।

वर्ष 2023 के लिए विनिमय व्यवस्था और विनिमय प्रतिबंधों (एआरआईएआर) पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की विनिमय दर नीति को दिसंबर 2022-अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए एक वास्तविक 'स्थिर व्यवस्था' करार दिया है, जबकि वास्तविक वर्गीकरण 'अस्थिर' बना हुआ है। आईएमएफ ने खुद स्वीकार किया है कि पुनर्वर्गीकरण पद्धति एक पिछड़े-दिखने वाले सांख्यिकीय दृष्टिकोण का अनुसरण करती है और बहुत कम समय क्षितिज के आधार पर निष्कर्ष निकालती है।²⁵

विनिमय दर व्यवस्था को स्थिर व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आईएमएफ की +/- 2 प्रतिशत उतार-चढ़ाव सीमा तदर्थ, विषयपरक, सदस्य देशों की नीतियों की निगरानी के अपने केंद्रीय उद्देश्य का अतिक्रमण और लेबलिंग के समान है। इसके अलावा, अवधि (दिसंबर 2022-अक्टूबर 2023) का चयन विवेकाधीन है और इस प्रकार, पुनर्वर्गीकरण पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। वास्तव में, विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप (एफएक्सआई) पर आईएमएफ के हालिया शोध पत्र का निष्कर्ष है कि आरबीआई बाह्य आघातों के प्रभाव को कम करने, बाजार की अस्थिरता को कम करने, अव्यवस्थित बाजार स्थितियों के उद्भव को रोकने और अवसरवादी रूप से अपने एफएक्स भंडार को फिर से भरने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है।²⁶

हाल ही में, मीडिया में आईएनआर की विनिमय दर नीति पर कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं। इसमें उठाए गए मुद्दे पर बात करना उचित है, लेकिन भावनाओं, असंतोष या पूर्व-प्रतिबद्ध सैद्धांतिक स्थितियों से मुक्त होना चाहिए जो वास्तविक तथ्यों के साथ परखे नहीं गए हैं।

वर्ष 2020 से, भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था पिछले संकटों के विपरीत, अनिश्चितता के लंबे दौर से जूझ रही है, जैसे कि वैश्विक वित्तीय संकट (2008) और टेपर टैंट्रम (2013) जिसमें भारत या तो मूकदर्शक था या केवल 'बातचीत' कर रहा था। 2020 से अनुभव किए जा रहे एक के बाद एक तरह-तरह की समस्याओं के बावजूद, रिज़र्व में कमी, निवल मूल्यांकन घाटा, वास्तव में इन सभी घटनाओं में तुलनीय है।

इसके अलावा, निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप (एफएक्सआई) को अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है²⁷। इस सिद्धांत का पालन करते हुए, यह पाया गया है कि फरवरी से अक्टूबर 2022 के दौरान जीडीपी में आरबीआई का निवल हस्तक्षेप औसतन 1.6 प्रतिशत था, जबकि पहले के संकटों के दौरान यह 1.5 प्रतिशत था, जो बहुत कम परिमाण के थे।

आरबीआई के हस्तक्षेप का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार तरल और जमा हुआ हो, और व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा हो। परिणामस्वरूप, आईएनआर की अस्थिरता - जैसा कि विकल्प कीमतों के साथ-साथ जीएआरसीएच²⁸ अनुमानों और 30 दिनों के रोलिंग मानक विचलन से निकाला गया है - लगातार कम हो रही है (चार्ट 2ए)। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के मामले में इसका लाभकारी प्रभाव पड़ा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रुपये में 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई और वर्ष 2023-24 के लिए 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2023-24 में भारतीय रुपये में गिरावट का निम्न क्रम भारत के व्यापक-आधार की मजबूती को दर्शाता है।

(Contd.)

25 आईएमएफ अनुच्छेद IV परामर्श - भारत (2023)।

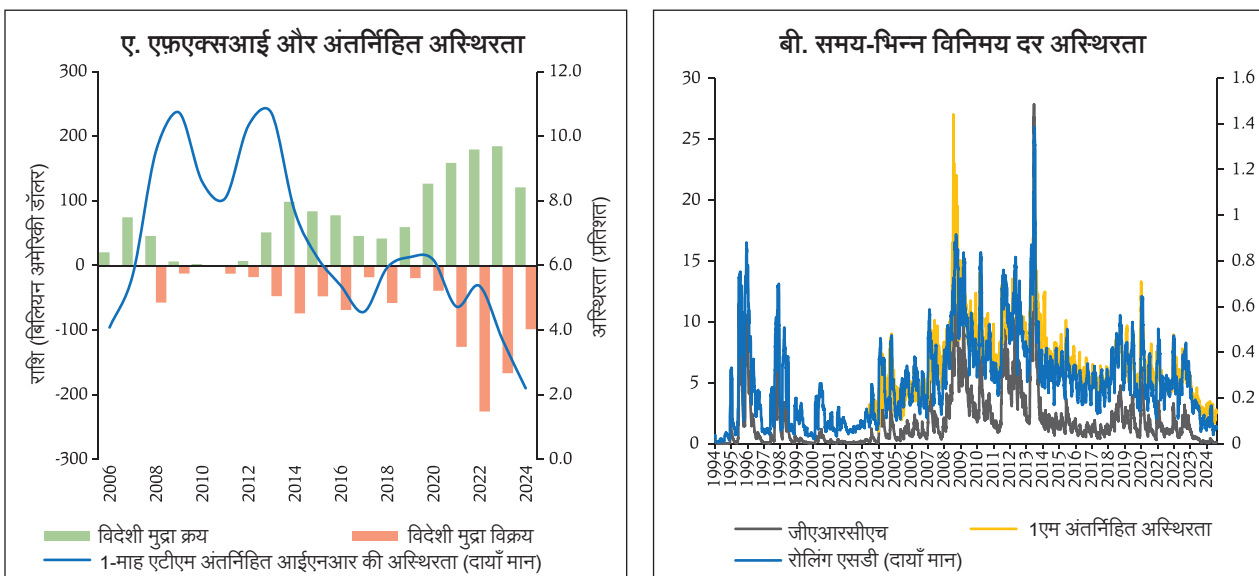
26 लिंडे, जेस्पर, एवं अन्य (2024), "एकीकृत नीतिगत ढांचे के तहत विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप: भारत का मामला", आईएमएफ, वर्किंग पेपर, 24/236

27 अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 1994-2018 के दौरान औसतन 1,186 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2019-2024 के दौरान 3,248 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

28 सामान्यीकृत स्वतःप्रतिगमन सशर्त विषमता (जीएआरसीएच)।

29 (i) अमेरिका और भारत के बीच सीपीआई मुद्रास्फीति का अंतर 2023 में केवल 1.6 प्रतिशत अंक पर मामूली था; (ii) भारत के चालू खाता घाटा (सीएडी) 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.7 प्रतिशत था; (iii) वर्ष 2023-24 में निवल पूंजी प्रवाह 89.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2022-23 में 57.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है; और (iv) 8.2 प्रतिशत (2022-23 में 7.0 प्रतिशत से ऊपर) की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ, भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।

चार्ट 2ए: आईएनआर बाज़ार निर्धारित: एफ़एक्सआई अस्थिरता को सुचारु करना



कुछ टिप्पणीकारों का यह अनुमान कि विनिमय दर नीति के रुख ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, साक्ष्यों से पुष्ट नहीं होता। निर्यात प्रदर्शन को पैमाने-2018-19 और 2023-24 के बीच के हिसाब से समायोजित किया जाना चाहिए, वैश्विक पण्य वस्तु निर्यात ने 4.0 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक औसत वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की, जबकि भारत के पण्य वस्तु निर्यात ने 5.8 प्रतिशत की उच्च सीएजीआर दर्ज की। इस अवधि में, भारत के पण्य वस्तु निर्यात की वृद्धि कई क्षेत्रीय समकक्षों की तुलना में अधिक थी³⁰

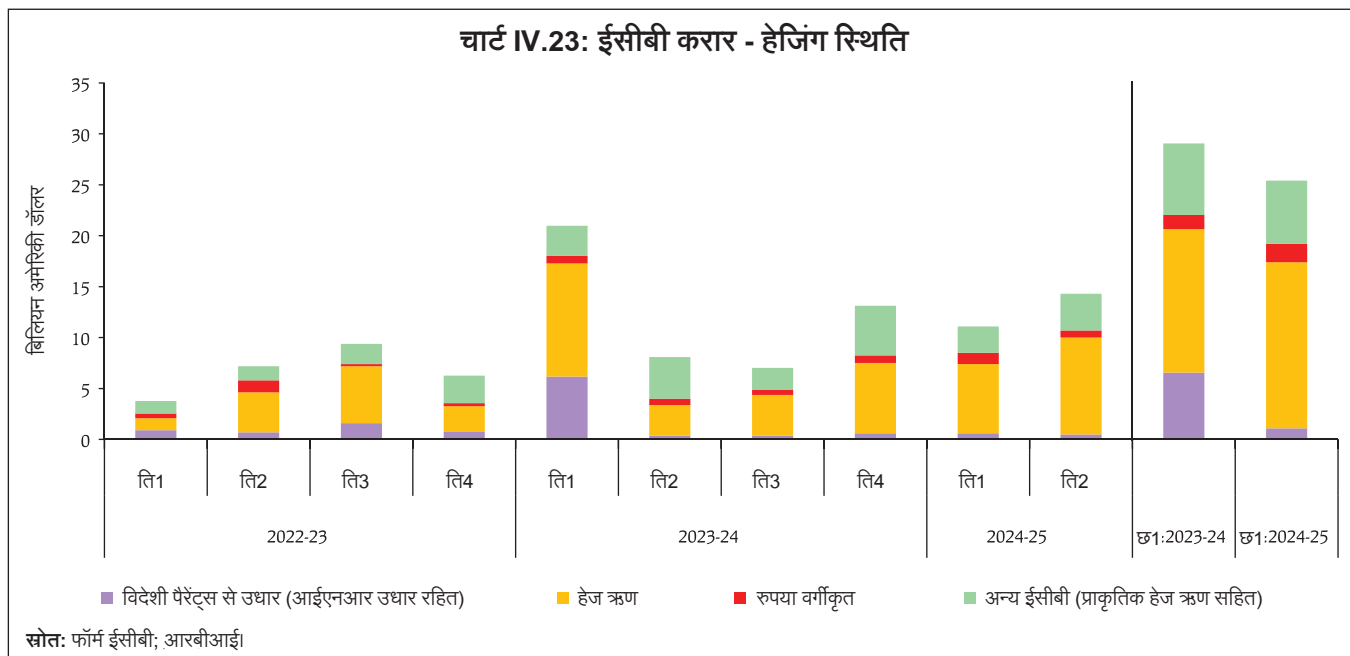
इसके अलावा, भारत की निर्यात संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया है - सेवा निर्यात ने वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान 10.4 प्रतिशत की मजबूत सीएजीआर दर्ज की, जो उनकी बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। वर्तमान में, भारत 4.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में सेवाओं का सातवाँ सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि पण्य वस्तु के वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी केवल 1.8 प्रतिशत है, जिसमें यह अठारहवें स्थान पर है। वर्ष 1994-2018 के दौरान, भारत के पण्य वस्तु निर्यात में 11.1 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई, लेकिन वैश्विक पण्य वस्तु निर्यात वृद्धि भी 6.3 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ अधिक रही।

इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक विनिमय दर परिवर्तनों के प्रति भारत के पण्य वस्तु निर्यात की संवेदनशीलता में कमी आई है, जो बाजारों और निर्यात वस्तुओं में विविधीकरण, विनिर्माण निर्यात में बढ़ती प्रौद्योगिकी गहनता और उच्च मूल्य संवर्धन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ती भागीदारी और उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है³¹ इस प्रकार, भारत के निर्यात प्रयास में जोर कम मूल्यांकित विनिमय दर जैसे कृत्रिम सहारे की आवश्यकता के बिना गुणवत्ता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में सुधार के आधार पर बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण सभी मौजूदा और पूंजीगत वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद किया जाता है, ताकि कमज़ोर समय में यह सहायक साबित हो। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि विदेशी मुद्रा बाजार तरल और गहरा बना रहे, खासकर जब बड़ी पूंजी बहिर्वाह हो, और वित्तीय स्थिरता जोखिमों को कम करने के लिए, जिनमें से सभी का वास्तविक क्षेत्र पर प्रभाव हो सकता है।

30 थाईलैंड (2.5 प्रतिशत), मलेशिया (4.6 प्रतिशत), दक्षिण अफ्रीका (3.2 प्रतिशत) और चीन (6.3 प्रतिशत) के बराबर।

31 निर्यात की विनिमय दर लोच यह मापती है कि किसी देश का निर्यात अपनी विनिमय दर में बदलाव के प्रति कितना संवेदनशील है। विनिमय दर लोच में गिरावट का मतलब है कि मुद्रा मूल्यहास अब निर्यात मात्रा में अनुपातिक वृद्धि की ओर नहीं जाता है।

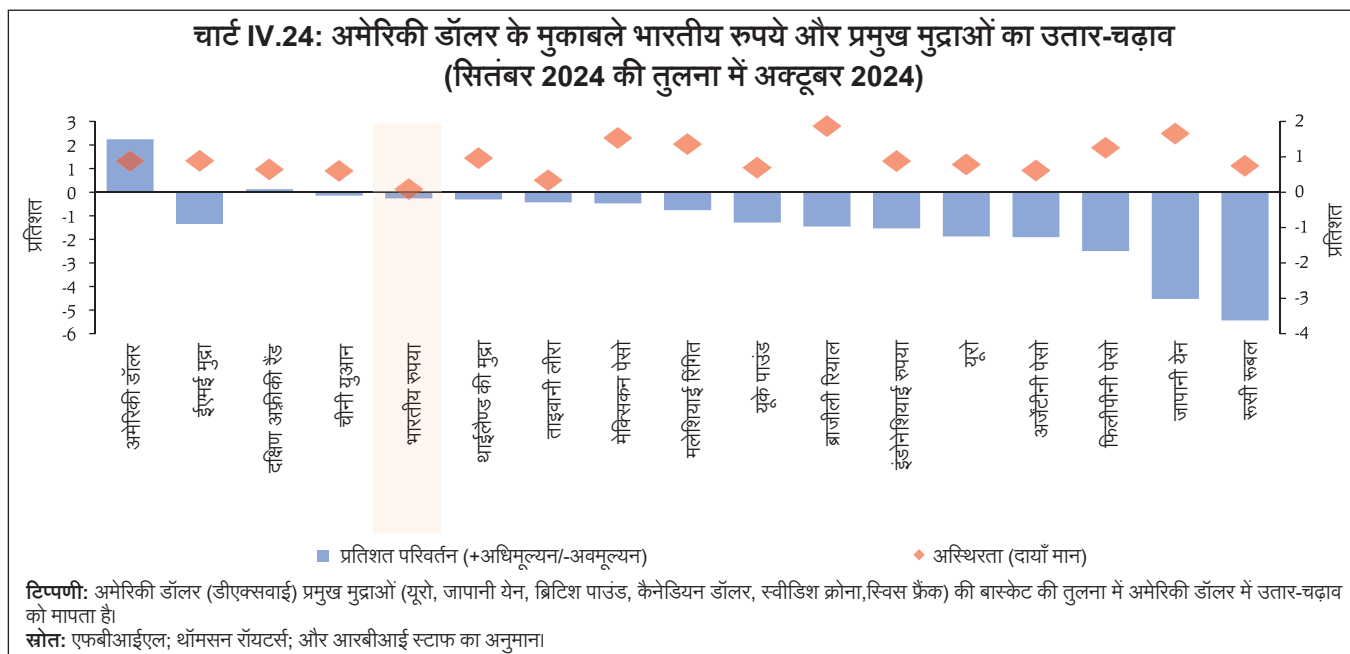


8 नवंबर 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार 675.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2024 के अंत में दर्ज 705.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर से पीछे हट गया। वर्तमान स्तर पर, भंडार 11 महीने से अधिक के आयात और जून 2024 के अंत में बकाया बाह्य ऋण के 99 प्रतिशत से अधिक को कवर करता है (चार्ट IV.26ए)। भारत ने वर्ष 2024 के दौरान अब तक (8 नवंबर तक) अपने भंडार में 53.2 बिलियन

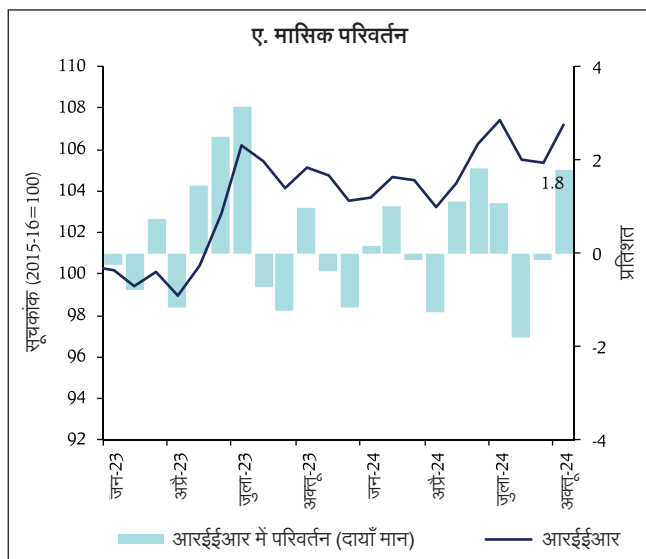
अमेरिकी डॉलर जोड़े हैं, जो एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे अधिक है (चार्ट IV.26बी)। 2024 में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार पर एशिया का दबदबा है, दुनिया की शीर्ष दस भंडार रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से सात इस क्षेत्र में स्थित हैं।

भुगतान प्रणाली

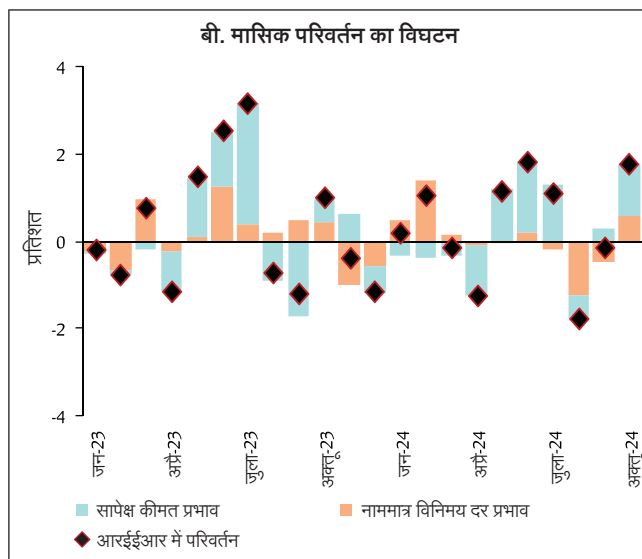
त्यौहारी मौसम के दौरान भुगतान के सभी माध्यमों में डिजिटल लेन-देन में तेज़ी देखी गई (सारणी IV.3)। तत्काल



चार्ट IV.25: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव



स्रोत: आरबीआई

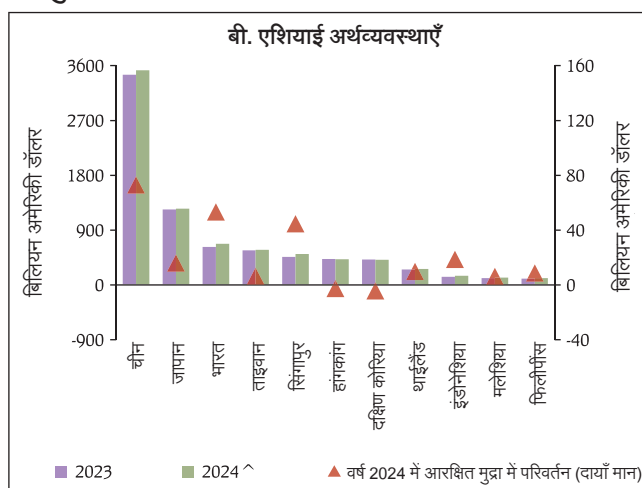
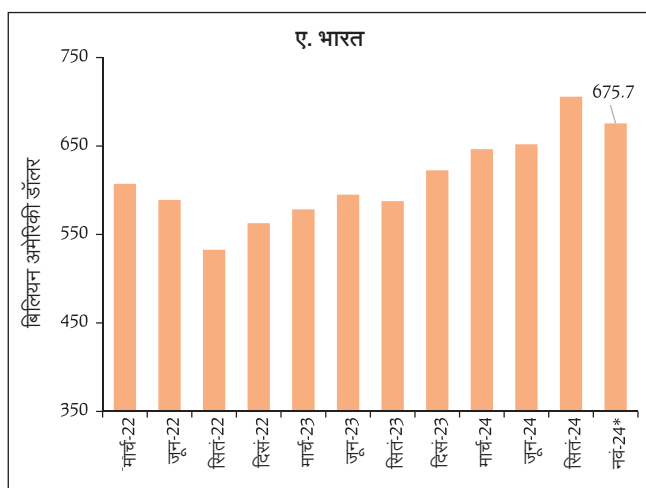


सकल निपटान (आरटीजीएस) में वृद्धि देखी जा रही है, अक्टूबर 2024 तक लेन-देन की मात्रा और मूल्य में क्रमशः 19 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से खुदरा भुगतान अक्टूबर 2024 में 16.6 बिलियन लेन-देन की रिकॉर्ड मात्रा तक पहुँच गया। यूपीआई क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड की संख्या एक वर्ष पहले की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई, सितंबर 2024 तक लगभग 61

करोड़ सक्रिय यूपीआई क्यूआर हैं। पैमाने में इस महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ-साथ, सिस्टम की कार्यक्षमता में भी सुधार हुआ है, जो सितंबर 2023 में 77 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत तक सफल तत्काल डेबिट रिवर्सल में वृद्धि से प्रदर्शित होता है।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) ने वर्ष 2024-25 में अब तक तिहरे अंकों की वृद्धि हासिल की है, जो कि अप्रैल 2024 से गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स को प्रणाली में अनुमति देने वाले

चार्ट IV.26: विदेशी मुद्रा भंडार



टिप्पणियाँ: 1. *: 8 नवंबर 2024 का डेटा।

2. ^: देशों को वर्ष 2024 में आरक्षित मुद्राओं में परिवर्तन के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। भारत के लिए नवीनतम डेटा 8 नवंबर 2024, हांगकांग और मलेशिया के लिए सितंबर के अंत और अन्य देशों के लिए अक्टूबर के अंत तक है।

स्रोत: आरबीआई; संबंधित केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें।

सारणी IV.3: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि

(व-व-व प्रतिशत में)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन की मात्रा				लेनदेन का मूल्य			
	सितं-23	सितं-24	अक्टू-23	अक्टू-24	सितं-23	सितं-24	अक्टू-23	अक्टू-24
आरटीजीएस	7.9	9.1	18.0	19.3	5.5	22.3	16.6	26.8
एनईएफटी	29.2	41.3	38.2	45.4	7.0	15.1	19.6	27.3
यूपीआई	55.7	42.5	56.2	45.4	41.4	30.7	41.6	37.0
आईएमपीएस	2.3	-9.1	2.2	-5.3	11.7	11.4	15.5	16.9
एनएसीएच	20.1	20.2	-1.5	64.5	14.0	27.1	11.9	43.5
एनईटीसी	15.4	6.5	13.0	7.9	19.9	10.4	24.4	10.4
बीबीपीएस	20.2	106.6	26.6	101.0	43.8	268.5	59.2	299.2

टिप्पणी: आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान, एनईएफटी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण

यूपीआई: एकीकृत भुगतान इंटरफेस, आईएमपीएस: त्वरित भुगतान सेवा,

एनएसीएच: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, एनईटीसी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, बीबीपीएस: भारत बिल भुगतान प्रणाली।

स्रोत: आरबीआई।

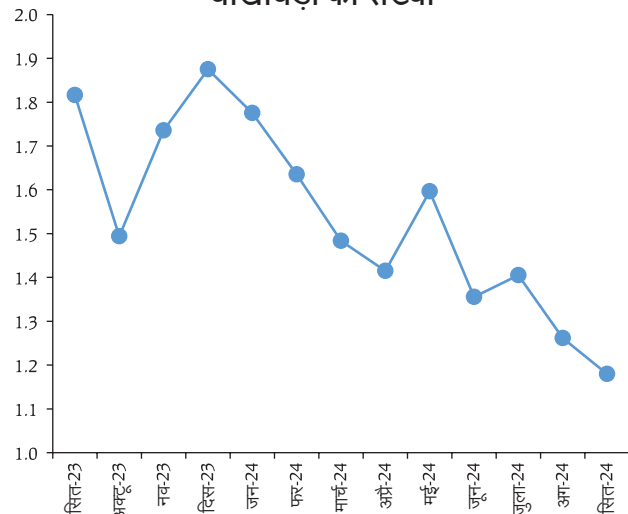
रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों से प्रभावित है।³² बिल भुगतानों को केंद्रीकृत करने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, बीबीपीएस सभी क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतानों को संसाधित करता है, जिसमें प्रमुख जारीकर्ता तीसरे पक्ष के लेनदेन का समर्थन करते हैं।³³ इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) भारत बिलपे लिमिटेड और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के बीच साझेदारी ने भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भुगतान को जोड़ा, जिससे बीबीपीएस को अपनाने में और तेजी आई।³⁴

दिसंबर 2023 से, प्रति 1 लाख डिजिटल लेनदेन पर धोखाधड़ी की घटनाओं की संख्या में गिरावट आई है, जो डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षा में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है (चार्ट IV.27)। आरबीआई इनोवेशन हब (आरबीआई) ने अगस्त 2024 में म्यूलहंटर नामक एक एडवांस एआई टूल विकसित किया, ताकि म्यूल खातों का पता लगाया जा सके।³⁵ इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने डिजिटल धोखाधड़ी के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की, जिसमें

इंटरनेट पर सेंध लगाना और ओटीपी घोटाले जैसे जोखिमों पर ध्यान केंद्रित किया गया।³⁶ इसके अलावा, एनपीसीआई ने उपयोगकर्ताओं में यूपीआई की सुरक्षा और मजबूती को सक्रिय रूप से सुदृढ़ करने के लिए यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है।³⁷

28 अक्टूबर 2024 को, रिज़र्व बैंक ने भारत में समाशोधन और निपटान के लिए अधिकृत केंद्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जो जून 2019 के दिशा-

चार्ट IV.27: प्रति 1 लाख डिजिटल लेनदेन पर धोखाधड़ी की संख्या



टिप्पणी: डेटा में धोखाधड़ी करने का प्रयास शामिल नहीं है।

स्रोत: आरबीआई।

37 एनपीसीआई परिपत्र, 6 नवंबर 2024

38 आरबीआई प्रेस प्रकाशनी, 28 अक्टूबर 2024

32 आरबीआई मास्टर निर्देश, 29 फरवरी 2024

33 भारत कनेक्ट प्रेस रिलीज, 9 जुलाई 2024

34 एनपीएस प्रेस प्रकाशनी, 28 अगस्त 2024

35 <https://rbihub.in/mule-hunter-ai/>

36 एनपीसीआई परिपत्र, 17 अक्टूबर 2024

निर्देशों को बदल देते हैं।³⁸ इन नए नियमों का उद्देश्य सीसीपी की परिचालन सुरक्षा, वित्तीय आघात-सहनीयता बढ़ाना और वैश्विक मानकों के साथ संरेखण को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्यों में सीसीपी अभिशासन, वित्तीय सुदृढ़ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना, अंततः भारत की वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता और समाशोधन और निपटान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना शामिल है।

निष्कर्ष

वैश्विक वृद्धि की निकट भविष्य में अपनी गति बनाए रखने की उम्मीद है क्योंकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में घटती मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थितियों में सहजता उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा देती है। नौकरी रिक्रियों की दरों में गिरावट और कम बेरोजगारी दरों के साथ श्रम बाजार की स्थिति सहायक बनी हुई है। वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण सकारात्मक है, हालांकि संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की आशंकाएँ नवजात सुदृढ़ता पर हावी हैं। मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद, अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता विश्वास अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जो आगे चलकर बाधा बन सकता है। हालाँकि लक्षित बुनियादी ढाँचा निवेश और सामाजिक व्यय कार्यक्रमों सहित विकसित अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीतियों से वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन उच्च ऋण स्तरों पर चिंताएँ महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, जिसने हाल के महीनों में प्रतिफल को बढ़ाया है। मौद्रिक अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक सहजता के लिए जगह बनने के बावजूद, ईएमई केंद्रीय बैंकों को बाहरी प्रतिकूलताओं से चुनौतियों का सामना करना

पड़ रहा है, जिससे नीतिगत प्रतिक्रियाओं में अंतर हो रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था त्योहारों से जुड़ी खपत और कृषि क्षेत्र में सुधार के कारण आघात-सहनीयता दिखा रही है। खरीफ खाद्यान्नों के लिए रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान और रबी फसल की आशाजनक संभावनाएं कृषि आय और ग्रामीण मांग के लिए भविष्य में अच्छी हैं। संस्थागत बुनियादी अवसंरचना के संदर्भ में, सटीक उत्पादन अनुमान के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षणों को अपनाना और ड्रोन की शुरुआत वास्तविक समय के आधार पर उत्पादन स्थितियों का आकलन करने और संभवतः सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन को सक्षम करके इस क्षेत्र में दीर्घकालिक दक्षता और उत्पादकता लाभ लाने के लिए तैयार है।

औद्योगिक मोर्चे पर, विनिर्माण और निर्माण में गतिशीलता बनी रहने की उम्मीद है। ईवी अपनाने, अनुकूल नीतियों, सब्सिडी और बढ़ते बुनियादी ढांचे ने भारत को टिकाऊ परिवहन में अग्रणी बना दिया है और उभरते स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है। भारत के सेवा क्षेत्र में वृद्धि की गति, मजबूत रोजगार सृजन और उच्च उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास को बनाए रखने की उम्मीद है।

वैश्विक अनिश्चितता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में उतार-चढ़ाव के कारण बॉण्ड और इक्विटी बाजारों में दबाव के बावजूद, वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल बनी रहने की संभावना है, जैसा कि कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने और एफडीआई प्रवाह में परिलक्षित होता है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भी अपनी विकास गति को बनाए रखने की उम्मीद है।